

ที่ พณ ๐๓๐๙.๐๙/ว ๕๓



ถึง สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรมการค้าต่างประเทศ ขอแจ้งประกาศของหน่วยงาน Directorate General of Trade Remedies (DGTR) กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม สาธารณรัฐอินเดีย ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ผลขั้นที่สุด (Final Findings) กรณีการไต่สวนเพื่อใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure) กับสินค้า Low Ash Metallurgical Coke โดย DGTR ออกคำแนะนำให้กำหนด มาตรการด้วยวิธีการจำกัดปริมาณการนำเข้า (Quantitative Restrictions) สินค้าดังกล่าว เป็นระยะเวลา ๑ ปี อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศกำลังพัฒนาที่ได้รับการยกเว้นจากการใช้ มาตรการ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศดังกล่าวได้ตาม QR Code ที่แนบ มาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งสมาชิก ที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดยทั่วกัน



กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า

โทร ๐๒ ๕๔๗ ๔๗๓๘

โทรสาร ๐๒ ๕๔๗ ๔๗๔๑



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052024-254066
CG-DL-E-08052024-254066

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 1, 2024/वैशाख 11, 1946

No. 121]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 1, 2024/VAISAKHA 11, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2024

मामला सं. एसजी (क्यूआर) -04/2023

अंतिम जांच परिणाम

विषय: भारत में लो ऐश मेटलर्जिकल कोक के आयातों के संबंध में रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 22/4/2023-डीजीटीआर.—बीएलए कोक प्राइवेट लिमिटेड, जिंदल कोक लिमिटेड, सौराष्ट्र फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, वेदांता माल्को एनर्जी लिमिटेड और वीजा कोक लिमिटेड (इसके बाद इन्हें “आवेदक” अथवा “घरेलू उद्योग” के रूप में कहा गया है) द्वारा रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमावली, 2012 (इसके बाद इसे “मात्रात्मक प्रतिबंध नियमावली” अथवा “नियमावली” के रूप में भी कहा गया है) के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन), अधिनियम, 1992 (इसके बाद इसे “अधिनियम” के रूप में भी कहा गया है) की धारा 9क के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष दिनांक 04 अप्रैल, 2023 को एक आवेदन दाखिल किया गया था, जिसमें भारत में “लो ऐश मेटलर्जिकल कोक”

(इसके बाद इसे “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” अथवा “संबद्ध वस्तुएं” अथवा “मेट कोक” के रूप में भी कहा गया है) के आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।

2. आवेदकों ने यह आरोप लगाया है कि विचाराधीन उत्पाद को भारत में इतनी बढ़ती मात्रा में और ऐसी स्थितियों के अंतर्गत आयात किया जा रहा है कि उससे भारत में घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और उससे समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। इसी कारण से, आवेदकों ने एक वर्ष की अवधि के लिए इसकी क्षति को कम करने के एक उपाय के रूप में रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) लगाने का अनुरोध किया गया था।
3. आवेदकों द्वारा दाखिल की गई विधिवत प्रमाणित याचिका और संबद्ध वस्तुओं के आयातों में हाल की, अचानक, तेज और महत्वपूर्ण वृद्धि होने और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने के संबंध में प्रस्तुत किए गए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आलोक में विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9 क और मात्रात्मक प्रतिबंध नियमावली के नियम 5 के प्रावधानों के अंतर्गत, मात्रात्मक प्रतिबंधों के रूप में रक्षोपायों को लागू करने की जरूरत की जांच करने के लिए भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों के खिलाफ दिनांक 30 जून, 2023 की अधिसूचना सं. 22/4/2023-डीजीटीआर के तहत एक रक्षोपाय जांच शुरू की गई थी।

ख. प्रक्रिया

4. उक्त नियमावली के नियम 6 के उप नियम (2) और (3) के अनुसार, दिनांक 30 जून, 2023 की जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति और आवेदकों द्वारा दाखिल किए गए आवेदन के अगोपनीय पाठ (एनसीवी) की एक प्रति वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार, भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से प्रमुख निर्यातक देशों की सरकारों और उक्त आवेदन में उल्लिखित किए गए हितबद्ध पक्षकारों को भेजी गई थी।
5. उक्त नियमावली के नियम 6(4) के अंतर्गत यथानिर्धारित निर्यातकों/ आयातकों/ घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्तर दी जाने वाली प्रश्नावली को ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रेषित किया गया था, जिसमें उन्हें जांच शुरूआत अधिसूचना जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था।
6. जांच शुरूआत अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया :-
 - i. बाल्टा जीएमबीएच
 - ii. ब्लूस्कोप स्टील (एआईएस) प्राइवेट लिमिटेड
 - iii. चेओंगफुली (ज़ियामेन) कंपनी लिमिटेड
 - iv. चाइना नेशनल मिनरल्स कंपनी लिमिटेड
 - v. पीटी. डेटियन कोर्किंग इंडोनेशिया
 - vi. पीटी. किनरुई न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंडोनेशिया
 - vii. पीटी. किन्क्सियांग न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंडोनेशिया
 - viii. पीटी. रिसुन वेई शान इंडोनेशिया
 - ix. क्रिंगदाओ सायन कोक रिच इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड
 - x. रिसुन मार्केटिंग लिमिटेड
 - xi. सिनोकेम इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन
 - xii. यूनियन यिवुआ इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड
 - xiii. ज़ियामेन गुकिरिंग सप्लाई चैन कंपनी लिमिटेड

- xiv. ज़ियामेन आईटीजी डायनेमिक कंपनी लिमिटेड
7. जांच शुरूआत अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने प्रयोक्ता/ आयातक प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया :
- उड़ीसा मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 - जयसवाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - टाटा स्टील लिमिटेड
 - टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड
 - सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
 - मुकुंद लिमिटेड
 - आर्सेलरमिस्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड
 - बालमुकुंद स्पंज एंड आयरन प्राइवेट लिमिटेड
 - इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड
 - नरसिंह इस्पात लिमिटेड
 - नियो मेटालिक्स लिमिटेड
 - एसएमसी पावर जेनरेशन लिमिटेड
 - श्री मेटालिक्स लिमिटेड
 - स्वाति कॉनकास्ट एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
8. जांच शुरूआत अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध दाखिल किए :-
- अलॉय स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएसपीए)
 - बाल्टा जीएमबीएच
 - ब्लूस्कोप स्टील (एआईएस) प्राइवेट लिमिटेड
 - चाइना चैंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ मेटल्स मिनरल्स एंड कैमिकल इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स
 - इंडोनेशिया सरकार
 - जयसवाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - मुकुंद लिमिटेड
 - उड़ीसा मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 - सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
 - टाटा स्टील लिमिटेड और टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड
9. जांच शुरूआत अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया :-
- घरेलू उद्योग
 - नारायणी कोक प्राइवेट लिमिटेड
 - आर्सेलरमिस्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड
 - बालमुकुंद स्पंज एंड आयरन प्राइवेट लिमिटेड
 - बाल्टा जीएमबीएच

- vi. ब्लूस्कोप स्टील (एआईएस) प्राइवेट लिमिटेड
 - vii. चेओंगफुली (ज़ियामेन) कंपनी लिमिटेड
 - viii. चाइना नेशनल मिनरल्स कंपनी लिमिटेड
 - ix. इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड
 - x. नरसिंह इस्पात लिमिटेड
 - xi. नियो मेटालिक्स लिमिटेड
 - xii. क्रिंगदाओ सायन कोक रिच इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड
 - xiii. रिसुन मार्केटिंग लिमिटेड
 - xiv. सिनोकेम इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन
 - xv. एसएमसी पावर जेनरेशन लिमिटेड
 - xvi. श्री मेटालिक्स लिमिटेड
 - xvii. स्वाति कॉनकास्ट एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
 - xviii. इंडियन फेरो अलॉय प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (आईएफएपीए)
 - xix. यूनियन यिवुआ इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड
 - xx. ज़ियामेन गुकिरिंग सप्लाय चैन कंपनी लिमिटेड
 - xxi. ज़ियामेन आईटीजी डायनेमिक कंपनी लिमिटेड
10. प्राधिकृत अधिकारी ने अभी की हाल की अवधि के रूप में 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 और जांच की अवधि के रूप में 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2023 पर विचार किया है।
 11. डी जी टी आर की वेबसाइट पर हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची प्रकाशित की गई थी, ताकि सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अगोपनीय पाठ (एनसीवी) के लिए किए गए सभी अनुरोध सुलभ कराए जा सकें। सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रत्येक के ई-मेल के माध्यम से उनके अनुरोधों के अगोपनीय पाठ का आदान प्रदान करने का परामर्श दिया गया था।
 12. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकृत अधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर प्रदान किया कि वे दिनांक 17 जनवरी, 2024 को हाईब्रिड मोड में अर्थात् वर्चुअल और भौतिक दोनों तरीके से आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकें। जिन पक्षकारों ने ऑनलाइन भाग लेने की इच्छा व्यक्त की थी, उन्होंने डिजिटल विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। मौखिक सुनवाई में जिन हितबद्ध पक्षकारों ने भाग लिया था, उन्हें अपने मौखिक रूप से प्रस्तुत किए गए विचारों को लिखित में दाखिल करने का अनुरोध किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिखित अनुरोधों के लिए प्रत्युत्तर (रिज्वाइंडर), यदि कोई हो, दाखिल करने का एक अवसर भी प्रदान किया गया था। निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई के बाद लिखित अनुरोध दाखिल किए थे :-
 - i. घरेलू उद्योग
 - ii. अलॉय स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन
 - iii. आर्सेलर मिट्तल निप्पॉन स्टील लिमिटेड
 - iv. बालमुकुंद स्पंज एंड आयरन प्राइवेट लिमिटेड
 - v. बाल्टा जीएमबीएच
 - vi. ब्लूस्कोप स्टील (एआईएस) प्राइवेट लिमिटेड
 - vii. चाइना चैंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ मेटल्स मिनरल्स एंड कैमिकल इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स

- viii. यूरोपीय आयोग
 - ix. इंडोनेशिया सरकार
 - x. इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड
 - xi. जयसवाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - xii. मुकंद लिमिटेड
 - xiii. नरसिंह इस्पात लिमिटेड
 - xiv. नियो मेटालिक्स लिमिटेड
 - xv. उड़ीसा मेटालिक्स प्रा. लिमिटेड
 - xvi. पीटी. डेटियन कोर्किंग इंडोनेशिया
 - xvii. पीटी. किनरुई न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंडोनेशिया
 - xviii. पीटी. किन्क्सियांग न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंडोनेशिया
 - xix. पीटी. रिसुन वेई शान इंडोनेशिया
 - xx. रूसी संघ
 - xxi. एसएमसी पावर जेनरेशन लिमिटेड
 - xxii. श्री मेटालिक्स लिमिटेड
 - xxiii. सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
 - xxiv. स्वाति कॉन्कास्ट एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
 - xxv. टाटा स्टील लिमिटेड
 - xxvi. टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड
13. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा मौखिक सुनवाई अथवा अन्यथा सुनवाई के अनुसरण में किए गए अनुरोधों को साक्ष्य के साथ पाए जाने और वर्तमान जांच के लिए संगत होने के अनुसार इस प्रकटीकरण विवरण में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विचार में लिया गया है।
 14. प्राधिकृत अधिकारी ने जांच के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना की सटीकता के लिए स्वयं को संतुष्ट किया, जो यथासंभव इस प्रकटीकरण विवरण का आधार बना और घरेलू उद्योग द्वारा इसके संगत, व्यवहार्य और आवश्यक होने के अनुसार, प्रस्तुत डेटा/ दस्तावेजों की पुष्टि की गई।
 15. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की, गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकृत अधिकारी ने आवश्यकता के अनुसार गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना के पर्याप्त अगोपनीय पाठ को प्रदान करने का निदेश दिया गया था।
 16. जहां कहीं भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा, जांच की अवधि के दौरान आवश्यक सूचना सुलभ कराने से इंकार किया गया है अथवा जांच को महत्वपूर्ण रूप से छिपाया गया है, वहां प्राधिकृत अधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस प्रकटन विवरण को दर्ज किया है।
 17. जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का सौदा-वार ब्यौरा प्रदान करने के लिए महानिदेशालय (सिस्टम) से अनुरोध किया गया था।
 18. इस प्रकटीकरण विवरण में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना को दर्शाता है और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस पर विचार किया गया है।

19. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 यू एस डॉलर= 81.06 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद का दायरा और समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

20. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे :-

- क. चूंकि घरेलू उद्योग लो ऐश मेटालर्जिकल कोक का 0.30 प्रतिशत तक फास्फोरस की मात्रा और 30 मि.मि. तक के ओवरसाइज के साथ, जिसकी अधिकतम सीमा 5 प्रतिशत तक सीमित है, उत्पादन करने में समर्थ है। मौखिक सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा इसे बाहर करने पर सहमति हो गई है।
- ख. अल्ट्रा फॉस्फोरस कोक (यूएलपी) [फॉस्फोरस : $\leq 0.007\%$, S:0.65%, FC:84-86%, 10-30 मि.मी.]; अल्ट्रा लो फॉस्फोरस कोक (यूयूएलपी), [फॉस्फोरस: $\leq 0.005\%$, S:0.65%, FC:84-86%, 10-30 मिमी.]; अल्ट्रा लो फॉस्फोरस कोक फाइनस(यूएलपीसी) [फॉस्फोरस: $\leq 0.007\%$, S:0.65%, FC:85-89%, 0-6मि.मी.] को बाहर कर दिया जाना चाहिए।
- ग. यद्यपि आवेदक 0.03 से कम फास्फोरस सामग्री और 30 मि.मी. तक के पार्टिकल साइज वाले लो फॉस्फोरस कोक को सुनवाई के दौरान बाहर करने पर सहमत हो गए थे, लेकिन पार्टिकल साइज 30 मि.मी. तक की स्थिति संगत नहीं है और उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
- घ. 5 प्रतिशत के टोलरेंस के साथ 40 मि.मी. तक के आकार वाले मेट कोक को बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि यह घरेलू तौर पर अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है। चूंकि केवल यही आकार मिनी ब्लॉक फर्नेस में प्रयोग हो सकता है और सीमित मात्रा में आयात किया जाता है, मात्रात्मक प्रतिबंध का पिग आयरन निर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उन्हें लागत में वृद्धि के लिए बड़े आकार के कोक को तोड़कर छोटे आकार करने पर मजबूर किया जाएगा।
- ङ. घरेलू उद्योग कोक फाइन/ कोक ब्रीज के उत्पादन में शामिल नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए कोक फाइन में हाई ऐश और वोलेटाइल मैटर कंटेंट होता है। एक आवेदक का संगत पक्षकार तो स्वयं ही अन्य हितबद्ध पक्षकार को आपूर्ति के लिए कोक फाइनस का आयात करता है। इस प्रकार से, लो ऐश मात्रा वाले ऐसे कोक फाइनस को, जैसा कि मौखिक सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा सहमति दी गई है, विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए।
- च. भारतीय उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए मेट कोक में आयात किए गए कोक की तुलना में घटिया गुणवत्ता होती है। घरेलू कोक में अधिक नमी होती है, जिससे अधिक फ्यूल की मांग होती है, जिसमें कटौती के बाद कमतर कोक मजबूती होती है और अधिक कोक प्रतिसंवेदनशीलता (रीएक्टिविटी) इंडेक्स होता है, निचला और कमजोर पार्टिकल साइज होता है और ऊपरी ओर -30 मि.मी और -25 मि.मी. का फ्रेक्शन होता है, घरेलू कोक का आकार अर्सिलर मित्तल निप्पो स्टील इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्धारित मानकों से कम था। घटिया गुणवत्ता के मेट कोक का उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग करने से हॉट मेटल उत्पादन में कमी आती है। अन्य सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं, जिनमें टेपहोल अवरूद्ध होना, कोक रश होना, कर्मियों की सुरक्षा, उपकरण क्षति, प्रचालन संबंधी अवरोध आदि शामिल हैं
- छ. मेट कोक आयात के विश्लेषण के लिए एच एस कोड 2704 पर विचार करना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार का कोयला शामिल है और विचाराधीन उत्पाद को केवल 27040030 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
- ज. एच एस कोड 2704 ऐश की मात्रा को नहीं दर्शाता। भारत में कोक में 11 प्रतिशत तक लो ऐश की मात्रा, 18 प्रतिशत तक मिडिल ऐश की मात्रा और 25 प्रतिशत तक हाई ऐश की मात्रा शामिल है। चूंकि 14 प्रतिशत ऐश की मात्रा वाला कोक ब्लास्ट फर्नेस में प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकों ने सभी प्रकार के कोक को शामिल करने के लिए 4-डिजिट कोड पर सीमा शुल्क डेटा का गलत प्रयोग किया है।

ग 2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

21. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :-

- क. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद लो ऐश मेटलर्जिकल कोक है, जिसमें राख (ऐश) की मात्रा 18 प्रतिशत से कम है। कम राख की मात्रा वाले मेट कोक का उत्पादन करने के लिए, एकमात्र जरूरत लो ऐश कोकिंग कोयले की है।
- ख. विचाराधीन उत्पाद कोक, नट कोक, कोयले का सेमी कोड, बीएफ कोक, फाउंड्री कोक, कोक ब्रीज, मेटलर्जिकल ब्रीज कोक, कोक फाइन्स, कोक डस्ट, कोक ऐश पाउडर, कोक पाउडर और कार्बन कोक/कोक जैसे विभिन्न नामों के तहत आयात किया जाता है।
- ग. कार्बो फ्लक्स, कार्बन ब्लॉक, कार्बन एनोड बट्स, कार्बन रेंजर, कार्बन रेज्ड, बैग, लिग्नाइट या पीट का सेमी कोक, लिग्नाइट स्पेशल कोक, गैर-सक्रिय चारकोल, बाबॉलक्स सीटीएफ 065 एस ए एस सी ए आर बी नाम के तहत आयात किए गए उत्पाद विचाराधीन उत्पाद का भाग नहीं है।
- घ. घरेलू उद्योग ने आर्थिक अव्यवहार्यता के कारण फैंरो अलॉय अनुप्रयोगों में प्रयोग के लिए 0.03 प्रतिशत से कम फास्फोरस सामग्री और 30 मि.मी. से कम आकार के साथ अल्ट्रा लो फास्फोरस मेटलर्जिकल कोक का निर्माण नहीं किया है और ऐसे उत्पाद को जब आयातक फैंरो अलॉय के विनिर्माण के लिए उक्त उत्पाद के उपयोग को दर्शाता है, तो कोटा के प्रयोग से बाहर किया जाए।
- ड. कोक ब्रिज/ फाइन्स वैश्विक रूप से किसी भी निर्माता द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता, बल्कि कोक का उत्पादन करते समय उत्पन्न एक उप उत्पाद है। चूंकि घरेलू उद्योग ने कम राख वाले कोक ब्रीज/ फाइन्स का उत्पादन नहीं किया है, अतः इसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जा सकता है।
- च. अन्य हितवद्ध पक्षकारों के ऐसे तर्कों के विपरीत गुणवत्ता आयात में वृद्धि होने का कारण नहीं हो सकती। इसके अलावा, यदि आयात बेहतर गुणवत्ता का होता है, तो उत्पाद की कीमतें अधिक होती।
- छ. 40 मि.मी. तक के आकार वाले मेट कोक को बाहर करने के लिए अनुरोध के संबंध में, उक्त उत्पाद का उत्पादन भारतीय उद्योग द्वारा किया जा रहा है और उसे बाहर करने की जरूरत नहीं है।
- ज. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए एच एस वर्गीकरण केवल सांकेतिक प्रकृति का है, जैसा कि जांच शुरूआत अधिसूचना में प्रदान किया गया है। प्रस्तुत की गई सूचना केवल विचाराधीन उत्पाद के लिए प्रासंगिक है और आवेदन में किसी भी तरह से किसी ऐसी वस्तु के संबंध में किसी आंकड़े की सूचना नहीं दी गई है, जो विचाराधीन उत्पाद की प्रतिनिधित्व नहीं है।
- झ. मेट कोक को एच एस कोड 27040030 के तहत वर्गीकृत किया गया है। यद्यपि, इसे एच एस कोड 2704 0010, 2704 0020, 2704 0030 और 2704 0090 के तहत भी आयात किया जा रहा है। तदनुसार, रक्षोपाय अधिसूचना के लिए एच एस कोड 2704 पर विचार किया जा सकता है।
- ञ. अन्य हितवद्ध पक्षकारों ने तर्कों के विपरीत आयात में और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के निर्धारण के लिए केवल 10 प्रतिशत से कम ऐश की मात्रा वाले मेटलर्जिकल कोक से संबंधित लेन देन पर विचार किया गया है।

ग.3 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की गई जांच

22. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद लो ऐश मेटलर्जिकल कोक है, अर्थात् 18 प्रतिशत से कम ऐश वाला मेटलर्जिकल कोक है। इस उत्पाद को सामान्य तौर पर बाजार की आम भाषा में मेट कोक या कोक के नाम से जाना जाता है। उच्च राख मात्रा वाला मेटलर्जिकल कोक अर्थात् 18 प्रतिशत से अधिक राख वाला उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है।
23. अन्य हितवद्ध पक्षकारों ने 0.030 प्रतिशत तक कम मात्रा और 30 मि.मी. से कम आकार वाले अल्ट्रा लो फास्फोरस लो ऐश मेटलर्जिकल कोक को बाहर करने का अनुरोध किया है कि ऐसे उत्पादक के उत्पादन के लिए किसी नए उपकरण या संयंत्र की जरूरत नहीं है और केवल एक विशिष्ट प्रकार के कोकिंग कोयले की आवश्यकता होती है। यद्यपि, घरेलू उद्योग ने 0.030% प्रतिशत तक कम फास्फोरस मात्रा और 30 मि.मी. से कम आकार वाले मेटलर्जिकल कोक को बाहर करने की सहमति दी है। प्राधिकृत अधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने उक्त उत्पाद की व्यवसायिक अव्यवहार्यता बताते हुए उसका निर्माण नहीं किया है। ऐसे उत्पाद का उपयोग फैंरो अलॉय के निर्माण के लिए किया जाता है। अतः प्राधिकृत अधिकारी का प्रस्ताव है कि 0.03 प्रतिशत से कम फास्फोरस सामग्री

और 30 मि.मी. से कम आकार वाले अल्ट्रा लो फास्फोरस मेटलर्जिकल कोक किसी भी मात्रात्मक प्रतिबंध के अंतर्गत नहीं होंगे।

24. कोक फाइन/ कोक ब्रीज के संबंध में, प्राधिकृत अधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग लो ऐश कोक फाइन/ कोक ब्रीज को बाहर करने के लिए सहमत हो गया है क्योंकि इसका उत्पादन इसके द्वारा नहीं किया जाता है। तदनुसार, प्राधिकृत अधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे में लो ऐश कोक फाइन/ कोक ब्रीज अर्थात 18 प्रतिशत तक की ऐश मात्रा वाले फाइन/ कोक ब्रीज शामिल नहीं है।
25. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि 40 मि.मी. तक के आकार वाले मेट कोक को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी यह नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने स्वयं ही यह कहा है कि उक्त उत्पाद भारत में उपलब्ध है और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की जा रही है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सीमित मात्रा में ऐसे उत्पाद की उपलब्धता के संबंध में अपने दावों की पुष्टि नहीं की है। तदनुसार, यह माना गया है कि 40 मि.मी. तक के आकार वाले मेट कोक को बाहर करने की आवश्यकता को प्रभावित नहीं किया गया है।
26. एच एस कोड के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के संबंध में, यह नोट किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद विभिन्न एच एस कोड के तहत आयात किया जा रहा है। मेटलर्जिकल कोक के संबंध में 2704 पर 4-अंकीय स्तर के तहत आयात संबंधी आंकड़े को उत्पाद के विवरण के आधार पर 18 प्रतिशत से कम ऐश मात्रा वाले लो ऐश मेटलर्जिकल कोक के रूप में 8 अंकीय स्तर पर अलग किया जा रहा है।
27. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की गुणवत्ता घटिया है। प्राधिकृत अधिकारी यह नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इसके लिए साक्ष्य प्रदान करके अपने दावों की पुष्टि नहीं की है। इसके अलावा, बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद के मामले में एक निर्माता आम तौर पर प्रीमियम लेता है क्योंकि प्रयोक्ता मूल्य निर्धारण नीति के कारण निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद की ओर नहीं जाएंगे। वर्तमान मामले में आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और इसलिए आयात की बेहतर गुणवत्ता के संबंध में अनुरोध उचित नहीं है।
28. यह भी नोट किया जाता है कि उत्पाद के संबंध में विगत पाटनरोधी जांच में प्राधिकृत अधिकारी ने यह पाया था कि घरेलू उद्योग आयातित उत्पाद के समान वस्तु का उत्पादन कर रहा था। रक्षोपाय जांच में, यह जांच करना आवश्यक है कि क्या घरेलू उद्योग ने आयातित उत्पाद के समान या सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पाद का उत्पादन किया है। विगत जांचों में प्राप्त निष्कर्षों के मतभेद अथवा विवाद के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई साक्ष्य नहीं रखा गया है। इसके अलावा, किसी भी पक्षकार ने यह दावा नहीं किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं आयात किए गए उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही हैं। अतः प्राधिकृत अधिकारी ने यह पाया है कि रिकॉर्ड पर दर्ज सूचना उत्पादों की गुणवत्ता में अंतर को नहीं दर्शाती।
29. रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी के आधार पर वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित है

"लो ऐश मेटलर्जिकल कोक, यानी, मेटलर्जिकल कोक जिसमें कोक फाइन/कोक ब्रीज को छोड़कर 18% से कम राख सामग्री होती है और 0.030% तक फॉस्फोरस सामग्री के साथ अल्ट्रा-लो फॉस्फोरस मेटलर्जिकल कोक, 30 मिमी के आकार के साथ उपयोग के लिए 5% आकार सहिष्णुता के साथ होता है। लौहमिश्र धातु विनिर्माण"

घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और भारत में आयात की गई वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। वे भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, वितरण और विवरण तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं भी तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से आयातित उत्पाद से तुलनीय है। उपभोक्ताओं ने दोनों का परस्पर उपयोग किया है और उपयोग कर रहे हैं। प्राधिकृत अधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि आवेदकों द्वारा निर्मित उत्पाद नियमावली के नियम 2(ड.) के अनुसार भारत में आयात की जाने वाली संबद्ध वस्तु के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग और आधार

घ.1 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

30. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :-

- क. एक रक्षोपाय जांच में, घरेलू उद्योग के गठन के लिए एकमात्र शर्त कुल उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा है। पाटनरोधी जांच में इसे बाहर करने पर विचार नहीं किया गया। आइसोप्रोसिल अल्कोहल के आयात की रक्षोपाय जांच में प्राधिकृत अधिकारी ने माना कि संबद्ध वस्तुओं का आयात करने वाले उत्पादक का कोई बहिष्करण नहीं है।
- ख. प्राधिकृत अधिकारी मध्यवर्ती उत्पाद के साथ में संबद्ध वस्तु का निर्माण करने वाले उत्पादकों को शामिल करने के बाद वर्तमान मामले में स्थिति की पुनः जांच कर सकते हैं।
- ग. स्थिति का निर्धारण करने के लिए कैप्टिव अथवा व्यापारी बाजार के बावजूद मेट कोक का उत्पादन करने वाली सभी संस्थाओं के उत्पादन पर विचार किया जाना चाहिए। यूएस -कॉटन यार्न मामले में अपीलीय निकाय ने माना कि घरेलू उत्पादन के प्रमुख भाग का निर्धारण करते समय, कैप्टिव उपभोक्ताओं को बाहर नहीं किया जा सकता है। कैप्टिव उत्पादक भारत में 73 प्रतिशत कोर्किंग कोयले का आयात करते हैं और अधिकांश विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करते हैं।
- घ. भारत में मेट कोक के कुल उत्पादन के निर्धारण के लिए उत्पाद के कैप्टिव उपभोक्ताओं को बाहर नहीं किया जा सकता है। आवेदकों ने मेट कोक के आयातों पर पाटनरोधी जांच में प्राधिकृत अधिकारी के निर्णय और सेस्टेट के निर्णय पर भरोसा किया है। रक्षोपाय नियमावली के तहत घरेलू उद्योग की परिभाषा में दो या दो से अधिक प्रतिस्पर्धी बाजारों पर विचार करने की अनुमति नहीं है, जहां उत्पादों को पाटनरोधी नियमावली के तहत परिभाषा के विपरीत, अलग उद्योग के रूप में माना जा सकता है।
- ड. जबकि आवेदकों ने यह दावा किया है कि कैप्टिव उत्पादों ने अपनी वेबसाइट पर उत्पाद के रूप में मेट कोक का उल्लेख नहीं किया है। आर आई एन एल और सातवाहन इस्पात लि. ने अपनी वेबसाइट पर उत्पाद का उल्लेख किया है। सातवाहन इस्पात लिमिटेड और बंगाल एनर्जी लिमिटेड मर्चेन्ट बाजार में मेट कोक की बिक्री में लगे हुए हैं, जैसा कि आस्ट्रेलिया और चीन से मेट कोक के आयात पर पाटनरोधी जांच में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए अंतिम जांच निष्कर्षों से यह स्पष्ट है। यदि ऐसे उत्पादों के उत्पादन को कुल घरेलू उत्पादन में जोड़ा जाता है, तो आवेदकों की हिस्सेदारी हमेशा कम होगी।
- च. 33.46 प्रतिशत की हिस्सेदारी को कुल उत्पादन में बड़ी हिस्सेदारी नहीं माना जा सकता। वर्तमान उद्योग एक खंडित उद्योग नहीं है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि आवेदकों ने सभी घरेलू उत्पादकों की एक सूची प्रदान की है। घरेलू उत्पादन में कम हिस्सेदारी होने से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की प्रतिनिधिक और उद्देश्यपरक जांच की अनुमति नहीं होगी।
- छ. आवेदकों ने अप्रैल-2019-मार्च, 2023 के दौरान कुल घरेलू उत्पादन में अपने हिस्से के बारे में जानकारी प्रदान नहीं की है। समग्र क्षति अवधि के दौरान उत्पादन में हिस्सेदारी के आधार पर स्थिति का निर्धारण किया जाना चाहिए।
- ज. पाटनरोधी जांच में आवेदकों की घरेलू उत्पादन में हिस्सेदारी वर्तमान जांच की तुलना में अधिक थी। इसके अलावा, पाटनरोधी जांच में आवेदक अभी भी प्रचालन में है (गुजरात एनआरई कोक लिमिटेड को छोड़कर), लेकिन उन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। चूंकि रक्षोपाय जांच में आवश्यक जानकारी कम बोझिल होती है, अतः यह स्पष्ट नहीं है कि अन्य उत्पादकों ने जानकारी प्रदान नहीं की है।
- झ. अर्जेन्टीना – पोल्ट्री मामले में, पैनल ने यह माना है कि प्रमुख का अर्थ महत्वपूर्ण गंभीर या पर्याप्त है और घरेलू उद्योग उन घरेलू उत्पादकों को संदर्भित करता है, जिनका सामूहिक उत्पादन घरेलू उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक है। ई-सी फास्टनर (चीन) में, अपीलीय निकाय ने यह माना है कि कुल घरेलू उत्पादन का 36 प्रतिशत का अनुपात खंडित फास्टनर उद्योग के संदर्भ में भी कम है। ई सी स्टील फास्टनरों में, अपीलीय निकाय ने माना कि एक बड़े अनुपात को कुल घरेलू उत्पादन का अपेक्षाकृत उच्च अनुपात समझा जाना चाहिए। वर्तमान जांच में प्रमुख हिस्सेदारी कुल घरेलू उत्पादन का 51 प्रतिशत से अधिक है। हालांकि, आवेदकों के पास कुल घरेलू उत्पादन का केवल 33.63 प्रतिशत हिस्सा है।
- ञ. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की गई 35 से अधिक रक्षोपाय जांचों में, प्राधिकृत अधिकारी ने कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक प्रमुख हिस्सा रखा है। आपरेटिंग प्रैक्टिस मैनुअल के पैरा 4.9.2 के अनुसार, कुल

भारतीय उत्पादन में भारत में समग्र भारतीय उत्पादन सम्मिलित होना चाहिए, जिसमें घरेलू बिक्री, निर्यात के साथ-साथ कैप्टिव खपत का उत्पादन भी शामिल होना चाहिए। ओ-एसिड के आयात की पाटनरोधी जांच में, प्राधिकृत अधिकारी ने यह माना कि जांच की अवधि में वास्तविक व्यापारी बिक्री की अनुपस्थिति को कंपनी को घरेलू उद्योग के रूप में मानने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

- ट. जबकि आवेदकों ने समर्थकों की पहचान की है, लेकिन रक्षोपाय जांच में समर्थकों की कोई अवधरणा नहीं है। इस प्रकार, ऐसे उत्पादकों के उत्पादन को स्थिति का निर्धारण करने के उद्देश्य से नहीं माना जा सकता है।
- ठ. समर्थकों ने अपना डेटा उपलब्ध नहीं कराया है। प्राधिकृत अधिकारी को अतिरिक्त उत्पादकों और समग्र रूप से भारतीय उद्योग के प्रदर्शन की स्थिति की एक और जांच करनी चाहिए। यह आवश्यक है, क्योंकि अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री घरेलू उद्योग की बिक्री से अधिक है।
- ड. समर्थकों ने व्यापार सूचना सं. 13/2018 के अनुसार सूचना प्रदान नहीं की है।
- ढ. आवेदकों ने स्वीकार नहीं किया है कि कुल घरेलू उत्पादन के संबंध में सूचना अनुमानित है। यद्यपि, ऐसे अनुमान का आदान प्रदान नहीं किया गया है।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

31. घरेलू उद्योग और स्थिति के संबंध में आवेदकों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

- क. यह याचिका बीएलए कोक प्राइवेट लिमिटेड, जिंदल कोक लिमिटेड, सौराष्ट्र फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, वेदांता माल्को एनर्जी लिमिटेड और वीजा कोक लिमिटेड द्वारा दायर की गई है।
- ख. याचिका को भाटिया कोक एंड एनर्जी लिमिटेड, कृष्णा कोक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मदरसंस कंसोलिडेट, एम वी इंटरनेशनल लिमिटेड, नीलाचल कार्बो मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड, तिरुपति ट्रेडर्स, कोरोमंडल मेट कोक इंडस्ट्रीज और नारायणी कोक प्राइवेट लिमिटेड ने समर्थन किया है।
- ग. आवेदकों के पास भारतीय मर्चेट उत्पादन का 39 प्रतिशत हिस्सा है। समर्थकों के पास आवेदकों के भारत में कुल उत्पादन का 49 प्रतिशत हिस्सा है।
- घ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, व्यापार सूचना 13/2018 रक्षोपाय जांच के लिए लागू नहीं है।
- ड. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, अर्जेन्टाइना -पोल्ट्री मामले में डब्ल्यू टी ओ पैनल ने माना है कि सदस्यों को घरेलू उद्योग को 50 प्रतिशत से अधिक रखने वाले घरेलू उत्पादक के रूप में परिभाषित करने की कोई जरूरत नहीं है। ई-सी फास्टनर (चीन) मामले में अपीलीय निकाय उत्पादकों के स्व-चयन से संबंधित है।
- च. जबकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि पाटनरोधी जांच में घरेलू उद्योग का दायरा बड़ा था, लेकिन रक्षोपाय जांच में घरेलू उद्योग के गठन को समान बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं है।
- छ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान अपने उत्पादन के साथ-साथ कुल भारतीय उत्पादन भी प्रदान किया है।
- ज. जबकि टाटा स्टील लि. और धनबाद एसोसिएशन के सदस्यों के उत्पादन को आधार के प्रयोजन के लिए माना गया था, उन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि टाटा स्टील कैप्टिव उपभोग के लिए उत्पादन करता है और धनबाद एसोसिएशन के सदस्य एन पी वी सी का उत्पादन करते हैं।
- झ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, बंगाल एनर्जी लि. और सातवाहन इस्पात लिमिटेड को सूचीबद्ध करने का तात्पर्य यह नहीं है कि सभी इस्पात निर्माता इसे एक उत्पाद के रूप में पहचानेंगे और अपनी वेबसाइट पर दर्शाएंगे।
- ञ. भारत में तीन प्रकार के उत्पादक हैं, जिनमें हाई ऐश वाले मेट कोक का उत्पादन करने वाला एम एस एम ई उद्योग, संगठित क्षेत्र और मर्चेट बाजार तथा उत्पाद के कैप्टिव उत्पादकों के लिए समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली कुछ एम एस एम ई कंपनियां शामिल हैं।
- ट. उत्पाद के कम से कम 17 उत्पादक हैं, जो निजी तौर पर मेट कोक का उत्पादन करते हैं। कैप्टिव उपयोग के लिए मेट कोक का उत्पादन करने वाले स्टील निर्माताओं पर वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचार नहीं किया

जाना चाहिए, क्योंकि वे मूल रूप से उत्पाद के उपभोक्ता हैं। वे मेट कोक को एक उत्पाद के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। वे मर्चेट बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं और व्यापार बाजार स्थिति से अलग हैं।

- ठ. स्टील निर्माता अपनी वेबसाइट पर मेट कोक को उत्पाद के रूप में निर्दिष्ट नहीं करते हैं। कोकिंग कोयले की तुलना में मेट कोक की व्यापारिक बाजार कीमतों से स्टील निर्माताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- ड. कैप्टिव उत्पादकों को घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जाना चाहिए जो रक्षोपाय कानूनों, पाटनरोधी कानूनों और प्राधिकृत अधिकारी की प्रथा के उद्देश्यों के अनुसार है।
- ढ. कम ऐश वाले मेटलार्जिकल कोक के आयातों पर पाटनरोधी जांच में, जो उत्पादक उत्पाद का उपयोग कर रहे थे, उन्हें घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना गया।
- ण. मर्चेट उत्पादकों और कैप्टिव उत्पादकों की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय अंतर है। मर्चेट उत्पादकों को घरेलू और विदेशी, दोनों प्रकार के अन्य मर्चेट उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जबकि कैप्टिव उत्पादकों को ऐसी किसी भी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता। मर्चेट उत्पादकों को अपने संयंत्र की व्यवहार्यता को बनाए रखने के लिए बाजार में उत्पादित की गई और बेची गई संबद्ध वस्तुओं पर निवेश के प्रतिफल को प्राप्त करने की जरूरत होती है। कैप्टिव उत्पादकों को डाउनस्ट्रीट उत्पाद पर लाभ और निवेश पर प्रतिफल की जरूरत होती है।
- त. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग मामला दर मामला आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी ने रक्षोपाय जांच में 50 प्रतिशत से कम को बड़ा हिस्सा माना है।
- थ. यह आवेदन भारत में समान वस्तुओं के प्रमुख उत्पादकों द्वारा दायर किया गया है। अन्य सभी उत्पादक उत्पादन के व्यक्तिगत उत्पादन के मामले में छोटे हैं।

घ.3. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच

32. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग के संबंध में दिए गए तर्कों और उनकी स्थिति पर विचार किया गया तथा उठाए गए मुख्य मामलों में घरेलू उद्योग की परिभाषा, बड़े हिस्से का तात्पर्य तथा आवेदकों की वैध स्थिति थे

घरेलू उद्योग: विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9क4(ख) के तहत घरेलू उद्योग को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है :

“(ख) घरेलू उद्योग से तात्पर्य वस्तुओं के उत्पादकों से है (कृषि वस्तुओं के उत्पादों सहित)

- (i) भारत में समग्र रूप से समान वस्तुएं अथवा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तुएं; अथवा
- (ii) जिनका भारत में समान वस्तुओं अथवा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तुओं का सामूहिक उत्पादन भारत में उक्त वस्तुओं के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है।”

33. अनुच्छेद 4 के तहत रक्षोपाय पर समझौता अर्थात गंभीर क्षति या उसके खतरे का निर्धारण इस समझौते के प्रयोजन के लिए परिभाषित किया गया है :

(ग) क्षति अथवा उसके खतरे का निर्धारण करने में, एक घरेलू उद्योग का तात्पर्य किसी सदस्य के क्षेत्र के भीतर काम करने वाले समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पादों के समग्र उत्पादकों से है, अथवा जिनसे समान या प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पादों का सामूहिक उत्पादन उन उत्पादों के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा होता है।

यह नोट किया जाता कि रक्षोपाय समझौते के तहत निर्धारित “कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा” शब्द के सटीक चित्रण को समझने के लिए उत्पादन के प्रासंगिक ढांचे की गहन समझ की आवश्यकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कुल उत्पादन और इस तरह का बड़ा हिस्सा क्या है।

34. यह नोट किया जाता है कि न तो रक्षोपाय और न ही एफटीडीआर अधिनियम उत्पादन शब्द को परिभाषित करता है। रक्षोपाय पर समझौते में घरेलू उद्योग शब्द को गंभीर क्षति शीर्षक के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और इसीलिए उत्पादन और बड़ा हिस्सा शब्द की व्याख्या अलग से नहीं की जा सकती है।

35. यह नोट किया जाता है कि रक्षोपाय पर समझौता और एफटीडीआर अधिनियम में उत्पादन शब्द की परिभाषा के संबंध में नहीं कहा गया है। लेकिन ऐसी परिभाषाओं को शामिल करने वाले अन्य कानून भी हैं जिनमें अन्य के अलावा, 1948 का कारखाना अधिनियम, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986, बीडी और सिगार कामगार अधिनियम, 1966 शामिल है। विशेष रूप से इन कानूनों के भीतर व्यक्त की गई उत्पादन की परिभाषाएं पर्याप्त विविधता दर्शाती हैं। इन विविध कानूनों और विनियमों में उत्पादन की संकल्पना से अलग-अलग अर्थ दिए गए हैं, जैसा कि विभिन्न विधायी प्रावधानों में स्पष्ट असमान व्याख्याओं से पता चलता है। यह भी नोट किया जाता है कि उत्पादन के तात्पर्य के निर्धारण के लिए विशिष्ट कानूनों और विनियमों पर उचित विचार की आवश्यकता होती है, जिनमें अंतर्निहित उद्देश्यों और प्रयोजनों की जांच के साथ-साथ उनमें दी गई परिभाषाएं और व्याख्याएं भी शामिल हैं, जिनके लिए उक्त कानून प्रख्यापित किए गए थे। विशेष रूप से प्रासंगिक यह अवलोकन है कि उत्पाद शुल्क कानून के तहत, कुछ सहायक गतिविधियों को पूरा करना, जैसे पैकेजिंग, लेबलिंग, या उपभोज्य विपणन योग्य वस्तुएं मानना, उत्पादन के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि ऐसी गतिविधियां आवश्यक रूप से रक्षोपाय कानून या एफटीडीआर अधिनियम के तहत उत्पादन के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं। अतः उत्पादन शब्द की एक सार्वभौमिक परिभाषा लागू करना अरक्षणीय होगा और इसे अलग-अलग कानूनों के अंतर्निहित प्रयोजनों के साथ मामला दर मामला आधार पर निर्धारित या सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी।
36. अनुच्छेद 4.1 (ग) के तहत रक्षोपायों पर समझौते में घरेलू उद्योग को समान या प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पादों के उत्पादकों के रूप में संदर्भित किया गया है। हालांकि समान वस्तुओं के संबंध में कोई समस्या नहीं है। समझौते के तहत यह प्रावधान है कि वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी होगी। चूंकि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या उसके खतरे व्याख्या के तहत परिभाषित किया गया है। घरेलू उत्पादन के निर्धारण का उद्देश्य उन घरेलू सामानों से होगा, जो आयातों के साथ प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा में हैं और गंभीर क्षति या खतरे का सामना कर रहे हैं।
37. जबकि कुल घरेलू उत्पादन के दायरे में कैप्टिव उत्पादन को शामिल करने का समर्थन करते हुए तर्क दिए गए हैं। यह ध्यान दिया गया है कि ऐसी वस्तुएं अपनी प्रकृति से मर्चेट बाजार में प्रवेश नहीं करती हैं और इस प्रकार आयात किए गए उत्पादों के साथ प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा नहीं करती है। कैप्टिव रूप से उत्पादित वस्तुएं, आयात के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं होने के कारण समझौते, अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तुओं के लिए निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करती है।
38. इसके अलावा, “कुल घरेलू उत्पादन” शब्द की पूर्ण शब्दिक व्याख्या, अधिनियम के अंतर्गत निहित व्यापक उद्देश्य और विधायी प्रयोजन से अलग होने से अस्पष्टता उत्पन्न होती है। अस्पष्टता भी उन स्थितियों से उत्पन्न होती हैं, जहां पर समान वस्तुओं का अधिकांश (80%) उत्पादन निजी तौर पर किया जाता है। घरेलू उत्पादकों द्वारा घरेलू उत्पादन का एक छोटा हिस्सा (20%) मर्चेट बाजार में होता है और इस प्रकार उन्हें प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। आयात किए गए विचाराधीन कैप्टिव उत्पादन को शामिल करने के लिए कुल घरेलू उत्पादन की इस तरह की व्याख्या से ऐसे उत्पादकों को कुल घरेलू उत्पादन का 20 प्रतिशत अल्प हिस्सा मिल जाएगा, जो सक्रिय मर्चेट बाजार की बिक्री में लगे हुए हैं और इस प्रकार से जांच के तहत, आयात किए गए उत्पाद के साथ प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, कानून के तहत किसी भी सहायता से वंचित हो जाएंगे। इसके परिणामस्वरूप एफटीडीआर अधिनियम का अंतर्निहित उद्देश्य और प्रयोजन विपरीत होगा, जो अचानक तेज और महत्वपूर्ण आयात वृद्धि होने से घरेलू उत्पादकों को होने वाली गंभीर क्षति का निवारण करने के लिए बनाया गया है।
39. यूएस -लैंब¹ में अपीलीय निकाय ने पैनल के इस निष्कर्ष पर सहमति व्यक्त की कि एक जांच के संदर्भ में जिसमें प्रासंगिक उत्पाद को मेमने के मांस के रूप में परिभाषित किया गया था, “घरेलू उद्योग” शब्द की व्याख्या में जीवित मेमनों के पालकों और उन्हें खाना खिलाने वालों को शामिल नहीं किया जा सकता है। अपीलीय निकाय ने “घरेलू उद्योग” को परिभाषित करने के लिए विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा
- “[क] रक्षोपाय एक विशिष्ट ‘उत्पाद’ अर्थात् आयातित उत्पाद पर लागू किया जाता है। यह उपाय केवल तभी लागू किया जा सकता है जब उस विशिष्ट उत्पाद (‘ऐसे उत्पाद’) का ‘समान या सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पादों’ का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग पर उल्लिखित प्रभाव पड़ रहा हो। (ज़ोर दिया गया) इसलिए अनुच्छेद 2.1 में दी गई शर्तें कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशिष्ट उत्पादों से संबंधित हैं। विशेष रूप से, अनुच्छेद 2.1 के अनुसार, रक्षोपाय उपाय लागू*

¹ अपीलीय बॉडी रिपोर्ट, यूएस -लैंब, पारस. 86-87

करने का कानूनी आधार केवल तभी होता है जब किसी विशिष्ट उत्पाद के आयात का उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो उस आयातित उत्पाद के 'समान या सीधे प्रतिस्पर्धी' होते हैं। हमारे विचार में, यह अनुच्छेद 2.1 के पाठ से स्पष्ट रूप से अलग होगा यदि जो उत्पाद आयातित उत्पाद के संबंध में 'समान या सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पाद' नहीं हैं उनके घरेलू उत्पादकों पर आयातित उत्पाद का प्रतिकूल प्रभाव होने के कारण एक रक्षोपाय लागू किया जाता है। तदनुसार, घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र का निर्धारण करने में पहला कदम उन उत्पादों की पहचान करना है जो आयातित उत्पाद के 'समान अथवा सीधे प्रतिस्पर्धी' हैं। उन उत्पादों की पहचान किए जाने के बाद ही उन उत्पादों के 'उत्पादकों' की पहचान करना संभव है।"

40. यह भी नोट किया जाता है कि पहले भी अधिकृत अधिकारी ने भारत में "मॉड्यूल या पैनल में असेंबल की गई या नहीं की गई सौर सेलों"² के आयात से संबंधित रक्षोपाय जांच के मामले में रक्षोपाय समझौते के तहत प्रमुख अनुपात के संदर्भ में स्थिति का निर्धारण करते हुए एसईजेड के उत्पादकों को कुल घरेलू उत्पादन से बाहर रखते हुए इसी सिद्धांत को रेखांकित किया है जो निम्नानुसार है:

"यद्यपि, एसईजेड अधिनियम की धारा 2(i) में डीटीए में आयात के रूप में एसईजेड इकाई द्वारा डीटीए स्वीकृतियों के बारे में विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी स्वीकृतियाँ सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क और धारा 8ख के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क, प्रतिकारी शुल्क और रक्षोपाय शुल्क जैसे शुल्कों के अधीन होती हैं। एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 30, जिसमें लागू पाटनरोधी, प्रतिकारी एवं रक्षोपाय शुल्कों का एकत्रण निर्धारित किया गया है, के लिए एक प्रविष्टि बिल दाखिल करना अपेक्षित है जो इस तथ्य को वैध ठहराता है कि डीटीए स्वीकृतियाँ वास्तव में आयात मानी जाएंगी। इसलिए, निम्नलिखित निष्कर्ष दिया गया है:

- (i) एसईजेड इकाइयों की स्थापना का मूल उद्देश्य एक विशिष्ट एसईजेड अधिनियम, 2005 द्वारा प्रबंधित निर्यात को बढ़ावा देना है। एसईजेड के क्षेत्र को एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2(i) के तहत डीटीए की परिभाषा से बाहर रखा गया है। डीटीए से एसईजेड तक माल की आपूर्ति को निर्यात माना जाता है।
- (ii) एसईजेड इकाई द्वारा निर्मित वस्तुओं की डीटीए बिक्री केवल आयात लाइसेंस प्रस्तुत करने पर की जा सकती है, जैसा कि भारत में इसी तरह की वस्तुओं के आयात पर लागू है। एसईजेड से डीटीए को माल की बिक्री या स्वीकृति विभिन्न शुल्कों के अधीन है अर्थात् सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुसार क्रमशः धारा 9 और 8ख के अनुसार लागू किए गए और एसईजेड अधिनियम, 2005.126 की धारा 30 के अनुसार लगाए गए पाटनरोधी शुल्क, प्रतिकारी शुल्क और रक्षोपाय शुल्क।
- (iii) (ईओयू विशिष्ट विदेश व्यापार नीति प्रावधानों द्वारा प्रबंधित होते हैं और एसईजेड इकाइयों को इनकी बिक्री निर्यात मानी जाती है। विदेश व्यापार नीति के प्रावधान डीटीए इकाइयों के साथ-साथ आयात/निर्यात करने की इच्छा रखने वाली इकाइयों पर भी लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त, ईओयू द्वारा डीटीए स्वीकृतियों पर लागू उत्पाद शुल्क/करों का भुगतान किया जाना होता है। वे एसईजेड क्षेत्रों के बाहर एक ही ईकोसिस्टम में सामान्य डीटीए इकाइयों के समान काम करते हैं।
- (iv) इसलिए, उपर्युक्त के आधार पर, मेरा मानना है कि विभिन्न मामलों में अलग-अलग विशेषताओं के साथ एसईजेड इकाई द्वारा डीटीए को अपवादस्वरूप बिक्री का प्रावधान एसईजेड अधिनियम, 2005 के वृहत्तर ढांचे के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए व्यापार उपचारात्मक उपायों के संबंध में एक एसईजेड इकाई को घरेलू उत्पादक के रूप में विचार करने के लिए औचित्यपूर्ण नहीं ठहराता है।

इसलिए, इस जांच में डीआई का दायरा केवल उत्पादकों अर्थात् मैसर्स इंडोसोलर लिमिटेड (ईओयू) और मैसर्स जुपिटर सोलर पावर लिमिटेड तक ही सीमित है, जिसमें ईओयू इकाई भी शामिल है, क्योंकि वे भौतिक रूप से विदेश व्यापार नीतियों द्वारा प्रबंधित डीटीए में स्थित हैं, हालांकि निर्यात उन्मुखीकरण के साथ। (v) 3 एसईजेड इकाइयों को शामिल न करने के साथ डीआई अब मैसर्स इंडोसोलर लिमिटेड और मैसर्स जुपिटर सोलर पावर लिमिटेड तक सीमित है जो संयुक्त रूप से डीटीए में कुल घरेलू उत्पादन का 38% उत्पादन करते हैं।

41. यह आगे नोट किया गया है कि डब्ल्यूटीओ रिपोर्ट के निर्णयों से मांगे गए संदर्भ भी सुरक्षा जांच के लिए घरेलू उद्योग उत्पादन में कैप्टिव खपत को शामिल करने और मूल्यांकन के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित करते हैं। अपीलीय निकाय ने यह भी स्वीकार किया है कि कैप्टिव खपत को उत्पादन गणना में शामिल किया जा सकता है। हालाँकि, इसने

² https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Solar-Final_Finding-English_0.pdf

आनुपातिकता की आवश्यकता पर जोर दिया। डब्ल्यूटीओ पैनल और अपीलीय निकाय की रिपोर्टों के निर्णयों को पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है कि कैप्टिव खपत को स्वचालित रूप से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, इसके लिए औचित्य की आवश्यकता है। अधिकारियों को कुल उत्पादन के सापेक्ष कैप्टिव खपत के अनुपात का आकलन करना चाहिए। केवल विश्लेषण को विकृत करने वाले महत्वपूर्ण अनुपातों को बाहर रखा जाना चाहिए। असंगत रूप से बड़ी मात्रा में कैप्टिव खपत को शामिल करने से घरेलू उद्योग का आकार कृत्रिम रूप से बढ़ सकता है और आयात से इसकी स्पष्ट क्षति हो सकती है। इससे वैध व्यापार को नुकसान पहुंचाने वाले अनुचित सुरक्षा उपाय हो सकते हैं।

42. पूर्व के उदाहरणों के अनुरूप और व्याख्या में सुसंगतता बनाए रखने के लिए, यह पुष्टि की जाती है कि कैप्टिव उत्पादन आयात के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं होने के कारण आयातित वस्तुओं के साथ **सीधी प्रतिस्पर्धा करने वाले** घरेलू उत्पादकों द्वारा सामना किए जाने वाले नुकसान में योगदान नहीं करता है। इसलिए, वर्तमान संदर्भ में कुल घरेलू उत्पादन का निर्धारण करने में, केवल प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी और कानून के तहत परिकल्पित नुकसानकारक प्रभावों के अधीन आने वाली समान वस्तुओं की बिक्री करने वाले उत्पादकों पर विचार किया जाता है। इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों में घरेलू उद्योग के तहत समान या सीधे प्रतिस्पर्धी वस्तुओं का एक बड़े हिस्से का आकलन कैप्टिव उत्पादन को छोड़कर व्यापारी बाजार में उद्योग के उत्पादन के आधार पर किए जाने का प्रस्ताव है।

43. जहां तक प्रमुख अनुपात के मुद्दे का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि यूएस - व्हीट ग्लूटेन³ में पैनल ने "प्रमुख अनुपात" वाक्यांश और डेटा कवरेज के प्रश्न के बीच संबंध को संबोधित किया है

"करार में स्पष्ट रूप से यह परिकल्पना की गई है कि कतिपय परिस्थितियों में 'घरेलू उद्योग' में वे घरेलू उत्पादक शामिल हो सकते हैं 'जिनका समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पादों का सामूहिक उत्पादन उन उत्पादों के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा होता है।' इसका तात्पर्य यह है कि पूर्ण डेटा कवरेज हमेशा संभव नहीं हो सकता है और इसकी आवश्यकता नहीं है। जबकि जांच को अधिकतम सटीक बनाने के लिए पूर्ण संभव डेटा कवरेज की आवश्यकता होती है, किसी विशेष मामले में ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो अन्वेषण करने वाले अधिकृत अधिकारी को इस तरह की कवरेज प्राप्त करने की अनुमति न दे।"

44. यूएस - लैंब 4 में पैनल ने यह भी बताया कि "घरेलू उद्योग" के गठन का गलत निर्धारण संभवतः इस तरह के गलत तरीके से निर्धारित घरेलू उद्योग से संबंधित डेटा की प्रातिनिधिकता को भी बिगाड़ देगा:

"प्रातिनिधिकता की यह कमी की समस्या इस तथ्य से और बढ़ सकती है कि यूएसआईटीसी ने घरेलू उद्योग को मोटे तौर पर उत्पादकों और फीडरों को शामिल करते हुए परिभाषित किया है, क्योंकि अमेरिकी उत्पादकों और फीडरों के केवल एक छोटे से अनुपात से संबंधित आंकड़ों से निकाले गए निष्कर्ष यूएसआईटीसी की गंभीर नुकसान के खतरे के समग्र निष्कर्ष का आधार हैं।"

45. उपरोक्त उदाहरणों और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) अपीलीय निकाय द्वारा दी गई व्याख्याओं के आधार पर, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि घरेलू उद्योग को परिभाषित करने में "एक प्रमुख अनुपात" की अवधारणा एक सख्त सीमा में नहीं बंधी है। बल्कि, मूल बात यह सुनिश्चित करने में निहित है कि घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े गंभीर नुकसान के मानदंड और उसके संभावित खतरे का मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रातिनिधिक हैं।

46. रक्षोपाय के करार के अनुच्छेद 4(ग) के अंतर्गत घरेलू उद्योग की स्थिति के मद्देनजर प्रमुख अनुपात की दलील के संबंध में यह नोट किया जाता है कि रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 4 का पाठ निम्नानुसार है:

47. इस करार के प्रयोजनार्थ:

- (क) "गंभीर क्षति" का अर्थ घरेलू उद्योग की स्थिति में काफी अधिक समग्र गिरावट समझा जाएगा।
- (ख) "गंभीर क्षति का खतरा" का अर्थ ऐसी गंभीर क्षति समझा जाएगा जो पैरा 2 प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट रूप से आसन्न हो। गंभीर क्षति के खतरे की मौजूदगी तथ्यों पर आधारित होगी और केवल आरोप, संयोग और सुदूर संभावना पर आधारित नहीं होगी और

³ पैनल रिपोर्ट, यूएस - व्हीट ग्लूटेन, पारस. 8.54-8.56

⁴ पैनल रिपोर्ट, यूएस - लैंब, पैरा. 7.219

(ग) क्षति या उसके निर्धारण में घरेलू उद्योग का अर्थ किसी सदस्य के क्षेत्र के भीतर प्रचालन कर रहे समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पाद के समग्र रूप से उत्पादक समझे जाएंगे या ऐसे उत्पादक जिनका समान प्रत्यक्ष या प्रतिस्पर्धी उत्पाद का समग्र उत्पादन उन उत्पादों के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता हो।

48. जैसा कि उक्त से देखा जा सकता है कि रक्षोपाय संबंधी करार (घरेलू उद्योग) की परिभाषा के लिए दो विकल्प देता है (i) "समान या प्रतिस्पर्धी उत्पाद उत्पादों के समग्र रूप से उत्पादक"; या (ii) ऐसे उत्पादक जिनका उत्पादन समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन का "एक प्रमुख हिस्सा" बनता हो। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी करार से अलग रक्षोपाय करार में घरेलू उत्पादन के किसी विशिष्ट प्रतिशत या हिस्से का उल्लेख नहीं है जो "एक प्रमुख हिस्से" की अपेक्षा को पूरा करेगा। न ही इसमें किसी पद्धति या प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है जिसे सक्षम प्राधिकारी कुल घरेलू उत्पादन के प्रमुख हिस्से के निर्धारण के लिए अपनाएंगे। यह विचार कि "प्रमुख हिस्सा" कितना होता है, प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
49. अपीलीय निकाय ने पाटनरोधी करार के समान प्रावधान के संदर्भ में यह भी स्पष्ट किया है कि "प्रमुख हिस्सा" शब्द का अर्थ "कुल घरेलू उत्पादन का सापेक्ष रूप से अधिक हिस्सा" है। "प्रमुख हिस्सा" शब्द में "मात्रात्मक और गुणात्मक अर्थ" दोनों शामिल हैं। गुणात्मक तथ्य का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि "समान उत्पाद के घरेलू उत्पादक जिन्हें घरेलू उद्योग की परिभाषा में शामिल किया गया है, उन घरेलू उत्पादन के प्रतिनिधि हों"। अपीलीय निकाय ने बताया कि घरेलू उद्योग में शामिल कुल उत्पादन के हिस्से और घरेलू उद्योग की परिभाषा ने गड़बड़ी के वास्तविक जोखिम और क्षति को आकलन की मौजूदगी के बीच "एक विपरीत संबंध" है।
50. विशेष रूप से "जितना कम हिस्सा है, उतना ही जांचकर्ता प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक संवेदनशील होना होगा कि प्रयुक्त हिस्से में समग्र रूप से उत्पादकों का कुल उत्पादन पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होता हो"। इसी के साथ, "जितना अधिक हिस्सा हो, उतने ही अधिक उत्पादक शामिल किए जाएं और इस आधार पर किए गए क्षति निर्धारण में गड़बड़ी होने की कम संभावना होगी"।
51. इसके अलावा, यूएस – गेहूं के ग्लूटेन में पैनल ने "प्रमुख हिस्से" शब्द और आंकड़ा कवरेज के प्रश्न के बीच संबंध पर ध्यान दिया था। "करार में स्पष्ट रूप से परिकल्पना है कि कतिपय परिस्थितियों में घरेलू उद्योग में ऐसे घरेलू उत्पादक शामिल हो सकते हैं जिनका समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पाद का समग्र उत्पादन उन उत्पादों के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता हो। इसका अर्थ है कि पूरी डेटा कवरेज हमेशा संभव नहीं है और अपेक्षित नहीं है। यद्यपि जांच की सटीकता को अधिकतम बनाने के लिए पूर्णतः संभावित आंकड़ा कवरेज आवश्यक है। तथापि, किसी मामले विशेष में परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिनके कारण जांचकर्ता प्राधिकारी ऐसी कवरेज प्राप्त न कर पाएं।
52. यूएस – लैंब मामले में पैनल ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय प्राधिकारी सभी घरेलू उत्पादकों से सूचना एकत्र करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं ताकि अंतिम निर्धारण के लिए प्रयुक्त आंकड़ों का प्रतिनिधि होना सुनिश्चित हो। फिर भी पैनल ने अन्य बातों के साथ-साथ सांख्यिकीय रूप से वैध नमूने की जरूरत पर बल दिया। "प्रमुख हिस्सा" उद्योग की स्थिति से संबंधित आंकड़ों का प्रतिनिधि होने से संबंधित है।
53. इस प्रकार, जांचकर्ता प्राधिकारी का प्राथमिक सरोकार उद्योग की स्थिति पर आधारित है और प्रयुक्त आंकड़े घरेलू उत्पादकों की स्थिति को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करने चाहिए। इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों विश्लेषण शामिल हैं। यह तर्क दिया जा सकता है कि जब घरेलू उत्पादक की आंकड़ा कवरेज 50 प्रतिशत से कम हो, तो गंभीर क्षति के गलत आकलन का अत्यधिक जोखिम होता है। तथापि, ऐसी किसी प्रतिशत सीमा के अभाव में मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण प्रमुख बन जाता है।
54. वर्तमान जांच में आवेदकों ने कुल घरेलू उत्पादन में अपनी उत्पादन क्षमता और संबंधित शेयर का ब्यौरा देते हुए उत्पादकों का रॉस्टर पहले प्रस्तुत किया है। इसके बाद, आवेदकों द्वारा एक संशोधित सूची प्रस्तुत की गई है जिसमें विचाराधीन उत्पाद के लिए कतिपय उद्योगों को घरेलू उत्पादकों के दायरे से या तो उन व्यापारी के रूप में उनके दर्जे या संबद्ध वस्तु का उत्पादन नहीं करने के कारण बाहर किया गया है। ऐसे आंकड़ों के संशोधन पर कुल घरेलू उत्पादन में आवेदक उत्पादकों का प्रतिशत बढ़कर 53 प्रतिशत हो जाता है जबकि समर्थकों का हिस्सा बढ़कर 14 प्रतिशत हो गया। यदि प्रतिशत सीमा के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों पर विचार किया जाए तो आवेदक उत्पादकों के पास फिर भी कुल घरेलू उत्पादन में 53 प्रतिशत हिस्सा है और समर्थकों से जोड़ने पर समग्र प्रतिशत हिस्सा संशोधित आंकड़ों के अनुसार 67 प्रतिशत हो जाता है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग की स्थिति के लिए मापदंड पूरे होते हैं।

55. तथापि, इस समय घरेलू उद्योग ने उत्पादन के संशोधित आंकड़े प्रदान किए हैं। तथापि, प्राधिकृत अधिकारी उन पर विचार नहीं करते हैं, क्योंकि इसे जांच के बिल्कुल अंत अर्थात् प्रकटन विवरण जारी होने के बाद संशोधित किया गया है। फिर भी प्राधिकृत अधिकारी रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4(ग) से संबंधित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा रेखांकित न्यायशास्त्र कार्यवाही के अनुसरण में, यह बताते हैं कि आवेदक उत्पादकों में बड़े उद्यम और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) का मिश्रण शामिल है। यह संगठन गैर-भागीदार उत्पादकों के रोस्टर से मिलता-जुलता है। इस प्रकार, आवेदक उद्योग घरेलू उत्पादकों की वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से दर्शाने में पर्याप्त रूप से सक्षम है। इसके अलावा, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि विधायिका द्वारा प्रमुख हिस्से के सिद्धांत के अंतर्गत घरेलू उद्योग की स्थिति से संबंधित कोई विशिष्ट प्रतिशत सीमा परिभाषित नहीं की गई है जैसा कि रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4(ग) में रेखांकित है। इसके बजाय, उद्योग के प्रतिनिधित्व के कारण यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की आवश्यकता है कि आवेदक उद्योग मौजूद उद्योग की प्रचलित स्थिति को बिल्कुल सही ढंग से दर्शाता है। इस प्रकार, क्षति निर्धारण की प्रक्रिया की उपयुक्तता बढ़ जाती है। वर्तमान जांच में आवेदक उत्पादकों के दायरे में आमेसन उद्योग की वर्तमान स्थिति दर्शाता है, जो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विश्लेषण को पूरा करती है। परिणामस्वरूप, रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4(ग) में यथा रेखांकित प्रमुख हिस्से के सिद्धांत के अनुपालन में स्थिति के आधारों संबंधी धारणा नहीं बनायी जा सकती है। पूर्वोक्त के आलोक में, प्राधिकृत अधिकारी मानते हैं कि आवेदक उत्पादक वास्तव में रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4(ग) के अंतर्गत वास्तव में प्रमुख हिस्सा हैं।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

56. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं।

- क) आवेदकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि विक्री मूल्य, कर्मचारियों, प्रति दिन उत्पादकता, माल सूची, पीबीआईटी, ब्याज/वित्त लागत, मूल्यहास और परिशोधन व्यय के लिए कुल डेटा साझा नहीं किया गया है।

ड.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

57. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क) अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, कीमतों, लागत और लाभप्रदता के बारे में वास्तविक जानकारी के साथ ग्राहक आवेदकों की कीमतों पर मोल-भाव कर सकेंगे और इसका याचिकाकर्ताओं के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव होगा। अतः इसे साझा नहीं किया गया है।

ड.3. अधिकृत अधिकारी द्वारा जाँच

58. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, नियमों के नियम 7 में निम्नानुसार प्रावधान है:

गोपनीय सूचना-

(1) नियम 6 के उपनियम (1), (3) और (7) और नियम 9 के उपनियम (5) में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी जानकारी जो गोपनीय प्रकृति की है या जो गोपनीय आधार पर प्रदान की गई है, कारण बताए जाने पर अधिकृत अधिकारी द्वारा इसे गोपनीय माना जाएगा और ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) अधिकृत अधिकारी गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षों से उसका गैर गोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है और यदि, ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष की राय में, ऐसी जानकारी को संक्षेप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा पक्ष अधिकृत अधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि ऐसी जानकारी का सारांश देना क्यों संभव नहीं है।

(3) उप-नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि अधिकृत अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि गोपनीयता के अनुरोध की आवश्यकता नहीं है या सूचना का आपूर्तिकर्ता या तो सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी का अनुरोध छोड़ सकता है जब तक कि उचित स्रोतों से उसकी संतुष्टि के लिए यह प्रदर्शित न हो जाए कि ऐसी जानकारी सही है।”

59. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय संस्करण हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल के माध्यम से एक दूसरे की टिप्पणियों के अगोपनीय संस्करण को साझा करने का निर्देश देकर उपलब्ध कराया गया है।
60. घरेलू उद्योग ने गोपनीय आधार पर अपने आवेदन में कुछ जानकारी दी है और अनुरोध किया है कि इसे गोपनीय माना जाए। घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन का एक अगोपनीय संस्करण (एनसीवी) भी प्रदान किया है, जैसा कि नियमों के तहत अपेक्षित है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने इस सूचना की गोपनीयता के अपने दावे को न्यायोचित ठहराते हुए कारण प्रस्तुत किए हैं।
61. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि आवेदकों ने लाभप्रदता, व्याज/वित्त लागत, मूल्यहास और परिशोधन व्यय के बारे में कुल डेटा प्रदान नहीं करके अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। अधिकृत अधिकारी का मानना है कि गोपनीय मापदंडों को साझा करने से घरेलू उद्योग के व्यावसायिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और प्रतियोगियों और उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा। इससे ग्राहक यह आकलन कर सकेंगे कि वे अन्य ग्राहकों की तुलना में अधिक या कम कीमतों का भुगतान कर रहे हैं, और इससे ग्राहक कम कीमतों की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से अधिकृत अधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को कारण बताने पर ऐसी जानकारी को गोपनीय जानकारी के रूप में दावा करने की अनुमति दी है। इसे देखते हुए, अधिकृत अधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए गोपनीयता के दावे को स्वीकार कर लिया है।
62. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई थी। संतुष्ट होने पर, जहां भी आवश्यक है वहाँ गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया गया है, और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है।

च. विविध मुद्दे

च1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

63. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- क) आवेदकों ने जाँच शुरू करने के लिए ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं और अधिकृत अधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों की उपयुक्त और पर्याप्त जाँच नहीं की है।
- ख) घरेलू उद्योग व्यापार उपचारों का एक अभ्यस्त उपयोगकर्ता है और स्थायी रूप से व्यापार उपचारात्मक उपायों की मांग करके आयात प्रतिस्पर्धा को सीमित करने का इरादा रखता है।
- ग) आवेदकों ने आयात डेटा के स्रोत का खुलासा नहीं किया है। आयात डेटा अविश्वसनीय लगता है क्योंकि आवेदकों ने कहा है कि कुछ विवरणों को विचाराधीन उत्पाद के आयात के रूप में नहीं माना गया है। तथापि, डीजीसीआईएंडएस के प्रकाशित आंकड़ों से उत्पाद के विवरण का खुलासा नहीं होता है।
- घ) चूंकि वर्ष 2019-20 से पहले आयात की मात्रा क्षति की अवधि में आयात से अधिक थी, इसलिए वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में आयात के आधार पर कोटा निर्धारित करने से भारत में विचाराधीन उत्पाद की उपलब्धता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अधिकृत अधिकारी कृपया वर्ष 2019-20 से पहले के तीन प्रतिनिधि वर्षों पर विचार कर सकते हैं।
- ङ) आवेदकों ने प्रारंभ किए जाने के बाद की टिप्पणियों में अनुरोध किए गए उपायों की अवधि के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया है। यदि अनुरोध किए गए उपाय एक वर्ष से अधिक के लिए हैं, तो आवेदकों द्वारा एक समायोजन योजना प्रदान की जानी चाहिए।
- च) वृद्धि की अवधि को शामिल किए बिना कोटा निर्धारित करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। विचाराधीन उत्पाद की मांग में हाल ही में वृद्धि हुई है, जो कोटा मांग-आपूर्ति अंतर का प्रतिनिधित्व नहीं करता है वह डाउनस्ट्रीम उद्योग के लिए हानिकारक होगा।

च2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

64. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- क) अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उन साक्ष्यों का उल्लेख नहीं किया है जो घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

- ख) अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, अधिकृत अधिकारी ने विस्तृत जांच करने के बाद ही पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की और निष्कर्ष निकाला कि निर्यातक व्यापार के अनुचित तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं।
- ग) आवेदकों ने डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित डेटा प्रदान किया है, हालांकि, अधिकृत अधिकारी डीजीसीआईएंडएस के ट्रांज़ैक्शन बाई ट्रांज़ैक्शन डेटा को आधार मानेंगे।
- घ) अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों के विपरीत, वर्तमान जांच में ऐतिहासिक डेटा अप्रासंगिक है और कोटा अधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्व में अपनाई गई प्रणाली पर आधारित होना चाहिए।
- ङ) आवेदकों ने एक वर्ष की अवधि के लिए उपायों का अनुरोध किया है।
- च) अधिकृत अधिकारी द्वारा सतत रूप से पिछले तीन वर्षों के आधार पर कोटा निर्धारित करने की प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है।

च3. अधिकृत अधिकारी द्वारा जांच

65. इस तर्क के संबंध में कि जांच सबूतों के बिना निराधार जानकारी के आधार पर शुरू की गई थी, यह नोट किया जाता है कि आवेदकों ने एक विधिवत प्रमाणित आवेदन प्रदान किया है, जिसके आधार पर वर्तमान जांच शुरू की गई थी। पर्याप्त सबूत मौजूद होने के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के बाद ही जांच शुरू की गई थी। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रारंभ किए जाने के चरण में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई किसी भी ठोस सूचना को चुनौती देने अथवा इस चरण में अधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए प्रथम दृष्टया निष्कर्षों को चुनौती देने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।
66. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग व्यापार उपचारों का एक अभ्यस्त उपयोगकर्ता है। तथापि, यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने अप्रत्याशित घटनाक्रम के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षत पहुंचाते हुए आयात में वृद्धि के पर्याप्त साक्ष्य के साथ एक आवेदन किया है। उपचारात्मक उपाय मामला दर मामला आधार पर रक्षोपाय नियमों के अनुसार किए जाएंगे।
67. आयात डेटा के स्रोत के संबंध में, जैसा कि ऊपर प्रक्रिया भाग में बताया गया है, डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त ट्रांज़ैक्शन-वार डेटा को वर्तमान जांच के उद्देश्य से आधार बनाया गया है।
68. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उल्लेख किया है कि कोटा वर्ष 2019-20 से पहले के आयात पर आधारित होना चाहिए। अधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि अधिकृत अधिकारी सामान्य तौर पर वृद्धि की अवधि से पहले के तीन वर्षों में औसत आयात के आधार पर कोटा निर्धारित करते हैं। संभवतः वर्ष 2019-20 से पहले आयात अधिक था। हालांकि, कोविड-19 के बाद बाजार की स्थिति बदल गई है। भारत में मांग में भी कोविड-19 से पहले और बाद में काफी हद तक बदलाव आया है। अधिकृत अधिकारी प्रचलित नियमों के अनुसार किन्हीं उपायों की सिफारिश करेंगे।

छ. आयात में वृद्धि

1. छ1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

69. आयात में वृद्धि के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क) अर्जेंटीना में फुटवियर अपीलीय निकाय ने माना कि आयात में वृद्धि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप से हालिया, अचानक, तेज और उल्लेखनीय होनी चाहिए। इस प्रकार, ऐसी आवश्यकताएँ संयुक्त रूप से पूरी होनी चाहिए, और यदि इनमें से केवल एक या दो मानदंड पूरे होते हैं तो यह पर्याप्त नहीं है।
- ख) अधिकृत अधिकारी को नुकसान की पूरी अवधि के आधार पर वृद्धि का निर्धारण करना चाहिए, न कि केवल पिछले वर्ष के आधार पर। यूएस-लैम्ब में अपीलीय निकाय ने माना कि जांच की अवधि के लिए संपूर्ण रूझान को ध्यान में रखा जाना चाहिए, बजाय इसके कि सबसे हाल की अवधि के आंकड़ों को अलग किया जाए और इसका अलग से मूल्यांकन किया जाए।
- ग) पोलैंड से आयात में अचानक, तेज और हाल में वृद्धि नहीं हुई, जबकि अन्य देशों से भारत में आयात हुआ। आवेदकों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कोयले की कीमतों में वृद्धि से पोलैंड से भारत में आयात में वृद्धि कैसे होती है। नुकसान की अवधि में रूस से आयात में गिरावट आई है और अन्य सभी स्रोतों से आयात भी घट रहा है।

- घ) पोलैंड के निर्यातक ने दीर्घकालिक समझौते के तहत निर्यात किया है और इस तरह के निर्यात किसी भी अप्रत्याशित घटनाक्रम से प्रभावित नहीं हुए हैं। निर्यातक से आयात में वास्तव में गिरावट आई और सबसे हाल की अवधि के दौरान यह सबसे कम था। इस प्रकार, पोलैंड/निर्यातक को मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने से बाहर रखा जाना चाहिए।
- ङ) आयात मुख्य रूप से चीन से बढ़े हैं, इसलिए भारत में सभी आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध उपयुक्त उपाय नहीं है।
- च) चीन से आयात में प्रमुख रूप से वृद्धि हुई है। कोविड-19 के कारण वर्ष 2020-21 और 2021-22 में चीन से निर्यात में गिरावट आई थी, लेकिन जैसे ही अर्थव्यवस्था ठीक हुई, चीन से निर्यात बढ़ गया। इस तरह की वृद्धि इस कारण से भी थी कि भारतीय इस्पात उद्योग में मैट कोक की मांग बढ़ गई थी।
- छ) आयातों की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि जांच की कुल अवधि की तुलना में आयातों में वृद्धि नहीं हुई है। सबसे हालिया अवधि के दौरान आयात में वृद्धि केवल कोविड-19 के बाद व्यापार के सामान्यीकरण के कारण है। वास्तव में वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में आयात की तुलना में आयात में गिरावट आई है।
- ज) इंडोनेशिया से आयात कुल आयात का बहुत कम हिस्सा है। इंडोनेशिया से आयात की कीमत में बाजार की स्थिति के साथ उतार-चढ़ाव हुआ लेकिन कुल मिलाकर यह स्थिर रहा।
- झ) कच्चे इस्पात के उत्पादन में वृद्धि के कारण भारत में आयात में वृद्धि हुई है।
- ञ) कोविड-19 के प्रभाव के कारण वर्ष 2020-21 और 2021-22 में आयात में गिरावट आई। वर्ष 2019-20 की तुलना में भारत में आयात में केवल 20% की वृद्धि हुई जो मांग में वृद्धि को देखते हुए वृद्धि की सामान्य दर है।
- ट) चूंकि रक्षोपाय (क्यूआर) नियमावली के नियम 9 में कहा गया है कि अधिकृत अधिकारी को गंभीर नुकसान की रोकथाम के लिए पर्याप्त मात्रात्मक प्रतिबंधों की सीमा और प्रकृति की सिफारिश करनी चाहिए, अधिकृत अधिकारी किसी विशिष्ट देश को मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने से बाहर रख सकता है। यहां तक कि वैश्विक रक्षोपाय (टैरिफ-दर कोटा) किसी विशिष्ट देश के खिलाफ लगाया जा सकता है।

छ2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

70. आयातों में वृद्धि के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क) अप्रत्याशित घटनाओं के परिणामस्वरूप विचाराधीन उत्पाद के आयात में अचानक, तेज और उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- ख) भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में विचाराधीन उत्पाद की हिस्सेदारी में काफी वृद्धि हुई है।
- ग) आयात मुख्य रूप से चीन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात से बढ़ा है। हालांकि, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और यूएई के पास विनिर्माण सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए, इस तरह के आयात माल का ट्रांसशिपमेंट हैं।
- घ) अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के विपरीत, वर्ष 2019-20 की तुलना में चीन से आयात में काफी वृद्धि हुई है, जो कोविड-19 के कारण नहीं था।
- ङ) विचाराधीन उत्पाद की मांग में पिछले वर्ष की तुलना में 5% की वृद्धि हुई है जबकि आयात में 46% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार, ऐसी वृद्धि इस्पात के उत्पादन में वृद्धि के कारण नहीं है।
- च) अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों के विपरीत, भारत में इंडोनेशिया से आयात काफी बढ़ गया है और इसकी कीमत घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत से कम है।
- छ) अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों के विपरीत, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि सभी स्रोतों से आयात बढ़े।
- ज) अधिनियम अथवा नियमों के अंतर्गत किसी विशेष देश अथवा निर्यातक से आयात को वर्तमान जांच के दायरे से बाहर रखने का कोई प्रावधान नहीं है।

छ3. अधिकृत अधिकारी द्वारा जांच**छ.3.1. "बढ़ी हुई मात्रा" का अर्थ**

71. अधिनियम की धारा 9क के प्रावधानों के अंतर्गत रक्षोपाय उन मामलों में लागू किए जा सकते हैं जहां किसी उत्पाद का आयात बढ़ी हुई मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में किया जा रहा है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान हो अथवा उससे गंभीर नुकसान होने का खतरा हो। मात्रात्मक प्रतिबंध नियमों के नियम 2(ग) के अनुसार, "बढ़ी हुई मात्रा" में आयात में वृद्धि शामिल है, चाहे वह निरपेक्ष रूप से हो या घरेलू उत्पादन के सापेक्ष हो।

छ.3.2. निरपेक्ष रूप से आयात में वृद्धि

72. जांच की अवधि में आयात की मात्रा इस प्रकार थी।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
ऑस्ट्रेलिया	एमटी	1,44,573	18,002	1,16,925	2,55,530
बहरीन	एमटी	453	552	1,711	-
भूटान	एमटी	-	-	91	100
चिली	एमटी	-	11,364	11,800	12,408
चीन जन.गण.	एमटी	3,13,567	32,690	82,431	8,29,732
कोलंबिया	एमटी	3,99,682	5,22,275	4,39,508	4,39,850
मिस्र	एमटी	42,675	-	-	-
फिनलैंड	एमटी	40,812	-	-	-
जर्मनी	एमटी	3	-	-	-
हांगकांग	एमटी	3,565	56	1,934	-
इंडोनेशिया	एमटी	1,50,521	1,34,267	76,956	2,56,699
ईरान	एमटी	17,384	610	-	-
इटली	एमटी	-	32	-	-
जापान	एमटी	4,19,909	3,79,058	3,45,603	3,00,245
कोरिया जनवादी गणराज्य	एमटी	-	-	36,371	-
मलेशिया	एमटी	597	-	-	-
नीदरलैंड	एमटी	-	-	38,418	-
न्यूज़ीलैंड	एमटी	-	291	-	-
ओमान	एमटी	-	-	-	10,000
पोलैंड	एमटी	7,49,967	9,56,636	10,53,358	8,60,925
प्यूर्टो रिको	एमटी	4,000	-	-	-
कतर	एमटी	956	2,842	5,031	3,367
रूस	एमटी	3,22,561	1,18,850	44,710	85,144
सऊदी अरब	एमटी	-	-	-	237

सिंगापुर	एमटी	1,76,351	51,878	25,112	1,98,182
दक्षिण अफ्रीका	एमटी	-	-	-	312
स्पेन	एमटी	259	97	94	-
स्विट्ज़रलैंड	एमटी	46,019	1,96,647	2,03,074	2,09,586
संयुक्त अरब अमीरात	एमटी	24	5,831	2,558	53,112
यूके	एमटी	87	98	229	225
यूएसए	एमटी	-	-	653	0
यूक्रेन	एमटी	-	-	25,000	-
वेनेजुएला	एमटी	940	504	218	-
कुल	एमटी	28,34,905	24,32,580	25,11,786	35,15,654

73. यह देखा गया है कि वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में आयात की मात्रा में गिरावट आई है। यह कम से कम आंशिक रूप से कोविड-19 के कारण हो सकता है, जैसा कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किया गया है। तथापि, इसके बाद आयातों में सर्वाधिक हाल की अवधि तक वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वृद्धि हुई। हालाँकि वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान आयात में 40% की वृद्धि हुई। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 में आयात की मात्रा पहले के सभी वर्षों की तुलना में अधिक थी। आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में आयात में 24% की वृद्धि हुई।

74. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उल्लेख किया है कि आयात केवल चीन से बढ़ा है और यह कोविड-19 के बाद व्यापार के सामान्यीकरण के कारण है। तथापि, यह देखा गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में चीन से आयातों में 907% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, आधार वर्ष की तुलना में भी, ऐसे आयात में 165% की वृद्धि हुई है। चूंकि वर्ष 2019-20 कोविड-19 से प्रभावित नहीं था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि आयात में वृद्धि केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के सामान्यीकरण के कारण है। इसके अलावा, किसी भी स्थिति में, भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयात में वृद्धि हुई है। वृद्धि केवल चीन से नहीं है। वास्तव में, चीन भारतीय बाजार में कोक का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता नहीं था और जांच अवधि में चीन से आयात कुल आयात का केवल 11% था (जांच अवधि में सभी स्रोतों से संयुक्त रूप से 112.95 लाख के कुल आयात की तुलना में 12.58 लाख)। इसके अलावा, आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में आयात में 6,80,749 मीट्रिक टन की कुल वृद्धि की तुलना में, चीन से आयात में 5,16,165 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। शेष वृद्धि अन्य बातों के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और स्विट्जरलैंड से आयातों में वृद्धि के कारण है।

75. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उल्लेख किया है कि इंडोनेशिया से आयात का भारतीय बाजार में एक छोटा हिस्सा है और इस तरह के आयात की कीमत स्थिर बनी हुई है। हालाँकि यह देखा गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में इंडोनेशिया से आयात में 234% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार, इंडोनेशिया से आयात में स्पष्ट वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि (क) जांच अवधि के बाद इंडोनेशिया से आयात में और वृद्धि हुई थी, (ख) इंडोनेशिया से निर्यात में बढ़ा हिस्सा भारत को किए गए निर्यात का है, (ग) इंडोनेशिया से आयात की कीमत घरेलू उद्योग के कच्चे माल की कीमत से कम है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
इंडोनेशिया से आयात की मात्रा	एमटी	1,50,521	1,34,267	76,956	2,56,699
इंडोनेशिया से आयात की कीमत	₹/एमटी	22,024	22,574	35,340	37,142
आरएम की लागत	₹/एमटी	18,427	15,713	24,539	39,312

76. इस तर्क के संबंध में कि पोलैंड से आयात में गिरावट आई है और निर्यातक ने दीर्घकालिक समझौते के तहत निर्यात किया है, यह देखा गया है कि पोलैंड से आयात में वर्ष 2022-23 में गिरावट आई है। हालाँकि, इस गिरावट के बावजूद, पोलैंड से आयात कुल आयात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (24%) है। रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 2.2 में यह प्रावधान है

कि “आयात किए जा रहे उत्पाद पर रक्षोपाय उपाय लागू किए जाएंगे चाहे उसका स्रोत कुछ भी हो।” एकमात्र अपवाद विकासशील देशों के संबंध में है, जिनके आयात की मात्रा निर्धारित स्तरों से कम है। हालांकि, पोलैंड से आयात इस तरह के अपवाद के अंतर्गत नहीं आते हैं। देश में कुल मांग के संबंध में आयात उल्लेखनीय थे, जिनकी हिस्सेदारी 14% थी। इसलिए, पोलैंड से आयात को शुल्क के दायरे से बाहर रखने के लिए बनाया गया मामला पर्याप्त नहीं है। इसे देखते हुए, पोलैंड से आयात को कोई छूट नहीं दी जा सकती है।

छ.3.3. निरपेक्ष रूप से आयात में वृद्धि

77. इस अवधि में भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में आयात की मात्रा की भी जांच की गई है। यह देखा गया है कि घरेलू उत्पादन और खपत की तुलना में आयातों में काफी वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
विभिन्न स्रोतों से आयात (डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार)	एमटी	28,34,905	24,32,580	25,11,786	35,15,654
आवेदकों द्वारा बिक्री	एमटी	***	***	***	***
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	एमटी	100	90	93	106
		***	***	***	***
कुल भारतीय बिक्री	एमटी	100	80	113	104
कुल व्यापारी मांग	एमटी	***	***	***	***
भारत में संस्थापित कुल व्यापारी क्षमताएँ	एमटी	100	84	106	105
की तुलना में आयात		***	***	***	***
भारतीय व्यापार बिक्री की तुलना में आयात	%	100	85	97	115
भारतीय मांग की तुलना में आयात	%	***	***	***	***

यह देखा गया है कि:

क) पिछले वर्ष की तुलना में व्यापार बिक्री के संबंध में आयात में 41% की वृद्धि हुई है।

ख) खपत के संबंध में आयात में पिछले वर्ष की तुलना में 18% की वृद्धि हुई है।

यह भी देखा गया है कि भारतीय उद्योग के पास पर्याप्त क्षमताओं के मौजूद होने के बावजूद उत्पादन और खपत की तुलना में आयातों में उपर्युक्त वृद्धि हुई है। इस प्रकार यह देखा गया है कि हाल की अवधि में आयातों में अचानक, तीव्र, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ज. अप्रत्याशित घटनाक्रम

ज1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

78. अप्रत्याशित घटनाओं के संबंध में अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए।

क) घरेलू उद्योग ने अप्रत्याशित घटनाक्रम का दावा करने के लिए कोई उचित कारण नहीं दिया है क्योंकि रूस-यूक्रेन संघर्ष का निपटारा हो गया है और घटनाक्रम और आयात में वृद्धि के बीच कोई तार्किक संबंध प्रदान नहीं किया गया है।

ख) जबकि घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि ऑस्ट्रेलिया में कोर्किंग कोयले की कीमतें कम बनी हुई हैं, यह सच नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी कोयले की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ग) ऑस्ट्रेलिया के कोयले की कीमतों में वृद्धि का भारतीय बाजार, वैश्विक बाजार और ऑस्ट्रेलिया में स्थानीय बाजार पर समान प्रभाव पड़ा।

- घ) कोयले की कीमतों में विश्व स्तर पर वृद्धि हुई थी और न केवल भारत के लिए, बल्कि इंडोनेशियाई उत्पादकों ने भी बढ़ी हुई कीमतों पर कोयला खरीदा था। इस प्रकार, यह अप्रत्याशित घटनाक्रम नहीं है।
- ङ) यदि कोयले की कीमत में वृद्धि को अप्रत्याशित घटना माना जाता है तो यह ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे देशों से आयात के मामले में लागू है न कि सभी देशों के लिए।
- च) रूस-यूक्रेन संघर्ष से पहले कोकिंग कोयले की कीमत में वृद्धि हुई थी, इसलिए कोयले की कीमतों में वृद्धि का कारण यह नहीं हो सकता है। कोकिंग कोयले की कीमतों में वर्ष 2022-23 में गिरावट आई है और वर्ष 2024 में और गिरावट की उम्मीद है। आवेदकों के लिए कोयले के खरीद मूल्य में वर्ष 2022-23 के दौरान गिरावट आई है।
- छ) कोविड-19 के परिणामस्वरूप आपूर्ति की बाधाओं के कारण वर्ष 2020 में कोयले की कीमतों में गिरावट आई। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के कारण कोयले की कीमत में वर्ष 2021 और वर्ष 2022 में अस्थिरता दिखाई दी। वर्ष 2023 में कोयले की कीमत में फिर से गिरावट शुरू हो गई है।
- ज) कोयले की कीमतों में वृद्धि कोयले की मजबूत मांग के कारण हुई, जिसका पूर्वानुमान लगाया गया था। चूंकि कोयले की कीमतों में वृद्धि वैश्विक स्तर पर लागू होती है, इसलिए भारत में कीमतों में वही रुझान देखा गया।
- झ) चूंकि भारत भी कोकिंग कोल का एक प्रमुख उत्पादक है, इसलिए इस तथ्य में कोई दम नहीं है कि स्थानीय स्तर पर कोयले की खरीद करने वाले उत्पादक प्रभावित नहीं हुए थे।
- ञ) वर्ष 2021 में माल दुलाई दरों में वृद्धि हुई और उसके बाद गिरावट आई। इसके अलावा, मालभाड़ा दरों ने भारत में कोकिंग कोयले और मैट कोक दोनों के आयात को प्रभावित किया है। पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयात की रक्षोपाय जांच में अधिकृत अधिकारी ने निर्णय दिया कि मालभाड़ा दर में वृद्धि कच्चे माल के साथ-साथ तैयार माल के आयात को प्रभावित करती है, इस प्रकार यह क्षतिकारक प्रभाव को निष्प्रभावी करती है।
- ट) वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कोकिंग कोयले की न्यूनतम मात्रा का आयात किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कोकिंग कोयले की कीमतों और मालभाड़ा में किसी प्रकार की वृद्धि से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति नहीं होनी चाहिए।
- ठ) घरेलू उद्योग द्वारा चिह्नित कारक अप्रत्याशित नहीं हैं। विभिन्न देशों के बीच कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों में निहित असमानता सामान्य भौगोलिक भिन्नताएं हैं। मालभाड़ा दर में वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि मांग-आपूर्ति की गतिशीलता के कारण मालभाड़ा दरों में उतार-चढ़ाव होना निश्चित है।
- ड) आवेदकों ने उल्लेख किया है कि चीन के उत्पादकों को रूसी कोयले की खरीद से लाभ हुआ है क्योंकि रूस से आयात पर चीन द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। भारत ने भी रूस से कोयले के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया और घरेलू उद्योग भी ऐसा करने के लिए स्वतंत्र था। इसके विपरीत, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारतीय उद्योग को रूसी कोयले के आयात से लाभ हुआ है।
- ढ) आवेदकों ने यह सिद्ध करने के लिए सूचना उपलब्ध नहीं कराई है कि आयात में वृद्धि गैट (GATT) के अंतर्गत भारत द्वारा दी गई वचनबद्धताओं के प्रभाव के कारण हुई है। कोरिया में डेयरी अपीलीय निकाय ने माना कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को रक्षोपायों को लागू करने से पहले रक्षोपायों पर समझौते के साथ-साथ गैट (GATT) के अनुच्छेद XIX का पालन करना चाहिए।
- ण) अप्रत्याशित घटनाक्रम को दर्शाने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अप्रत्याशित घटनाक्रम से पहले के हैं।
- त) आयात में वृद्धि मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और चीन से हुई है। ऐसी वृद्धि अप्रत्याशित घटनाक्रम के कारण नहीं है बल्कि ऐसे देशों पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने के कारण है।
- थ) अर्जेंटीना में फुटवियर अपीलीय निकाय ने माना कि अप्रत्याशित घटनाओं का अर्थ है रक्षोपाय पर डब्ल्यूटीओ करार के लागू होने के समय और टैरिफ रियायतें देते समय अप्रत्याशित या अनपेक्षित घटनाएँ। घरेलू उद्योग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के लागू होने के समय कोयले अथवा मालभाड़े की कीमत में वृद्धि किस प्रकार अप्रत्याशित थी।

- द) आयात की मात्रा में वृद्धि एफटीए के अंतर्गत भारत द्वारा दी गई टैरिफ रियायतों के कारण हुई है। भारत में आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स के पैनेल ने माना कि सीमा शुल्क पर रियायतें प्रदान करना गैट (GATT) के तहत बाध्यता नहीं है।
- ध) 6 महीने की अवधि के लिए सीमा शुल्क लागू न होने के कारण आयात में वृद्धि हुई है। सीमा शुल्क में कमी को अप्रत्याशित घटना नहीं माना जा सकता है। फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलीओल के आयातों की रक्षोपाय जांच में अधिकृत अधिकारी ने भारत-सिंगापुर सीईसीए को आयातों में वृद्धि का एक कारण माना और यह माना कि यह कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है।
- न) मेट कोक के आयात पर छूट 19 नवंबर 2022 को वापस ले ली गई है। इस प्रकार, आयात में वृद्धि का प्राथमिक कारण मौजूद नहीं है और इस प्रकार, उपायों को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- प) घरेलू उद्योग द्वारा चिह्नित की गई स्थितियां अस्थायी प्रकृति की हैं और दावा किए गए अप्रत्याशित घटनाक्रम हाल की अवधि में मौजूद नहीं थे।

ज2. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

79. अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण आयातों में वृद्धि के संबंध में आवेदकों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

- क. अप्रत्याशित परिस्थितियों के परिणामस्वरूप भारत में आयातों में वृद्धि हुई है।
- ख) जूते के आयात पर अर्जेंटीना के 'अपीलीय निकाय -रक्षोपाय' ने नोट किया कि अप्रत्याशित परिस्थितियां अनापेक्षित परिस्थितियां हैं, अपूर्वानुमेय परिस्थितियां नहीं हैं।
- ग) आयातों में वृद्धि रूस-यूक्रेन युद्ध का परिणामी प्रभाव है जिसके फलस्वरूप कोयले के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और भारत में उत्पादन की लागत में भी वृद्धि हुई। जिन देशों में स्थानीय रूप से कोयला उपलब्ध था, वहां उत्पादकों की उत्पादन लागत कोयले के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के अनुरूप नहीं बढ़ी।
- घ) अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, रूस-यूक्रेन युद्ध अभी जारी है। चूंकि भारत में मेट कोक का आयात घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत से कम कीमतों पर किया जा रहा था, इसलिए आयातक मेट कोक का आयात करने के लिए प्रेरित हुए।
- ङ) कई देशों ने रूस से आयात पर प्रतिबंध लगा दिए, जिससे रूसी कोयले की मांग में गिरावट आई और इसके परिणामस्वरूप रूसी कोयले की कीमतों में गिरावट आई।
- च) रूस से कोयले की आपूर्ति में गिरावट के कारण अन्य देशों से कोयले की मांग में वृद्धि हुई और इसके कारण कोयले की कीमत में वृद्धि हुई।
- छ) ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे देशों में कोकिंग कोल घरेलू स्तर पर उपलब्ध है और ऐसे देशों में उत्पादकों को उत्पादन की लागत में उतनी वृद्धि का सामना नहीं करना पड़ा जितना भारतीय उत्पादकों को करना पड़ रहा है।
- ज) अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आस्ट्रेलिया में कोकिंग कोल के मूल्य का कोई साक्ष्य नहीं दिया है। आस्ट्रेलिया से आयातों का वायदा मूल्य घरेलू उद्योग के कच्चे माल की लागत से कम है।
- झ) चीन में कोकिंग कोल अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से कम मूल्यों पर उपलब्ध है।
- अ) चीन के उत्पादकों ने रूस से सस्ता कोकिंग कोल अंतरराष्ट्रीय कीमतों से कम कीमतों पर आयात करना शुरू कर दिया।
- ट) अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के विपरीत उत्पादकों द्वारा चिह्नित की गई अप्रत्याशित परिस्थिति मेट कोक के वायदा मूल्य में आनुपातिक वृद्धि किए बिना कोयले की लागत में वृद्धि पर आधारित है।
- ठ) भारत में उत्पादन लागत और कोकिंग कोल की घरेलू उपलब्धता वाले देशों में स्थित उत्पादकों के बीच विषमता के कारण, निर्यातक कम कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने में सक्षम थे।
- ड) अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के विपरीत, रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत में कोकिंग कोयले की कीमत में वृद्धि हुई है। तथापि, कोयले की लागत में वृद्धि के अनुरूप संबद्ध वस्तुओं के वायदा मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है।

- जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में हाल की अवधि के बाद गिरावट आई है, वायदा मूल्य में अधिक गिरावट आई है।
- द) माल दुलाई की दरों में वृद्धि के कारण भारतीय उत्पादकों की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई, हालांकि, जिन देशों में घरेलू स्तर पर कोयला उपलब्ध था, वहां उत्पादकों को इस प्रकार की वृद्धि का सामना नहीं करना पड़ा।
- ण) अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, 2022-23 में माल दुलाई दरें अधिक बनी रही।
- त) रूस से चीन की भौगोलिक निकटता के कारण, चीन के उत्पादक रेल मार्गों के माध्यम से रूस से कोयला आयात करने में सक्षम रहे हैं।
- थ) रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद चीन द्वारा रूस से कोयले का आयात तीन गुना हो गया है जबकि अन्य देशों में रूस से आयात में गिरावट आई है।
- द) जबकि भारत ने भी रूस से कोयले का आयात किया है, परंतु भारत में आयात की कीमत चीन में आयात के मूल्य से अधिक है।
- ध) चीन के उत्पादकों ने ऑस्ट्रेलियाई कोकिंग कोयले का लाभ उठाने के लिए इंडोनेशिया में संयंत्र स्थापित किए हैं क्योंकि इंडोनेशिया में ऑस्ट्रेलियाई कोयले की खरीद की लागत चीन की तुलना में कम है।
- ण) इंडोनेशिया ने मुख्य रूप से भारत और वियतनाम को निर्यात किया है।
- प) अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इंडोनेशिया में कोयले की कीमतों के आंकड़े नहीं दिए हैं। इंडोनेशिया ने रूस से अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से कम कीमतों पर कोयले का आयात किया है।
- फ) अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत कि अप्रत्याशित परिस्थिति के साक्ष्य रूस-यूक्रेन युद्ध से पहले की अवधि के हैं, उपलब्ध कराए गए साक्ष्य रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद की अवधि से संबंधित हैं।
- ब) अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत इंडोनेशिया से भी आयात में वृद्धि हुई है, जो किसी भी पाटन रोधी शुल्क के अधीन नहीं थे।
- भ) अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, आयात में वृद्धि एफटीए रियायतों के कारण नहीं है, क्योंकि चीन से आयात भी बढ़ गया है और चीन के लिए कोई एफटीए रियायतें लागू नहीं हैं। इंडोनेशिया से आयात केवल हाल की अवधि में बढ़ा, जबकि रियायत 2019 में दी गई थी।

ज3. अधिकृत अधिकारी की जाँच

80. अप्रत्याशित परिस्थितियों के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार किया गया और अधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित पाया:
81. जीएटीटी का अनुच्छेद XIX जांच अधिकारियों को उन "अप्रत्याशित परिस्थितियों" की जांच करने के लिए बाध्य करता है जिसके कारण आयात में वृद्धि हुई और परिणामतः घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई। इसके अलावा, नियमावली के नियम 9(1) में यह भी प्रावधान है कि आयात में वृद्धि अप्रत्याशित परिस्थितियों के परिणामस्वरूप निम्नानुसार होनी चाहिए:
- “अधिकृत अधिकारी, जांच शुरू होने की तारीख से आठ महीने के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जैसा केंद्र सरकार अनुमति दे सकती है, यह निर्धारित करेगा कि क्या अप्रत्याशित परिस्थितियों के परिणामस्वरूप जांच के अधीन माल के बड़े हुए आयात ने घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाई है या इसका खतरा पैदा किया है, और क्या बड़े हुए आयात और गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे के बीच कोई करणीय संबंध मौजूद है।”*
82. अधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि आयात में वृद्धि केवल उन परिस्थितियों के कारण होनी चाहिए जो अप्रत्याशित या अनपेक्षित थे। इसके अतिरिक्त, दायित्वों का निर्वहन करते समय अर्थात् विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने, डब्ल्यूटीओ के विभिन्न समझौतों के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं का अनुपालन करने का संकल्प लेते समय और शुल्क रियायतें प्रदान करते समय परिस्थिति अप्रत्याशित रही हो।

83. आवेदकों ने बताया है कि वह अप्रत्याशित घटना जिसके कारण भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात में वृद्धि हुई, वह रूस-यूक्रेन युद्ध, माल दुलाई दरों में वैश्विक वृद्धि थी और कई देशों के द्वारा रूस से आयात पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण चीनी उत्पादकों को लाभ हुआ है।

ज 3.1. वैश्विक स्तर पर कोकिंग कोल की उपलब्धता

84. घरेलू उद्योग ने बताया है कि विश्व स्तर पर दो प्रकार के कोयले का खनन किया जाता है। ये थर्मल कोल और कोकिंग कोल हैं। थर्मल कोयला भारत में अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है, परंतु कोकिंग कोयला भारत में उपलब्ध नहीं है। मेट कोक के उत्पादन के लिए कोकिंग कोल की आवश्यकता होती है और थर्मल कोल इस प्रयोजन के लिए उपयोगी नहीं है। मेट कोक का उत्पादन करने के लिए भारतीय उद्योग पूरी तरह से कोकिंग कोल के आयात पर निर्भर है।
85. कोकिंग कोल ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस और इंडोनेशिया जैसे देशों में अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। कोकिंग कोल की कुछ मात्रा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में भी उपलब्ध है।
86. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि कोयले और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की कीमत सीमित उपलब्धता के कारण बदल सकती है और इसे अप्रत्याशित परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तथापि, यह नोट किया गया है कि यद्यपि कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो सकता है, तथापि यह आशा की जाती है कि तदनुसार एवं आनुपातिक रूप से सामान्य बाजार स्थिति में मेट कोक के मूल्य में भी भिन्नता होगी। इसलिए, जांच अवधि के दौरान कोयले और कोक के मूल्य में उतार-चढ़ाव की जांच की गई थी। यह देखा गया है कि वर्तमान जांच में कोकिंग कोल की लागत में वृद्धि हुई थी और मेट कोक की पहुंच कीमत में आनुपातिक वृद्धि नहीं हुई थी। चूंकि मेट कोक की उत्पादन लागत का 90% पर कोकिंग कोल के तहत है, इसलिए कोकिंग कोल की लागत में वृद्धि के अनुरूप मेट कोक के मूल्य में वृद्धि होनी चाहिए थी। तथापि, जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कच्चे माल की लागत और कोक की पहुंच कीमत के बीच अंतर में गिरावट आई है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
आरएम की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
रुझान	अनुक्रमणिका	100	85	133	213
कोक की पहुंच कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
रुझान	अनुक्रमणिका	100	88	157	179
अंतर	₹/एमटी	***	***	***	***
रुझान	अनुक्रमणिका	100	106	339	-79

इस प्रकार यह देखा गया है कि बहुत हाल की अवधि में कोयले और कोक की कीमत के बीच के अंतर में बहुत अधिक गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने कहा कि अंतर में यह गिरावट आयात में वृद्धि और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने का कारण है। घरेलू उद्योग ने आगे कहा है कि अंतर में यह गिरावट इस तथ्य के कारण थी कि विदेशी उत्पादकों के लिए हो रही कोयले की कीमत में वृद्धि की तुलना में भारतीय उद्योग को अधिक वृद्धि का सामना करना पड़ रहा था। चूंकि भारतीय उद्योग की तुलना में इन विदेशी उत्पादकों को कोयले की कीमत में वास्तविक रूप से कम वृद्धि का सामना करना पड़ा, इसलिए ये विदेशी उत्पादक पूर्व की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में निर्यात करने में सक्षम हुए, जिसके कारण आयात में वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई।

ज 3.2. रूस- यूक्रेन युद्ध के कारण कोयले की कीमतों में वृद्धि

87. घरेलू उद्योग द्वारा दी गई जानकारी से पता चलता है कि रूस- यूक्रेन युद्ध के कारण, वैश्विक स्तर पर कोकिंग कोयले की कीमतों में वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रदान किए हैं कि रूस- यूक्रेन युद्ध से पहले रूस कोकिंग कोल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और कोकिंग कोल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक था।
88. रूस- यूक्रेन युद्ध के कारण, कई देशों ने रूस से कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके कारण, इन बाजारों में रूसी कोयले की मांग में गिरावट आई। इसने रूसी उत्पादकों को उन बाजारों में कम कीमतों पर कोयला बेचने के लिए विवश किया जहां से उन्हें मांग प्राप्त हो पा रही थी। साथ ही, इसने कोकिंग कोल के अन्य उत्पादक देशों पर अतिरिक्त बोझ पैदा किया। कई उपभोक्ताओं द्वारा कोयले की खरीद में वैश्विक स्तर पर इस बदलाव के कारण अन्य देशों से

कोकिंग कोल की मांग में वृद्धि हुई। इससे रूस के अलावा अन्य देशों में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कोकिंग कोयले की कीमतों में असमान रूप से उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

89. घरेलू उद्योग ने बताया है कि वह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया से कोयले का आयात करता है। ऊपर वर्णित स्थिति के कारण भारतीय उद्योग के लिए कोयले की उतराई तक की कीमत में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई। आगे यह भी बताया गया है कि कोकिंग कोल, मेट कोक की उत्पादन लागत का लगभग 90% है।
90. यह देखा गया है कि जबकि कोकिंग कोयले की कीमतों में वैश्विक स्तर पर वृद्धि हुई है, कुछ देशों में कोकिंग कोल के मूल्य में उन देशों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई जहां यह घरेलू रूप से उपलब्ध नहीं था अथवा जो रूस से तुलनीय मूल्यों पर कोयला प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। इस प्रकार, आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और चीन के उत्पादकों को भारत के उत्पादकों की उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुरूप तत्संबंधित वृद्धि का सामना नहीं करना पड़ा।
91. भारत में उत्पादन की लागत और जिन देशों में कोकिंग कोल या तो घरेलू रूप से उपलब्ध था, या जो देश तुलनात्मक रूप से कम कीमतों पर रूसी कोयले की पूर्ति में सक्षम थे, उन देशों में स्थित उत्पादकों के बीच असमानता के कारण विदेशी उत्पादक, मुख्य रूप से चीन, इंडोनेशिया और आस्ट्रेलिया के उत्पादक बाजार में भारतीय उद्योग की कीमतों में कटौती करने में और भारतीय बाजार में उल्लेखनीय रूप से अधिक मात्रा में सामग्री का निर्यात करने में सक्षम हुए। परिणामस्वरूप, भारत में घरेलू उद्योग की विक्रय लागत और विक्रय मूल्य से कम कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं का आयात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप आयात में वृद्धि हुई है। आवेदक ने दावा किया है कि उन्होंने माल दुलाई की उच्च लागत का हवाला देते हुए रूस से कोयले का आयात नहीं किया है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
आयात की पहुंच कीमत	₹/एमटी	20,872	18,294	32,830	37,381
विक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
रुझान	अनुक्रमणिका	100	104	157	202
विक्री की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
रुझान	अनुक्रमणिका	100	89	124	197
आयात कीमत और विक्री कीमत के बीच अंतर					
	₹/एमटी	***	***	***	***
रुझान	अनुक्रमणिका	-100	2,203	-215	3,060
विक्री की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
रुझान	अनुक्रमणिका	100	128	-814	691

92. यह देखा गया है कि आयातों की पहुंच कीमत हाल की अवधि से पूर्ववर्ती वर्ष में भारतीय उद्योग के विक्रय मूल्य और विक्री लागत से अधिक थी, पर हाल की अवधि में यह अंतर उल्टा हो गया, जिससे आयात में वृद्धि हुई।
93. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए उन अनुरोधों के संबंध में कि आस्ट्रेलिया में कोकिंग कोल की कीमत में वृद्धि हुई है, अधिकृत अधिकारी का मानना है कि संगत विचार यह है कि मेट कोक की कीमतों में किस प्रकार वृद्धि हुई है और क्या यह वृद्धि कोयले की कीमतों के अनुरूप हुई है। घरेलू उद्योग के कच्चे माल की लागत और ऑस्ट्रेलिया से मेट कोक के आयात की वायदा कीमत की तुलना करने से पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया से आयातित मेट कोक की वायदा कीमत वर्ष 2021-22 को छोड़कर घरेलू उद्योग के कच्चे माल की लागत से कम थी।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
आरएम की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***

रुझान	अनुक्रमणिका	100	85	133	213
ऑस्ट्रेलिया से आयात की पहुंच कीमत	₹/एमटी	17,699	8,816	34,655	36,083
अंतर	₹/एमटी	***	***	***	***
रुझान	अनुक्रमणिका	100	947	-1,390	444

ज 3.3. रूस- यूक्रेन युद्ध के कारण चीन के उत्पादकों को असमान रूप से लाभ हुआ है

94. घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए जानकारी दी है कि चीन के उत्पादकों ने रूस- यूक्रेन युद्ध के बाद रूसी कोयले के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि की है। जबकि चीन के उत्पादकों के पास पहले से ही कम कीमत वाले घरेलू कोयले उपलब्ध हैं, फिर भी उन्होंने कम पहुंच कीमत का लाभ उठाने के लिए रूस से कम कीमतों पर कोयला खरीदा है, जिस मूल्य पर रूसी कोयला चीन के उत्पादकों के लिए विशेष रूप से उपलब्ध था। भारत ने भी रूसी कोयले की अपनी खरीद में वृद्धि की है, पर चीन के उत्पादकों के लिए उपलब्ध लाभ – मात्रा और मूल्य दोनों से भारतीय उद्योग को प्राप्त होने वाला लाभ चीन के उत्पादकों की तुलना में बहुत कम है। इससे चीन के उत्पादकों की उत्पादन लागत कम हुई है जिसके कारण वे भारत जैसे बाजारों में कम कीमतों पर अधिक मात्रा में मेट कोक का निर्यात करने में सक्षम हुए हैं।
95. अधिकृत अधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए इस अनुरोध का संज्ञान लिया है कि चीन में रूसी कोयले के आयात की पहुंच कीमत विश्व के बाकी देशों द्वारा कोकिंग कोल के आयात की पहुंच कीमत से कम थी। इसके अलावा, रूस से चीन में आयातित कोकिंग कोल की मात्रा में रूस- यूक्रेन युद्ध से पूर्व की अवधि की तुलना में 2.8 गुणा की वृद्धि हुई है।

विवरण	यूओएम	युद्ध से पहले*	वर्तमान**
चीन को रूसी निर्यात			
मात्रा	एमटी	***	***
मूल्य	लाख में	***	***
कीमत	₹/एमटी	***	***
चीन में आयात को छोड़कर वैश्विक आयात			
मात्रा	एमटी	60,06,14,011	39,65,30,737
मूल्य	लाख में	5,17,84,161	8,75,97,015
कीमत	₹/एमटी	8,622	22,091

*अप्रैल 2019 – मार्च 2022 पर आधारित वार्षिक आंकड़े

**अप्रैल 2022 - अक्टूबर 2023 पर आधारित वार्षिक आंकड़े

ज 3.4. वैश्विक माल दुलाई दरों में वृद्धि

96. घरेलू उद्योग ने आगे बताया है कि चूंकि यह पूरी तरह से कोकिंग कोल के आयात पर निर्भर है, इसलिए माल दुलाई की दरों में वृद्धि के कारण कोकिंग कोल की खरीद की लागत में काफी वृद्धि हुई। हालांकि, कोकिंग कोल स्थानीय रूप से उपलब्धता वाले देशों में उत्पादकों को इस वृद्धि का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये उत्पादक ऐसी खरीद के लिए समुद्री माल दुलाई के लिए भुगतान नहीं करते हैं।
97. घरेलू उद्योग ने आगे कहा कि जबकि माल दुलाई की लागत 2021-22 और 2022-23 दोनों वर्षों में अधिक थी, वर्ष 2021-22 में माल दुलाई की अधिक लागत ने भारतीय उद्योग को इस कारण से कोई क्षति नहीं पहुँचाई, जिसका कारण था कि इस अवधि में मेट कोक की बढ़ी हुई कीमत ने भारतीय उद्योग को कोयले की बढ़ी हुई लागत को वहन

करने में सक्षम बनाया। हालांकि, 2022-23 में जहाँ इन दो कारकों की वजह से कोयले की लागत में वृद्धि हुई, वहीं कोक की कीमत चीन के उत्पादकों के द्वारा कम कीमतों पर कोक उपलब्ध कराने के कारण नहीं बढ़ी।

98. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने बताया है कि 2021 के बाद माल दुलाई की दरों में गिरावट आई है। तथापि, यह देखा गया है कि कोयले पर माल दुलाई की दरों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा अंकटाड (UNCTAD) की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य बताते हैं कि मई 2022 तक माल दुलाई दरें अधिक रहीं। जबकि, मई 2022 के बाद माल दुलाई की दरों में गिरावट आई, पर रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण 2023 की शुरुआत में एक बार फिर इसमें वृद्धि हुई।

ज 3.5. घरेलू कोयले की उपलब्धता का लाभ और सस्ता रूसी कोयला और माल दुलाई खरीदना चीन का दोहरा लाभ

99. यह नोट किया गया है कि चीन के उत्पादकों ने रूस से कम कीमत वाले कोकिंग कोल का रेल मार्गों के माध्यम से आयात किया है। अतः चीन के उत्पादकों के लिए खरीद की लागत समुद्री मार्गों से कोयले का आयात करने वाले किसी भी अन्य उत्पादक की तुलना में बहुत कम थी।
100. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने बताया है कि यहां तक कि भारतीय उत्पादकों ने रूस से कोयले का आयात किया है और इस प्रकार के आयात से लाभ प्राप्त किया है। अधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने बताया है कि भारत में आयातित रूसी कोयले की वायदा कीमत चीन में आयात की वायदा कीमत से बहुत अधिक थी।

ज 3.6. गैट (GATT) में प्रवेश के समय उठाए गए दायित्व के परिणामस्वरूप

101. दायित्वों के प्रभाव के संबंध में, अर्जेंटीना में 'अपीलीय निकाय - फुटवियर' ने नोट किया कि इस वाक्यांश का सीधा सा अर्थ है कि वास्तविक रूप में यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि आयात करने वाले सदस्य देश ने गैट (GATT) 1994 के तहत शुल्क रियायतों सहित अन्य दायित्वों का निर्वहन किया है। आगे यह नोट किया जाता है कि भारत ने गैट (GATT) के तहत विचाराधीन उत्पाद के संबंध में दायित्वों का निर्वहन किया है। विचाराधीन उत्पाद रियायतों की अनुसूची के तहत सूचीबद्ध उत्पादों में से एक है, और इस प्रकार भारत ने तहत उत्पाद के संबंध में गैट के प्रावधानों के तहत दायित्वों का निर्वहन किया है। इसे देखते हुए, यह माना जाता है कि दायित्वों के प्रभाव के संबंध में अनुच्छेद XIX की आवश्यकता सही है।

ज 3.7. एडीडी, सीमा शुल्क और एफटीए को हटाए जाने के परिणामस्वरूप आयात में वृद्धि

102. **एडीडी को हटाना:** नवंबर 2021 में एडीडी को हटाने के संबंध में उठाए गए मुद्दे और वर्ष 2022-23 में महसूस किए गए इसके प्रभाव के संबंध में, एडीडी चीन और ऑस्ट्रेलिया से आयात के विरुद्ध लागू था। हालांकि, आयात में वृद्धि केवल ऑस्ट्रेलिया और चीन से ही नहीं हुई है, यहां तक कि इंडोनेशिया से भी आयात में बड़ी वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार भारत में आयातों में वृद्धि का कारण एडीडी को हटाया जाना नहीं कहा जा सकता है।
103. **सीमा शुल्क:** अधिकृत अधिकारी का प्रस्ताव है कि आयात में वृद्धि सीमा शुल्क हटाने के कारण नहीं हुई थी। केंद्र सरकार ने दिनांक 21 मई 2022 की अधिसूचना संख्या 26/2022 के माध्यम से भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात पर सीमा शुल्क हटा दिया। हालांकि, इस तरह के सीमा शुल्क को दिनांक 18 नवंबर 2022 की अधिसूचना संख्या 59/2022 के तहत पुनः बहाल कर दिया गया था। अधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि आयात में वृद्धि मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, चीन जन. गण. और इंडोनेशिया से हुई है। सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 41/2019 –सीमा शुल्क के तहत इंडोनेशिया से संबद्ध वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात किया जाता है। इस प्रकार, सीमा शुल्क हटाए जाने से इंडोनेशिया से आयात में वृद्धि नहीं होनी चाहिए थी। इसके अलावा, जापान, कोरिया आरपी और आसियान (ASEAN) के सदस्य देशों जैसे देशों से संबद्ध वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात किया जा सकता है। तथापि, ऐसे देशों से आयातों में अधिक वृद्धि दिखाई नहीं दी है। भारत में आयात मुख्य रूप से पोलैंड और कोलम्बिया जैसे देशों से होता है, तथापि, सीमा शुल्क हटाने के बाद भी ऐसे देशों से आयात में वृद्धि नहीं हुई। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आयातों में वृद्धि उन देशों से हुई है जिन देशों में कच्चा माल, अर्थात् कोकिंग कोल की घरेलू स्तर पर उपलब्धता थी न कि उन देशों से जहां से संबद्ध वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात किया जा सकता है।
104. **एफटीए:** अधिकृत अधिकारी का प्रस्ताव है कि आयात में वृद्धि लागू एफटीए के कारण नहीं हुई है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि आयात में अधिक वृद्धि ऑस्ट्रेलिया, चीन जन. गण. और इंडोनेशिया से हुई है। दिनांक 31 दिसंबर 2019 की अधिसूचना संख्या 41/2019 – सीमा शुल्क के तहत संबद्ध वस्तुओं का इंडोनेशिया से शुल्क मुक्त आयात किया जा सकता है। जबकि वर्ष 2020 में सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया था, आयात में वृद्धि हाल की अवधि के

दौरान ही हुई है और इसलिये भारत में आयात में वृद्धि का कारण एफटीए को नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त, भारत और चीन जन. गण. ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में मुक्त व्यापार समझौता नहीं किया है। इस प्रकार, चीन जन. गण. से आयात में वृद्धि भी एफटीए के तहत मिलने वाली रियायतों के परिणामस्वरूप नहीं हुई है।

ज 3.8. इस्पात की मांग में तेजी के कारण आयात में वृद्धि

105. अधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि इस्पात की मांग में वृद्धि के कारण भारत में आयात में वृद्धि हुई है। अधिकृत अधिकारी का प्रस्ताव है कि भारत में व्यापारी क्षमता भारत में व्यापारी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। यह देखते हुए कि भारतीय उद्योग 'कम क्षमता उपयोग' पर काम कर रहा है, बढ़ी हुई मांग को घरेलू उद्योग द्वारा पूरा किया जा सकता था। इसलिए, भारत में मांग में वृद्धि आयात में वृद्धि का कारण नहीं हो सकती है, खासकर जब भारतीय उद्योग के पास पर्याप्त क्षमता है और यह 'कम क्षमता उपयोग' पर काम कर रहा है।

विवरण	इकाई	2022-23
व्यापारी की क्षमता	एमटी	***
व्यापारी की माँग	एमटी	61,86,991
अंतर	एमटी	***

106. इसके अलावा, पिछले वर्ष की तुलना में सबसे हाल की अवधि के दौरान भारत में मांग में 19% की वृद्धि हुई है, तथापि आयात में 40% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार, आयात में वृद्धि मांग में वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
भारत में आयात	एमटी	28,34,905	24,32,580	25,11,786	35,15,654
भारत में आयात	सूचीबद्ध	100	86	89	124
भारत में मांग	एमटी	53,82,045	45,64,092	52,02,880	61,86,991
भारत में मांग	सूचीबद्ध	100	85	97	115

107. रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात में वृद्धि अप्रत्याशित परिस्थितियों के परिणामस्वरूप हुई है, एवं ऊपर उल्लिखित अन्य कारकों के कारण नहीं हुई है।

गंभीर क्षति और करणीय संबंध

झ. घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति

झ1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

108. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे।

- क) कुल क्षमता की सूचना विश्वसनीय नहीं है क्योंकि क्षति की अवधि के दौरान कुल भारतीय क्षमता स्थिर रही है, घरेलू उद्योग की क्षमताओं में वृद्धि हुई है।
- ख) वर्ष 2021-22 और 2022-23 के बीच घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में केवल 1% की गिरावट आई, जबकि 2019-20 की तुलना में हाल की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री और लाभ में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट केवल क्षमताओं में वृद्धि के कारण आई है।
- ग) लाभप्रदता के मामले में घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष की तुलना में हाल की अवधि के दौरान बेहतर प्रदर्शन किया है। अधिकृत अधिकारी ने मेट्रोनिडाजोल के आयात में पाटन रोधी जांच को बंद कर दिया क्योंकि जांच की अवधि के उत्तरार्द्ध के दौरान ही घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई और यह क्षति की अवधि के दौरान लाभप्रद रहा।
- घ) जबकि 2021-22 की तुलना में पहुंच कीमत में 15% की वृद्धि हुई, घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत में 66% की वृद्धि हुई। अतः घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत में अत्यधिक वृद्धि के कारण कीमतों में कटौती हुई है।

- ड) चूंकि वर्ष 2019-20 और 2021-22 में कीमत में कटौती की दर नकारात्मक थी, इसलिए घरेलू उद्योग कीमत में कटौती के कारणों से क्षति का दावा नहीं कर सकता है।
- च) घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं क्योंकि आयात की पहुंच कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत, दोनों में वृद्धि हुई है लेकिन कीमतों में कटौती सकारात्मक हो गई है।
- छ) कोई मूल्य ह्रासकारी/ न्यूनकारी नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग के बिक्री की लागत वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 में बिक्री कीमत में गिरावट से अधिक कम हो गई, इसके अलावा, बिक्री कीमत वर्ष 2021-22 के दौरान विक्रय की लागत में वृद्धि से अधिक बढ़ गयी।
- ज) आवेदकों द्वारा उत्पादन लागत में चिह्नित की गई वृद्धि भारत में आयात के कारण नहीं हुई थी।
- झ) आवेदक जांच की अवधि में प्रदर्शन के साथ वर्ष 2020-21 और 2021-22 में प्रदर्शन की तुलना कर रहे हैं, हालाँकि, कोविड-19 के प्रभाव के कारण वर्ष 2020-21 और 2021-22 की अवधि असामान्य थी, जो कि आवेदकों की वार्षिक रिपोर्ट से स्पष्ट है। सभी आवेदकों ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आधार वर्ष से बेहतर प्रदर्शन किया है।
- अ) आयात की पहुंच कीमत वर्ष 2022-23 के दौरान सबसे अधिक थी और इस प्रकार, इसे घरेलू उद्योग को हुए नुकसान का कारण होने का दावा नहीं किया जा सकता है। वर्ष 2020-21 में पहुंच कीमत सबसे कम थी, पर लाभप्रदता सबसे अधिक थी।
- ट) अप्रैल-दिसंबर 2022 की तुलना में 2022-23 में घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों में सुधार हुआ है। इस प्रकार घरेलू उद्योग एक सकारात्मक दिशा में जा रहा है।
- ठ) अधिकृत अधिकारी को सबसे हाल की अवधि के दौरान महीने दर महीने घरेलू उद्योग की लाभप्रदता का विश्लेषण करना चाहिए। घरेलू उद्योग ने अप्रैल 2023 - दिसंबर 2023 के तीन महीनों में पर्याप्त लाभ अर्जित किया है।
- ड) रक्षोपाय जांच में मूल्य प्रभाव असंगत है और इसलिए आयातों के मूल्य निर्धारण व्यवहार पर विचार नहीं किया जा सकता है। रक्षोपाय नियमों में कहा गया है कि जब आयातों में वृद्धि के अलावा कोई अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा हो तो ऐसी क्षति का कारण आयात नहीं होगा।
- ढ) आवेदकों ने यह दर्शाने के लिए साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं कि चीन और आस्ट्रेलिया के बाजारों में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप नहीं बढ़ीं।
- न) आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के बीच कोई काणात्मक संबंध नहीं है। घरेलू उद्योग ने 2022-23 में क्षमता विस्तार किया और मूल्यह्रास के साथ-साथ वेतन और मजदूरी में वृद्धि हुई। कार्य-कारण का निर्धारण ब्याज, मजदूरी और मूल्यह्रास के स्व-प्रवृत्त प्रभावों को छोड़कर किया जाना चाहिए।
- त) पोलैंड से आयात का अलग से विश्लेषण होना चाहिए और इन आयातों को चीन से आयात के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कारणात्मक संबंध का अलग से मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि पोलैंड से आयात के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंची है।
- थ) पोलैंड से आयात को बाजार हिस्से में क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, जिसमें घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2% की गिरावट की तुलना में 18% की गिरावट आई है।
- द) आवेदकों को, यदि कोई क्षति हुई है, तो वह कोयले और माल ढुलाई की दरों में वृद्धि, विनिमय दरों में वृद्धि, ब्याज और मूल्य-ह्रास के कारण है न कि आयात के कारण।
- ध) महालक्ष्मी एन्नोर कोक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, विमला फ्यूल्स एंड मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड और जीनस पेपर एंड कोक लिमिटेड की क्रेडिट रेटिंग से पता चलता है कि उन्होंने वित्त वर्ष 2023 के दौरान लाभ अर्जित किया है।
- न) बेहतर कीमत प्राप्ति के कारण भारत 2021 में मेट कोक का शुद्ध निर्यातक बन गया है। अधिकृत अधिकारी को क्षति के कारण का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग की निर्यात प्रवृत्ति की जांच करनी चाहिए।

- प) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े अविश्वसनीय हैं क्योंकि 2021-22 में घरेलू उद्योग की क्षमता में 2% की वृद्धि हुई है, जबकि, नियोजित पूंजी में 50% की वृद्धि हुई है। जहाँ वर्ष 2022-23 में क्षमता में वृद्धि हुई, नियोजित पूंजी में गिरावट आई।
- फ) आवेदकों ने मौखिक सुनवाई के दौरान दिए गए आश्वासन के अनुसार जांच की अवधि के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं।
- ब) आवेदकों ने अप्रैल 2022-मार्च 2023 के संशोधित आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं।

झ2. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

109. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए।

- क. भारत में आयात में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंची है।
- ख. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, सबसे हालिया अवधि के दौरान किए गए आयात 2019-20 में किए गए आयात से भी अधिक है। यह अवधि कोविड- 19 से प्रभावित नहीं थी। अप्रैल-दिसंबर 2023 में आयात में और अधिक वृद्धि हुई है।
- ग. आयातों में भारत में घरेलू उत्पादन और मांग के सापेक्ष तथा निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है।
- घ. भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से और मांग में वृद्धि का स्थान आयातों द्वारा ले लिया गया है। जबकि क्षति की अवधि में मांग में 13% की वृद्धि हुई है, पर आयात में 46% की वृद्धि हुई है।
- ङ. जबकि भारतीय उद्योग ने पिछले वर्ष भारत में मांग के अधिकांश हिस्से को पूरा किया, पर हाल की अवधि के दौरान भारतीय बाजार के अधिकांश हिस्से पर आयात के द्वारा कब्जा कर लिया गया है।
- च. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के विपरीत, पोलैंड से आयात को अन्य आयातों से अलग नहीं माना जा सकता है।
- छ. इसके बावजूद कि घरेलू उद्योग ने वित्तीय घाटा सहकर विक्रय किया हो, आयात के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही थी।
- ज. सबसे हाल की अवधि के दौरान आयातों का मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य के साथ-साथ विक्रय की लागत से भी कम था।
- झ. कम कीमत पर होने वाले आयात के कारण, घरेलू उद्योग को बिक्री की लागत से कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- ञ. एक सामान्य व्यापार चक्र में, कोकिंग कोल की कीमत में बदलाव के साथ मेट कोक की कीमत भी बदल जाती है। हालांकि, वर्ष 2022-23 में संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत में कोकिंग कोल की कीमत में हुई वृद्धि के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। कच्चे माल की लागत और संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत के बीच अंतर में गिरावट आई है।
- ट. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री भारत में क्षमताओं अथवा मांग में वृद्धि के अनुरूप नहीं बढ़ी है, जबकि उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।
- ठ. सबसे हाल की अवधि के बाद मालसूची बढ़ने और बाजार हिस्से में कमी के कारण दो आवेदकों के संयंत्र बंद हो गए थे।
- ड. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में इसके विक्रय लागत के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है।
- ढ. सबसे हाल की अवधि में घरेलू उद्योग को घाटा, नकद घाटा हुआ है और निवेश पर नकारात्मक रिटर्न दर्ज किया गया है। सबसे हाल की अवधि के बाद के दौरान भी घरेलू उद्योग को घाटा, नकद हानि हुई है और निवेश पर नकारात्मक आय हुई है।
- ण. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमतों पर आयातों के बढ़ने के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता को काफी क्षति पहुंची है।

- त. जबकि वर्ष 2022-23 के दौरान पहुंच कीमत में बढ़ोत्तरी हुई, पर यह बढ़ोत्तरी घरेलू उद्योग की कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि की तुलना में बहुत कम थी।
- थ. मेट कोक की वायदा कीमत को कोकिंग कोल की कीमत से अलग करके नहीं लिया जा सकता क्योंकि कोकिंग कोल का हिस्सा संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के 90% के बराबर है।
- द. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने हाल की अवधि से तुलना करने में एक सुसंगत दृष्टिकोण का पालन नहीं किया है, कुछ मापदंडों की तुलना पिछले वर्ष और अन्य की तुलना आधार वर्ष से की गई है।
- ध. आयात में उछाल 2019-20 में भी हुआ था, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति उठानी पड़ी थी। घरेलू उद्योग उस समय अधिकृत अधिकारी तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि बाद का वर्ष कोविड से प्रभावित था। चूंकि आयात में वृद्धि हाल ही में हुई है, इसलिए आयात में ऐसी वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को भी हाल ही में क्षति हुई है।
- न. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के विपरीत, आवेदकों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में प्रदर्शन में गिरावट दर्शाती है।
- प. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, जांच के बाद की अवधि के लिए आंकड़े प्रदान किए गए हैं और दिनांक 25 जनवरी 2024 को ईमेल द्वारा परिचालित किए गए हैं।
- फ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उद्योग ने अप्रैल 2022 - मार्च 2023 का संशोधित आंकड़ा दिनांक 3 अगस्त 2023 को प्रस्तुत किया है।
- ब. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उद्योग के लाभों में गिरावट ब्याज और मूल्यास लागत में वृद्धि से अधिक है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के ईबीआईडीटीए में गिरावट आई है। इस प्रकार, क्षति ब्याज और मूल्यहास लागत में वृद्धि के कारण नहीं है।
- भ. चूंकि अधिकृत अधिकारी ने घरेलू उद्योग के आंकड़ों का सत्यापन किया है, इसलिए प्रदान की गई सूचना की विश्वसनीयता के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया जा सकता है।
- म. वर्तमान मामले के तथ्य अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भरोसा किए गए मेट्रोनिडाजोल पर पाटन रोधी जांच से अलग हैं, जिसमें अधिकृत अधिकारी ने माना कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में केवल अस्थायी रूप से गिरावट आई है, लेकिन इसने जांच की अवधि के दौरान पर्याप्त लाभ अर्जित किया है। हालांकि मौजूदा जांच में घरेलू उद्योग को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है।
- य. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, कानून के तहत महीने- वार लाभप्रदता विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- कक. किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग कंपनी के समग्र प्रदर्शन पर निर्भर करती है न कि संबद्ध वस्तुओं के प्रदर्शन से संबंधित है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा चिह्नित की गई कंपनियां बहु-उत्पाद कंपनियां हैं और अन्य देशों को निर्यात करने में शामिल हैं।
- खख. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, नियोजित पूंजी में वृद्धि हुई है क्योंकि वर्ष 2021-22 में एक नए उत्पादक ने उत्पादन शुरू किया है।
- गग. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, क्षति विनिमय दरों के कारण नहीं हो सकती क्योंकि कोक और कोयला दोनों इससे समान रूप से प्रभावित थे।
- घघ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, भारत संबद्ध वस्तुओं का शुद्ध आयातक है न कि निर्यातक। किसी भी मामले में, आवेदकों ने कंपनी के प्रदर्शन को केवल घरेलू प्रचालन के संबंध में अलग किया है।

अधिकाृत अधिकारी द्वारा जाँच

110. अधिकृत अधिकारी के द्वारा यह जांच करने की जरूरत है कि क्या उत्पाद के बढ़े हुए आयातों के कारण समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पादों के घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है अथवा होने का खतरा है। अधिनियम की धारा 9क (4) के अनुसार, गंभीर क्षति का अर्थ है ऐसी क्षति जो घरेलू उद्योग की स्थिति में उल्लेखनीय समग्र हानि पहुंचाए, जबकि गंभीर क्षति के खतरे का अर्थ है गंभीर क्षति का स्पष्ट और आसन्न खतरा। मात्रात्मक प्रतिबंध नियमावली के नियम 8 (क) में क्षति के निर्धारण के लिए निम्नानुसार प्रावधान हैं -

"अधिकृत अधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण करेगा:

(क) इस बात के निर्धारण के लिए होने वाली जांच में कि क्या आयात में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है या इसका खतरा है, अधिकृत अधिकारी उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले वस्तुपरक और मात्रात्मक प्रकृति के सभी संगत कारकों, विशेष रूप से, निरपेक्ष और सापेक्ष शर्तों में संबद्ध वस्तुओं के आयात में वृद्धि की दर और राशि, बड़े हुए आयात के द्वारा कब्जा किया गया घरेलू बाजार का हिस्सा, विक्रय के स्तर में बदलाव, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग, लाभ और हानि, और रोजगार का मूल्यांकन करेंगे;"

111. उपरोक्त को देखते हुए, क्षति से संबंधित मापदंडों का विश्लेषण नीचे किया गया है।

अ3.1. मांग/ खपत का आकलन

112. वर्तमान जांच के उद्देश्य से, भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों द्वारा उत्पादित उत्पाद की घरेलू बिक्री और भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात के योग के रूप में निर्धारित किया गया है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
घरेलू उद्योग बिक्री	एमटी	***	***	***	***
रुझान	अनुक्रमणिका	100	90	93	106
अन्य उत्पादकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
रुझान	अनुक्रमणिका	100	80	113	104
भारत में आयात (डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार)	एमटी	28,34,905	24,32,580	25,11,786	35,15,654
मांग	एमटी	***	***	***	***
रुझान	अनुक्रमणिका	100	85	97	115
स्थापित क्षमताएँ	एमटी	***	***	***	***
रुझान	अनुक्रमणिका	100	100	100	100

113. यह देखा गया है कि हाल की अवधि में उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, सबसे हाल की अवधि के दौरान मांग किसी भी अन्य अवधि के दौरान मांग की तुलना में अधिक थी। हालांकि, संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा में इतनी उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी कि जहाँ पिछले वर्ष की तुलना में सबसे हाल की अवधि में मांग में 19% की वृद्धि हुई, आयात में 40% की वृद्धि हुई, जो कि मांग में वृद्धि की संपूर्णता से अधिक है। इस प्रकार, खपत में वृद्धि को संबद्ध वस्तुओं के आयात के द्वारा स्पष्ट किया गया था।

अ3.2. निरपेक्ष और सापेक्ष रूप में आयात में वृद्धि की दर और राशि

114. बड़े हुए आयात के संबंध में ऊपर उल्लिखित सूचना के विश्लेषण और नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट होता है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात में निरपेक्ष रूप से और भारत में उत्पादन और खपत दोनों में वृद्धि हुई है। यह देखा गया है कि क्षति की अवधि में आयात में वृद्धि की दर और राशि दोनों महत्वपूर्ण हैं।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
निरपेक्ष रूप से आयात	एमटी	28,34,905	24,32,580	25,11,786	35,15,654
आयात में वृद्धि	एमटी		(4,02,325)	79,206	10,03,868
आयात में वृद्धि की दर	%		-14%	3%	40%

अ.3.3. बाज़ार हिस्सा

115. घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों और विचाराधीन उत्पाद के आयात का बाज़ार हिस्सा इस प्रकार था।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
रुझान	अनुक्रमणिका	100	106	94	89
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
रुझान	अनुक्रमणिका	100	93	117	90
समग्र रूप से भारतीय उद्योग	%	***	***	***	***
रुझान	अनुक्रमणिका	100	100	111	91
भारत में आयात	%	53%	53%	48%	57%
मांग	%	100%	100%	100%	100%

यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के साथ-साथ भारतीय उद्योग का बाज़ार हिस्सा 2019-20, 2020-21 और 2021-22 की तुलना में 2022-23 में समग्र रूप से घट गया। हाल की अवधि में भारत में आयात के बाज़ार हिस्से में काफी वृद्धि हुई है। यह देखा गया है कि आयातों ने भारतीय उद्योग के बाज़ार हिस्से को छीन लिया है।

116. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि भारतीय उद्योग देश में उत्पाद की पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता रखता है। तथापि, यह देखा गया है कि अधिकांश मांग आयातों के माध्यम से पूरी की गई थी, जबकि भारतीय उद्योग ने अल्पांश हिस्से की पूर्ति की।

117. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि पोलैंड से आयात कम हो गया है और इस प्रकार यह बाज़ार हिस्से में गिरावट का कारण नहीं हो सकता है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि सभी स्रोतों से विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में क्षति की जांच की जानी अपेक्षित है न कि किसी विशेष देश से आयात के संबंध में। इस प्रकार, पोलैंड से आयात को अन्य सभी देशों से आयात के साथ समेकित रूप से देखा जाना चाहिए।

अ. 3.4 कीमत कटौती

118. इस बात की जांच की गई कि क्या संबद्ध उत्पाद के आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रखी गयी थी और वे बाज़ार में कीमत कटौती कर रहे हैं। नीचे दी गई तालिका वास्तविक स्थिति को दर्शाती है।

विवरण	इकाई	राशि
निवल बिक्री प्राप्ति	₹/मी.टन	***
पहुंच कीमत	₹/मी.टन	37,381
कीमत कटौती	₹/मी.टन	***
कीमत कटौती	%	***%
कीमत कटौती	रेंज	10-20

119. यह देखा गया है कि आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे थे। कीमत कटौती महत्वपूर्ण और सकारात्मक है।

120. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है पिछले वर्षों में कीमत कटौती ऋणात्मक थी। यह नोट किया गया है कि 2019-20 और 2021-22 के दौरान कीमत कटौती ऋणात्मक थी। तथापि, सबसे हाल की अवधि के दौरान, आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती करना आरंभ किया था। इससे आयातित वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई जिससे आयातों में वृद्धि हुई और इसने घरेलू उद्योग की मांग और बाज़ार हिस्से पर एक तनाव सृजित किया।

झ. 3.5. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

121. यह जांच की गई कि क्या संबद्ध वस्तुओं के आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास/ या न्यूनीकरण कर रहे थे। इस प्रयोजन हेतु, क्षति अवधि में लागतों और कीमतों में प्रवृत्ति की जांच की गई। नीचे दी गई तालिका तथ्यात्मक स्थिति को दर्शाती है :-

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बिक्रियों की लागत	₹/मी.टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	89	124	197
पहुंच कीमत	₹/मी.टन	20,872	18,294	32,830	37,381
	सूचीबद्ध	100	88	157	179
बिक्री कीमत	₹/मी.टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	104	157	202

यह देखा गया है कि 2020-21 में, घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत में गिरावट आई है। तथापि, घरेलू उद्योग इस अवधि में अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि करने में सक्षम था क्योंकि इस अवधि में आयातों में गिरावट आई थी। हालांकि, आयातों की कीमत निम्न थी, फिर भी ऐसे आयातों ने कोविड से संबंधित व्यावधानों के कारण घरेलू उद्योग की मात्राओं या कीमतों पर दबाव सृजित नहीं किया। तत्पश्चात 2021-22 में, घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत और बिक्री कीमत, दोनों में वृद्धि हुई। तब भी, बिक्री कीमत में वृद्धि बिक्रियों की लागत में वृद्धि की अपेक्षा अधिक थी क्योंकि निर्यात कीमतें घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित किए गए स्तरों से भी अधिक थी। वास्तव में घरेलू उद्योग खपत में वृद्धि के समानुपात में अपनी मात्राओं में वृद्धि करने में सक्षम था। 2022-23 के दौरान, बिक्रियों की लागत में 58 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। तथापि, आयातित वस्तुओं के बड़े हुए अंतःप्रवाह ने घरेलू उद्योग को बिक्रियों की लागत के साथ-साथ अपनी कीमतों में वृद्धि करने से रोका। सस्ती कीमतों पर बाजार में प्रवेश कर रही वस्तुओं की विशाल मात्रा ने घरेलू उद्योग को लागतों में वृद्धि करने से रोका है। घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में केवल 29 प्रतिशत तक वृद्धि करने में सक्षम था। इसलिए, सर्वाधिक हाल की अवधि में, आयातों ने कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित किया है, जो अन्यथा घटित हुई होती।

झ.3.6 कच्चे माल की लागत और पहुंच कीमत की तुलना

122. चूंकि, कोकिंग कोल संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की प्रमुख लागत के लिए उत्तरदायी है और उत्पादन की लागत के लगभग 90 प्रतिशत हिस्से को नियंत्रित करता है, यह जांच की गई कि क्या संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत कोकिंग कोल की लागत के साथ-साथ बढ़ी है -

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
आर.एम की लागत	₹/मी.टन	***	***	***	***
रुझान	अनुक्रमणिका	100	85	113	213
कोक की पहुंच कीमत	₹/मी.टन	20,872	18,294	32,830	37,381
अंतर	₹/मी.टन	***	***	***	***
रुझान	अनुक्रमणिका	100	106	339	-79
मार्क-अप (अधिक मूल्य निर्धारण)	%	***	***	***	***
रुझान	अनुक्रमणिका	100	117	208	-42

123. यह देखा गया है कि क्षति अवधि में कोकिंग कोल की कीमत में वृद्धि हुई है। भारत में मेट कोक की पहुंच कीमत में भी वृद्धि हुई है। हालांकि, घरेलू उद्योग के कच्चे माल की लागत और मेट कोक की पहुंच कीमत के बीच अंतर में अत्यधिक कमी आई है। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया है कि पिछले वर्षों में ***-*** प्रतिशत के मार्क-अप की

तुलना में, कच्चे माल की लागत और कोक की पहुंच कीमत के बीच मार्क-अप सर्वाधिक हाल की अवधि में ऋणात्मक हो गया है। यह विचार करते हुए कि किसी उत्पादक को परिवर्तन लागतों, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों को वहन करना होता है और एक उचित लाभ भी सामान्यतः अर्जित करना होता है, किसी बाजार को बनाए रखने के लिए एक ऋणात्मक मार्क-अप (अधिक मूल्य निर्धारण) पूरी तरह से अपर्याप्त है।

झ.3.7 क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियां

124. क्षति अवधि में स्थापित क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण किया गया था –

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
क्षमताएं	मी.ट.	***	***	***	***
रुझान	अनुक्रमणिका	100	100	103	110
उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***
रुझान	अनुक्रमणिका	100	80	113	104
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
रुझान	अनुक्रमणिका	100	80	110	95
घरेलू बिक्रियां	मी.ट.	***	***	***	***
रुझान	अनुक्रमणिका	100	90	93	106

यह देखा गया है कि –

- क. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमताओं में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, कुछ घरेलू उत्पादकों ने अपनी क्षमताओं को स्थापित किया है या उनमें वृद्धि की है। यह देखा गया है कि देश में उत्पाद की मांग में 15 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमताओं में 10 प्रतिशत की वृद्धि की है।
- ख. घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियों में 2020-21 के दौरान गिरावट आई है। यह इस अवधि के दौरान कोविड और मांग में गिरावट को देखते हुए थी।
- ग. 2021-22 के दौरान, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों में सुधार हुआ है। इस अवधि में आयातों की पहुंच कीमत सापेक्ष रूप से उच्च थी। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग अपनी बिक्रियों और परिणामस्वरूप उत्पादन और क्षमता उत्पादन में वृद्धि करने में सक्षम था।
- घ. 2022-23 में, वह अवधि जब उत्पादन के आयातों में उछाल आया था, तब घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता, उपयोग और घरेलू बिक्रियों ने दुबारा क्षति का सामना किया। जहां घरेलू उद्योग की बिक्रियों में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, ऐसी वृद्धि मांग में वृद्धि के अनुरूप नहीं थी जिसमें 22 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई थी।

झ. 3.8 मालसूची

125. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति निम्नानुसार थी :-

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
प्रारंभिक मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***
औसत मालसूची	मी.ट.	93,478	71,287	82,241	1,09,285
रुझान	अनुक्रमणिका	100	76	88	117

यह देखा गया है कि क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग में वृद्धि हुई है। मालसूचियों में हाल की अवधि में, पिछले वर्ष की तुलना में 33% की और आधार वर्ष की तुलना में 17% की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की मालसूची की धारण अवधि में भी, आधार वर्ष की तुलना में 10% तक की वृद्धि हुई है।

झ.3.9 रोजगार और उत्पादकता

126. घरेलू उद्योग की रोजगार और उत्पादकता स्थिति निम्नानुसार थी :-

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
रुझान	अनुक्रमणिका	100	94	123	116
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.ट./सं.	***	***	***	***
रुझान	अनुक्रमणिका	100	85	92	89
प्रति दिन उत्पादकता	मी.ट./दिन	***	***	***	***
रुझान	अनुक्रमणिका	100	80	114	135

यह देखा गया है कि क्षति अवधि में कर्मचारियों की संख्या और दैनिक उत्पादकता में वृद्धि हुई है। प्रति कर्मचारी उत्पादकता में गिरावट आई है क्योंकि बड़ी हुई क्षमताओं और रोजगार के साथ-साथ उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है।

झ.3.10 लाभ/हानि

127. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता निम्नानुसार थी :-

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
लाभ/हानियां	₹/मी.टन	(***)	***	***	(***)
	सूचीबद्ध	(100)	252	646	(79)
नकद लाभ	₹/मी.टन	(***)	***	***	(***)
	सूचीबद्ध	(100)	658	1,493	(36)
निवेश पर आय	%	(***)	***	***	(***)
	सूचीबद्ध	(100)	1,352	1,941	(45)

128. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इसने नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड ("एन आई एन एल") द्वारा ब्लास्ट फर्नेस को बंद किए जाने के कारण 2019-20 में क्षति और वित्तीय हानियों का सामना किया है। एन आई एन एल एक सरकारी क्षेत्र का लौह और इस्पात विनिर्माता था और इसका स्वयं का कैप्टिव कोकिंग कोल संयंत्र था। हालांकि, एन आई एन एल इसे होने वाली हानि को रोकने के लिए, स्टील प्लांट को बंद किए जाने के बाद भी, कोक ओवन संयंत्र का संचालन करने के लिए विवश था। अतः इसके पास व्यापारी बाजार में मेट कोक की बिक्री करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। एम एम टी सी और एन आई एन एल ने निम्न कीमतों पर व्यापारी बाजार में मेट कोक की बिक्री करना आरंभ कर दिया जिस कारण बाजार में कीमत में गिरावट आनी शुरू हो गई। प्रस्तुत की गई कीमत अत्यधिक कम थी जिस कारण उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए निम्न कीमतों पर बिक्री करने का दबाव था।

129. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने पिछले वर्ष की तुलना में तत्काल हाल की अवधि में वित्तीय हानियों का सामना किया है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में तेजी से गिरावट आई है। जहां पिछले वर्ष घरेलू उद्योग लाभ, नकद लाभ और निवेशों पर पर्याप्त आय अर्जित कर रहा था, हाल की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में तीव्र गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने नकद हानियां और नियोजित पूंजी पर ऋणातमक आय वहन की है।

130. कुछ विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने निवेदन किया है कि घरेलू उद्योग को हानियां ब्याज और ह्रासात्मक लागतों में वृद्धि के कारण है। हालांकि, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में मूल्य ह्रास और ब्याज लागत में वृद्धि की तुलना में कहीं अधिक गिरावट आई है। जहां मूल्य ह्रास और ब्याज लागत में 783 लाख रूपए और 1906 लाख रूपए की वृद्धि हुई है, लाभप्रदता में वर्ष 2021-22 से हाल की अवधि में 55,656 लाख रूपए की गिरावट आई है। इस प्रकार, लाभप्रदता में गिरावट उक्त लागतों में वृद्धि के कारण नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की ई बी आई डी टी ए में 2021-22 की तुलना में और इस अवधि में आयातों में उछाल के साथ, हाल की अवधि में तेजी से गिरावट आई है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
ईबीआईडीटीए	₹/मी.टन	***	***	***	***
रुझान	अनुक्रमणिका	100	1,128	2,203	147
	लाख रूपए	***	***	***	***
रुझान	अनुक्रमणिका	100	1,012	2,040	156

झ. 3.11 आयातों के कारण संयंत्र का बंद होना

131. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि मालसूची के एकत्र हो जाने और बाजार हिस्से की कमी के कारण दो याचिकाकर्ताओं द्वारा संयंत्रों को बंद करना पड़ा था। उत्पादक बाजार में अपने उत्पाद की बिक्री करने में अक्षम थे और उन्हें उत्पाद को पूरी तरह से बंद करने के लिए विवश होना पड़ा था।

ञ. गैर-आरोपण विश्लेषण

132. नियमावली के नियम 8(ख) के अनुसार, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यह निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है कि क्या बढ़े हुए आयात गंभीर क्षति का कारण थे अथवा घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का खतरा था। इसलिए, कारणात्मक संबंध मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु, घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले वस्तुनिष्ठ और मात्रात्मक प्रकृति से सभी प्रासंगिक कारकों की जांच की गई और यह सुनिश्चित किया गया कि क्या संबद्ध वस्तुओं के बढ़े हुए आयात घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का प्राथमिक कारण थे। इसके अतिरिक्त, इस बात की जांच की गई कि क्या बढ़े हुए आयातों के अतिरिक्त अन्य कारक भी घरेलू उद्योग को क्षति का कारण थे। जहां कोई निर्धारित "अन्य कारक" उपस्थित नहीं है, जिनका मूल्यांकन किए जाने की जरूरत है, इस बात की जांच की गई कि क्या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, निर्यात निष्पादन, उत्पादकता, मांग में संकुचन, उत्पाद का संभावित पाटन जैसे कारक घरेलू उद्योग को क्षति का मुख्य कारण थे।

ञ.1 मांग में संकुचन

133. यह नोट किया गया है कि देश में संबद्ध वस्तुओं की मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है।

ञ.2 खपत पद्धति

134. किसी हितबद्ध पक्षकार ने यह आरोप नहीं लगाया है कि वस्तुओं की खपत पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है।

ञ.3 प्रतिस्पर्धा और बाजार प्रतिबंधित पद्धतियों की स्थितियां

135. जांच यह नहीं दर्शाती है कि प्रतिस्पर्धा या व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियों की स्थितियों में परिवर्तन हुआ है।

ञ.4 प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

136. यह देखा गया है कि प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

ञ.5 घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

137. क्षति विश्लेषण केवल विचाराधीन उत्पाद के लिए और घरेलू निष्पादन तक सीमित है।

138. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि अन्य भारतीय उत्पादकों के निष्पादन में सुधार हुआ है और इसलिए, भारतीय उद्योग क्षति का सामना नहीं कर रहा है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पादकों की क्रेडिट रेटिंग पर भरोसा किया है। यह नोट किया गया है कि क्रेडिट रेटिंग विचाराधीन उत्पाद के बारे में उत्पादक के निष्पादन

के संबंध में सही स्थिति उपलब्ध नहीं कराते। इसके अलावा, रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य दर्शाते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उल्लिखित कुछ उत्पादक उत्पाद का निर्यात करने में संलग्न हैं। चूंकि घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया है।

समायोजन योजना और सार्वजनिक हित

ट. समायोजन योजना

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

139. समायोजन योजना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे :-

- (क) आवेदकों ने कोई समायोजन योजना उपलब्ध नहीं कराई है। समायोजन योजना की जरूरत के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है चाहे उपायों के लिए एक वर्ष से कम अवधि के लिए अनुरोध किया गया है। बहुल संख्या में रक्षोपाय जांचों में, जिनमें थैलिक एन हाइड्राइड, कोल्ड रोल्ल्ड प्लेट प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, बिना गढ़ा गया एल्यूमिनियम और लचीले स्लैबस्टॉक पॉलीथीन की गैर-मिश्रित सिलिलियों पर की गई जांचें शामिल हैं प्राधिकृत प्राधिकारी ने माना है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई समायोजन योजना व्यवहार्य नहीं थी अथवा उसमें साक्ष्य की कमी थी।
- (ख) किसी समायोजन योजना के अभाव में, जांच की शुरुआत गलत है क्योंकि उपलब्ध कराए गए साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्तता की जांच नहीं की गई है।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

140. समायोजन योजना के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:-

- (क) घरेलू उद्योग ने केवल एक वर्ष की अवधि के लिए उपायों हेतु अनुरोध किया है। तदनुसार, कोई समायोजन योजना प्रस्तुत नहीं की गई है।
- (ख) अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बताए गए प्राधिकृत अधिकारी के जांच परिणाम वो थे जहां एक से अधिक वर्ष के लिए उपायों के लिए अनुरोध किया गया था।

ट.3 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच

141. रक्षोपाय उपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमावली, 2012 के नियम 9 में निम्नानुसार कहा गया है -

“9. अंतिम जांच परिणाम - (1) प्राधिकृत अधिकारी, जांच की शुरुआत किए जाने की तारीख से आठ महीनों के भीतर अथवा ऐसी बड़ाई गई अवधि के भीतर, जैसा कि केन्द्रीय सरकार स्वीकृत करें, यह निर्धारित करेंगे कि क्या अप्रत्याशित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप विचाराधीन माल के बड़े हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है या क्षति का खतरा है और क्या बड़े हुए आयातों और गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे के बीच कोई कारणात्मक संबंध मौजूद है और सिफारिश करेंगे -

(iv) मात्रात्मक प्रतिबंधों को लागू किए जाने की अवधि और जहां मात्रात्मक प्रतिबंधों को लागू किए जाने की अवधि एक वर्ष से अधिक है, प्रगतिशील उदारता सकारात्मक समायोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्याप्त है।”

142. नियम 9 के अनुसार, प्राधिकृत अधिकारी सकारात्मक समायोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्याप्त प्रगतिशील उदारता के लिए व्यवस्था करेंगे यदि सिफारिश किए जा रहे उपाय एक से अधिक वर्ष के लिए है। चूंकि, घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध किए जा रहे उपाय एक वर्ष की अवधि के लिए है, यह धारित करने का प्रस्ताव किया जाता है कि किसी समायोजन योजना की व्यवस्था करने की कोई जरूरत नहीं है।

ठ. सार्वजनिक हित

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

143. सार्वजनिक हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए -

- क. उपायों को लागू किया जाना सार्वजनिक हित में नहीं होगा क्योंकि यह मांग-आपूर्ति स्थिति को कृत्रिम रूप से बदलेगा, तुलनात्मक प्रगति की भरपाई करेगा, विनिर्माण में अकुशलता उत्पन्न करेगा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बाधित करेगा, कृत्रिम रूप से उत्पादन की लागत में वृद्धि करेगा और डाउन स्ट्रीम उद्योग द्वारा निर्णय लेने में विसंगति उत्पन्न करेगा।
- ख. आवेदक भारत में मांग को पूरा करने में असमर्थ है और कोई भी उपाय उपयोक्ताओं के लिए नियमित आपूर्ति के स्रोत को समाप्त कर देगा।
- ग. घरेलू उद्योग का उत्पादन भारत में कुल मांग का केवल आधा है। उस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का अधिकतम क्षमता उपयोग केवल 52 प्रतिशत रहा है जब पाटनरोधी शुल्क लागू था। इस प्रकार, भारतीय उद्योग भारत में मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा।
- घ. जहां आवेदकों ने देश में उच्च क्षमताओं का दावा किया है, उत्पादन मात्रा बहुत निम्न है। यह नहीं माना सकता कि सारे उत्पादक 50 प्रतिशत से कम क्षमता उपयोग पर संचालन कर रहे हैं।
- ङ. भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग के बढ़ने की संभावना है जिस कारण मांग-आपूर्ति अंतर में और अधिक वृद्धि होगी।
- च. उपायों को लागू किया जाना सार्वजनिक हित में नहीं होगा क्योंकि लौह, स्टील, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और सिलिकॉन का उत्पादन करने के लिए मेटकोक एक महत्वपूर्ण तत्व है। मेट कोक की गुणवत्ता स्टील उत्पादन की निपुणता उत्पादकता और समग्र लागत को प्रभावित करती है।
- छ. जहां आवेदकों ने अनुरोध किया है कि कैप्टिव उत्पादक बाजार स्थितियों से अछूते हैं, कोल की कीमतों में वृद्धि के कारण सर्वाधिक हाल की अवधि के दौरान कैप्टिव उत्पादकों के उत्पादनों की लागत भी बढ़ी है। यदि उपाय लागू किए जाते हैं तो कैप्टिव उत्पादक, पर भी, जो मेट कोक आयात करते हैं, विपरीत रूप से प्रभाव पड़ेगा।
- ज. मात्रा संबंधी प्रतिबंधों को लागू करने से स्टील विनिर्माताओं के निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। मेट कोक की कीमतों में वृद्धि के कारण स्टील निर्माण की कीमत में वृद्धि होगी जो भारतीय उद्योग को वैश्विक रूप से अप्रतिस्पर्धात्मक बना देगा।
- झ. उपायों को लागू किया जाना डाउन स्ट्रीम उद्योग की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव डालेगा क्योंकि यह कोटे को लागू किए बिना निर्यात के लिए अभिप्रेत उत्पाद के उत्पादन के लिए विचाराधीन उत्पाद को आयात करने में समर्थ नहीं होगा।
- ञ. मेट कोक की पहुंच कीमत में 10 प्रतिशत की वृद्धि पिग आयरन की कुल लागत पर 3-5 प्रतिशत, एलॉय स्टील की कुल लागत का 2-3 प्रतिशत, राउंड और बिलेट की कुल लागत पर 3-5 प्रतिशत का प्रभाव डालेगी। मेट कोक की पहुंच कीमत में 50 प्रतिशत की वृद्धि का पिग आयरन की कुल लागत पर 18-25 प्रतिशत का प्रभाव, एलॉय स्टील की कुल लागत का 10-11 प्रतिशत और राउंड्स और बिलेट की कुल लागत का 18-20 प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा।
- ट. आवेदक पहले ही इंडोनेशिया से मेट कोक के आयातों पर 5 प्रतिशत सीमा शुल्क का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
- ठ. भारत सरकार ने पहले ही आयात शुल्क को हटाने के द्वारा मेट कोक के उत्पादकों को और कोकिंग कोल के आयातों पर कृषि आधारभूत संरचना और विकास उपकरण को हटाकर पहले ही राहत प्रदान की है।
- ड. मिथाइल एसिटोएसिटेट में प्राधिकृत प्राधिकारी मानते हैं कि रक्षोपाय शुल्क को लागू किया जाना सार्वजनिक हित में नहीं है और इसलिए उक्त मामले में कोई शुल्क लागू नहीं किए गए हैं।
- ढ. कोकिंग कोल के संबंध में भारत सरकार और रूसी संघ के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। यह एम ओ यू स्टील विनिर्माताओं को रूस से उच्च गुणवत्ता वाला कोकिंग कोल की अधिप्राप्ति में सहायता करेगा। अतः मेट कोक पर कोई भी उपाय सरकार के दृष्टिकोण के विरुद्ध होगा।
- ण. मात्रात्मक प्रतिबंधों को लागू किए जाने की स्थिति में, आयात की मात्रा 2.69 मिलियन मी.टन पर सीमित कर दी जाएगी, जो भारतीय बाजार में मांग की तुलना में 8,50,000 मी.टन कम है। ऐसी मांग भारतीय उद्योग द्वारा पूरी की जाएगी। किन्तु, भारतीय उद्योग केवल 1.04 मिलियन मी.टन का उत्पादन करता है और इसलिए, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या भारतीय उद्योग भारत में मांग को पूरा करने में समर्थ होगा।

- त. घरेलू उद्योग आयातों की मात्रा द्वारा प्रभावित नहीं है बल्कि केवल आयातों की कीमत से प्रभावित है। अतः आयातों की कुल मात्रा को सीमित करना एक उचित उपचार नहीं है।
- थ. मात्रात्मक प्रतिबंध स्टील मंत्रालय के 2030-31 तक अपरिष्कृत स्टील की 300 मिलियन टन की क्षमता और 255 मिलियन टन के उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति को बाधा डालेगा।
- द. सरकार ने विशिष्ट स्टील के लिए पी एल आई 1.0 योजना को क्रियान्वित किया है और पीएलआई 2.0 पर कार्य चल रहा है। मेट कोक के आयातों पर कोई भी प्रतिबंध सरकारी दृष्टिकोण के लिए हानिकारक होगा।

8.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

144. सार्वजनिक हित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे :-

- क. डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोई कीमत प्रभाव नहीं होगा क्योंकि वर्तमान जांच के अनुसरण में कोई शुल्क लागू नहीं किया जाएगा।
- ख. विचाराधीन उत्पाद कच्चा माल नहीं है बल्कि केवल ऊर्जा का एक स्रोत है। विचाराधीन उत्पाद की लागत डाउनस्ट्रीम उद्योग के लिए यह कोई महत्वपूर्ण लागत नहीं है।
- ग. विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर उपायों को लागू किए जाने का प्रभाव नगण्य होगा।
- घ. भारत में उचित कीमतें बनाए रखी जाएंगी क्योंकि बाजार में उत्पादकों की एक बड़ी संख्या है जो भारत में परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- ड. कोई मांग-आपूर्ति अंतर नहीं है क्योंकि भारत में व्यापारी क्षमताएं व्यापारिक मांग से अधिक हैं।
- च. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित कोटा मुख्य रूप से केवल आस्ट्रेलिया, चीन और इंडोनेशिया को प्रभावित करेगा। सामान्य आपूर्तिकर्ता जैसे पोलैंड, कोलंबिया और रूस हाल ही की अवधि में उनके आयातों से अधिक कोटा प्राप्त करेंगे।
- छ. उद्योग का मुख्य खंड कैप्टिव उत्पादकों द्वारा वहन किया जाता है। अतः आयातों पर उपायों को लागू किया जाना ऐसे उद्योग को प्रभावित नहीं करेगा।
- ज. दो याचिकाकर्ताओं के संयंत्र, घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत से निम्न कीमतों पर भारत में आयातों में वृद्धि के कारण बंद हो गए थे।
- झ. अनुरोध किए गए उपाय केवल एक वर्ष की अवधि के लिए हैं।
- ञ. इस अवधि के दौरान डाउन स्ट्रीम उद्योग पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं था जहां पाटनरोधी शुल्क आस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से आने वाले आयातों पर प्रवृत्त था।
- ट. भारतीय उद्योग 12,500 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से और 62,500 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराता है। प्रचालनों की अव्यवहार्यता की स्थिति में, बड़ी संख्या में व्यक्तियों का रोजगार समाप्त हो जाएगा।
- ठ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के आरोप के विपरीत, दिनांक 31 दिसंबर, 2019 की अधिसूचना सं. 41/2019 के अंतर्गत इंडोनेशिया से आयात शुल्क मुक्त हैं।
- ड. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के आरोप के विपरीत, प्राधिकृत अधिकारी मिथाइल एसिटोएसेट के संबंध में ऊपर उल्लिखित जांच में निष्कर्ष देते हैं कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में ह्रास नहीं हुआ है और आयातों में वृद्धि अप्रत्याशित विकास के कारण नहीं थी।
- ढ. चाहे भारत सरकार द्वारा रियायतें उपलब्ध कराई गई हैं, किन्तु ऐसी रियायतों का घरेलू उद्योग के निष्पादन पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा था।
- ण. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, भारत सरकार ने हमेशा भारत में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया है।

उ.3 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच

145. रक्षोपायों पर करार के अनुच्छेद 3.1 में निम्नानुसार कहा गया है :-

“कोई सदस्य पहले से स्थापित और जी ए टी टी, 1994 के अनुच्छेद X के अनुसरण में उस सदस्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की गई जांच के अनुसरण में ही किसी रक्षोपाय उपाय के लिए आवेदन कर सकता है। इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को उचित सार्वजनिक नोटिस और सार्वजनिक सुनवाई या अन्य उचित साधन शामिल होंगे जिनमें आयातक, निर्यातक और अन्य हितबद्ध पक्षकार साक्ष्य और उनके मत प्रस्तुत कर सकते हैं जिनमें अन्य पक्षकारों के प्रतिवेदनों का उत्तर देने का अवसर देने और अन्य बातों के साथ-साथ इस संबंध में कि क्या कोई रक्षोपाय उपाय सार्वजनिक हित में है या नहीं अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना शामिल है। सक्षम प्राधिकारी तथ्यों और कानून के सभी मुद्दों पर अपने जांच परिणामों और तर्कसंगत निष्कर्षों को बताते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।”

146. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह जांच किए जाने की आवश्यकता है कि क्या रक्षोपाय उपायों को लागू किया जाना सार्वजनिक हित में होगा। हालांकि, अनुच्छेद 3.1 मूल्यांकन के तरीके पर कोई मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं कराता, तथापि इसकी अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न स्टैकधारकों पर उपायों के प्रभाव को मूल्यांकन किए जाने और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के प्रतिस्पर्धी हितों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है।

147. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के संबंध में कि भारत में मांग-आपूर्ति अंतर विद्यमान है, यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग निम्न क्षमता उपयोग पर प्रचालन कर रहा है जबकि भारत में इसकी प्रचुर मांग है। इसके अलावा, भारत में व्यापारी क्षमताएं देश में कुल व्यापारी मांग की तुलना में अधिक है। इसके अलावा, आयातों की मात्रा केवल 2022-23 में आयातों में उछाल की मात्रा तक ही विनियमित की जाएगी। जिस सीमा तक मात्रा विनियमित की जाएगी इसकी भरपाई याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग द्वारा भी बड़ी आसानी से की जा सकती है। तदनुसार, यह प्रस्ताव किया जाता है कि उपायों को लागू किए जाने से भारत में उत्पाद की उपलब्धता में कमी नहीं होगी।

विवरण	मात्रा
भारत में व्यापारिक मांग (2022-23)	61,86,991
भारत में व्यापारिक क्षमता (2022-23)	63,69,455
मांग-आपूर्ति अंतर	(1,82,464)

148. यह नोट किया जाता है कि मेट कोक बहुत से उत्पादों की उत्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है जैसे लौह, स्टील, फ़ैरो एलॉय, रसायन आदि। चूंकि मेट कोक एक प्रमुख कच्चा माल नहीं है और डाउन स्ट्रीम उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण लागत नहीं है, इसलिए मेट कोक की लागत में कोई भी परिवर्तन डाउन स्ट्रीम उद्योग की लागतों पर असहनीय प्रभाव नहीं डालेगा।

149. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि चाहे उत्पाद के आयातों पर उपायों को लागू किए जाने के पश्चात मेट कोक की कीमतों में वृद्धि हो जाती है तब भी ऐसे उपायों का प्रभाव नगण्य होगा।

विवरण	इकाई	दर
डाउन स्ट्रीम उत्पाद की कीमत		
हॉट रोल्ड कॉयल स्टील	₹/मी.टन	62,138
हॉट मैटल (पिग आयरन के लिए)	₹/मी.टन	41,000
घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत	₹/मी.टन	41,675
भारतीय व्यापारी उत्पादकों द्वारा कुल उत्पादन	मी.टन	26,99,115

भारत में कुल आयात	मी.टन	36,39,492
कैप्टिव उत्पादन	मी.टन	2,29,44,282
कुल खपत (कुल उत्पादन + आयात)	मी.टन	2,92,82,889
व्यापारी उत्पादकों का हिस्सा	%	9%
पिछले तीन वर्षों में औसत मार्जिन/ रूपए / कीमतों में वृद्धि	₹/मी.टन	2,081
कीमत में वृद्धि के मामले में बिक्री कीमत	₹/मी.टन	43,756
निम्न के लिए मेट कोक की खपत		
हॉट रोलड कॉयल स्टील	किग्रा./मी.ट.	304
हॉट रोलड कॉयल स्टील में व्यापारी का हिस्सा	किग्रा./मी.ट.	28
हॉट मेटल (पिग आयरन के लिए)	किग्रा./मी.ट.	357
हॉट मेटल के लिए व्यापारी का हिस्सा	किग्रा./मी.ट.	33
प्रभाव		
हॉट रोलड कॉयल स्टील	₹/मी.टन	58
हॉट मेटल (पिग आयरन के लिए)	₹/मी.टन	68
हॉट रोलड कॉयल स्टील	%	0.09%
हॉट रोलड कॉयल स्टील	%	0.17%

150. यह भी नोट किया जाता है कि उत्पाद के आयातों पर व्यापार उपचारात्मक उपायों का इतिहास है। तथापि, किसी भी प्रयोक्ता ने उनके निष्पादन पर पूर्ववर्ती उपायों के विपरीत प्रभाव का प्रदर्शन नहीं किया है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं है कि उपायों को लागू किया जाना डाउन स्ट्रीम उद्योग के निष्पादन को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा।

151. प्राधिकृत अधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों का संज्ञान लिया है कि उत्पाद का या तो उत्पादकों द्वारा व्यापारी बाजार में बेचने के लिए विनिर्माण किया जाता है या कैप्टिव रूप से उपभोग किया जाता है। उत्पाद के लिए कैप्टिव बाजार व्यापारी बाजार की तुलना में बहुत बड़ा है। उपायों को लागू किया जाना बाजार के बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित नहीं करेगा।

खंड	खपत				खंड-वार हिस्सा %	
	सकल (केटी)	कैप्टिव (केटी)	व्यापारी (केटी)	% व्यापारी हिस्सा	समग्र	व्यापारी
स्टील	***	***	***	11%	89%	54%
पिग आयरन	***	***	***	47%	5%	14%
जिंक, सोडा ऐश और अन्य	***	***	***	100%	2%	11%
फैरो अलॉय	***	***	***	100%	1%	8%
फाउंड्री	***	***	***	100%	1%	4%
अन्य	***	***	***	100%	2%	9%
जोड़	38,320	31,586	6,734		100%	100%

152. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि भारतीय बाजार में बड़ी संख्या में ऐसे उत्पादक हैं जो परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। तदनुसार, भारत में कीमतें उचित और प्रतिस्पर्धी बनी रहेंगी।

153. जांच की प्रक्रिया के दौरान जुटाए गए और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई सूचना के आधार पर यथा स्थापित अनिवार्य तथ्यों का यहां प्रकटन किया जा रहा है ताकि विभिन्न हितबद्ध पक्षकार इस प्रकार जुटाए गए इन तथ्यों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकें। तथापि, प्राधिकृत प्राधिकारी इस प्रकटीकरण विवरण के लिए हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर जांच के विभिन्न पहलुओं पर अंतिम निर्धारण करेंगे, जहां तक वे प्रासंगिक हैं।

ठ.4. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

154. प्रकटन विवरण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. चूंकि, घरेलू उद्योग आस्ट्रेलिया से कोयले का आयात करता है। इसलिए, रूस – यूक्रेन युद्ध का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। विशेष रूप से तब जब भारत में उच्च मालभाड़ा लागत के कारण रूस से कोयला का आयात नहीं किया है।
- ख. यद्यपि प्राधिकारी ने कोकिंग कोयले की कीमतों पर काफी अधिक भरोसा किया है। तथापि, रक्षोपाय जांच में संबद्ध वस्तु की वैश्विक आपूर्ति और अन्य देशों में आयात प्रतिबंध नीति का विश्लेषण करना आवश्यक है।
- ग. इंडोनेशियाई उत्पादकों ने उच्च मालभाड़ा के लागत के प्रभाव का भी सामना किया है, क्योंकि उसकी रूस और आस्ट्रेलिया से दूरी भारत के बराबर है। इंडोनेशियाई उत्पादक आयातित कोकिंग कोयले पर काफी अधिक निर्भर है।
- घ. घरेलू उद्योग अपने उत्पादन में वृद्धि करने में सक्षम था। घरेलू उद्योग की बिक्री और बाजार हिस्से में मामूली गिरावट आई है।
- ङ. आयातों कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में 2021-22 और 2022-23 में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि हुई है जिसकी वजह से उसकी लाभप्रदता में गिरावट आई है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति आंतरिक कारणों की वजह से हुई है।
- च. घरेलू उद्योग को हुई क्षति आयातों के कारण नहीं, बल्कि एनआईएनएल के बंद होने के कारण हुई है और एनआईएनएल तथा एमएमटीसी द्वारा व्यापारिक बाजार में कम कीमत पर मेट कोक बेचा गया है।
- छ. कोई कीमत हास नहीं हुआ है, क्योंकि पहुंच कीमत में 2019-20 की तुलना में 2022-23 में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक वृद्धि हुई है।
- ज. कोकिंग कोल की कीमत में वृद्धि का मेट कोक के आयातों में वृद्धि की गतिविधि से कोई सीधा संबंध नहीं है और उसे अप्रत्याशित घटना नहीं माना जा सकता है।
- झ. चूंकि, भारतीय कंपनियों ने अनुकूल कीमतों पर रूस से कोयला खरीदा है। इसलिए, उन्हें कच्ची सामग्री की काफी अधिक कीमत का सामना नहीं करना पड़ा है। जिंदल कोक लिमिटेड ने जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड से कोकिंग कोयला खरीदा है जिसे मोजाम्बिक में उनकी संबंधी कंपनी द्वारा खनिज किया गया है।
- ञ. उन उत्पादकों के नाम जिनके उत्पादन पर भारत में मेट कोक के कुल घरेलू उत्पादन, कुल घरेलू उत्पादन के निर्धारण, कुल उत्पादन के निर्धारण की पद्धति, ऐसे कुल उत्पादन में आवेदकों के हिस्से और उत्पादकों के नाम के निर्धारण में विचार किया गया है और जिन्हें अपात्र माना गया है, उनका ब्यौरा प्रकटन विवरण में नहीं है।
- ट. यद्यपि प्राधिकारी ने इस निष्कर्ष का प्रस्ताव किया है कि आबद्ध उत्पादन को बाहर रखना प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु नहीं है। तथापि आबद्ध उत्पादक भारत में समान उत्पाद के उत्पादक भी हैं। अतः ऐसे उत्पादकों को पात्र मानना चाहिए। “प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु” शब्द का अर्थ उन वस्तुओं को शामिल करना है, जो परस्पर समान वस्तु नहीं हों। परंतु विचाराधीन उत्पाद से प्रतिस्पर्धा करती हों। इस प्रकार, ‘प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु’, बंद उत्पाद की प्रकृति नहीं है, बल्कि उत्पादक के बारे में लिखित है।

- ठ. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की परिभाषा में "अथवा" की "और" के रूप में गलत व्याख्या की है। परिभाषा के प्रत्येक घटक को स्वतंत्र रूप से पढ़ना चाहिए। "समान वस्तु" और "प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु" की दो स्थितियां एक साथ पूरी करने के लिए अधिदेशित नहीं हैं।
- ड. यद्यपि प्राधिकारी ने यूएस - लैंब मामले में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट पर भरोसा किया है। तथापि, वह मामला वर्तमान जांच पर लागू नहीं होता है, क्योंकि उस मामले में मुद्दा उत्पाद से संबंधित था जबकि वर्तमान जांच में मुद्दा उत्पाद के उत्पादक से संबंधित है।
- ढ. सोलर सेल के आयातों संबंधी रक्षोपाय जांच के तथ्य वर्तमान जांच पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि आबद्ध उत्पादन के लिए संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले घरेलू उत्पादकों को एसईजेड में हिस्से उत्पादकों के बराबर नहीं माना जा सकता है।
- ण. यद्यपि प्राधिकारी ने अनेक कानूनों पर भरोसा किया है। तथापि, उनका केवल सामान्य संदर्भ दिया है। किसी भी कानून में आबद्ध उत्पादन के लिए वस्तु के उत्पादन में शामिल घरेलू उत्पादकों के लिए किसी विशेष व्यवहार्य का प्रावधान नहीं है।
- त. भारत में कोई डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय रिपोर्ट नहीं है-स्टेनलेस स्टील के कुछ हॉट-रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर सुरक्षा उपाय और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया उद्धरण चीन में अपीलीय निकाय रिपोर्ट को संदर्भित करता है - दुर्लभ पृथ्वी, टंगस्टन और मोलिब्डेनम के निर्यात से संबंधित उपाय
- थ. यदि आबद्ध उपभोक्ताओं का उत्पादन बाहर ही रखा जाए तो ही व्यापारी और आबद्ध बाजार के लिए उत्पादन कर रहे उत्पादकों के उत्पादन पर विचार किया जाना चाहिए।
- द. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में एसोसिएशन द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच नहीं की है।
- ध. कोयले की कीमत में वृद्धि को अप्रत्याशित घटना नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह समाप्त्य प्राकृतिक संसाधन की कीमत में वृद्धि है, जो इसकी उपलब्धता सीमित होना आशंकित रहता है। इसके अलावा, यह सामान्य बात है कि घरेलू रूप से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन में कीमतों में कम दर से वृद्धि होगी।
- न. यद्यपि घरेलू उद्योग ने स्वयं रूस के मुकाबले आस्ट्रेलिया से उच्चतर कीमत पर कोयले के आयात का विकल्प चुना है। तथापि, उसने उसे यह कहते हुए उचित ठहराया है कि रूस से आयातों की मालभाड़ा लागत अधिक है। इसका अर्थ है कि कम कीमत पर रूस से कोयले की अनुपलब्धता उच्च मालभाड़ा की दर की वजह से थी और उसे अप्रत्याशित घटना नहीं माना जा सकता है।
- प. यदि कोकिंग कोल की कीमत में वृद्धि को अप्रत्याशित घटना माना जाए तो वह आयातों में वृद्धि का कारण नहीं हो सकता है। बेयर इलास्टो मैरिक यार्न मामले में प्राधिकारी ने माना था कि गंभीर क्षति के कारण वाली अप्रत्याशित घटना और आयातों में वृद्धि वाली अप्रत्याशित घटना के बीच अंतर है।
- फ. प्राधिकारी द्वारा प्रभाव आकलन उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने केवल डाउनस्ट्रीम उत्पाद के रूप में हॉट रोल्ड कोइल स्टील पर विचार किया है और बिग आयरन, विलेट और राउंड पर नहीं। प्राधिकारी ने माना है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत को उपाय लगाने के बाद एक विशेष दर पर किया जाएगा और ऐसी मान्यता आर्थिक रूप से अव्यवहार्य है और कानूनी रूप से अनुमति योग्य नहीं है। यद्यपि प्राधिकारी ने यह माना है कि हॉट रोल्ड कोइल स्टील के उत्पादन के लिए 304 कि.ग्रा. मेट की जरूरत है परंतु वास्तव में 400-500 कि.ग्रा. की आवश्यकता होती है।
- ब. प्राधिकारी ने माना है कि अधिकांश मांग आबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा पूरी की जाएगी, परंतु उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया है कि उत्पाद के सभी उपभोक्ताओं के पास आबद्ध मेट कोक संयंत्र नहीं हैं।
- भ. वृद्धि की अवधि को छोड़कर पिछले तीन वर्षों में आयातों की मात्रा पर आधारित कोटे का निर्धारण गलत है और जांच अवधि को वृद्धि की अवधि और पूर्ववर्ती तीन वर्षों के रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है। कोटा तय करने की संगत प्रक्रिया नहीं हो सकती है, क्योंकि भारत में केवल दो रक्षोपाय (क्यूआर) जांच हुई है।

- म. कोटा तय करने के लिए पिछले तीन प्रतिनिधि वर्षों पर विचार करते समय मांग – आपूर्ति में वास्तविक अंतर की वर्तमान प्रतिनिधि अवधि अर्थात् 2023-24 को पहले ही बाहर किया गया है। 2022-23 को बाहर करने के परिणामस्वरूप कोटे का बिल्कुल अप्रतिनिधि निर्धारण होगा।
- य. अचानक वृद्धि की अवधि में आयातों में वृद्धि की भरपाई पूर्ववर्ती तीन वर्षों में औसत आयातों पर विचार करके की गई है।
- कक. अचानक वृद्धि की अवधि को कोटा निर्धारण से बाहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस्पात की मांग में वृद्धि हुई है। इससे भारत में मेट कोक की मांग में वृद्धि हुई है। इस्पात की मांग में आगे और वृद्धि होने की उम्मीद है। दोनों रक्षोपाय (क्यूआर) जांचों अर्थात् आईपीए और पीवीसी में प्राधिकारी ने कोटा तय करते समय मांग में वृद्धि पर विचार किया है।
- खख. प्रकटीकरण में बाल्टा के प्रस्तुतीकरण पर विचार नहीं किया गया और न ही उसका समाधान किया गया, जिसमें दर्शाया गया था कि सुरक्षा उपाय के दायरे से एक व्यक्तिगत काउंटी से आयात को बाहर करना स्वीकार्य है। तदनुसार, पोलैंड को उपायों के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
- गग. याचिकाकर्ताओं के पास कुल भारतीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा नहीं है क्योंकि यह भारत में उत्पादन के कुल हिस्से का 51% से अधिक होना चाहिए।
- घघ. ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में कुल उत्पादन का 67% बनाने वाले अन्य 20 घरेलू उत्पादकों को कोई क्षति नहीं हुई है और इसलिए, वे प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष नहीं हैं।
- ङङ. याचिकाकर्ताओं ने ट्रेड नोटिस संख्या 10/2018 दिनांक 7 सितंबर 2018 के अनुसार कुछ मापदंडों के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं, जबकि अधिकृत अधिकारी ने ट्रेड नोटिस का उल्लंघन करते हुए गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है।
- चच. पूर्ण रूप से या घरेलू उत्पादन के सापेक्ष इतनी बड़ी हुई मात्रा में इंडोनेशिया से आयात में कोई वृद्धि नहीं हुई है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो।
- छछ. बाजार की जानकारी के अनुसार, घरेलू उद्योग उचित मात्रा में संबद्ध वस्तुओं का आयात कर रहा है। इस प्रकार, आयात में वृद्धि का श्रेय याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वयं किए गए आयात को दिया जाना चाहिए जिससे उन्हें क्षति हो रही है।
- जज. प्राधिकृत अधिकारी को स्पष्ट रूप से सबूत देना चाहिए कि रूस-यूक्रेन संघर्ष, वैश्विक माल दुलाई दरों में वृद्धि और चीनी उत्पादकों के कथित लाभ ने भारतीय बाजार को विशेष रूप से कैसे प्रभावित किया है।
- ञञ. याचिकाकर्ता POI में आयात की तुलना असामान्य अवधि यानी 2020-21 और 2021-22 में आयात से कर रहे हैं जो अनुचित और अनुचित है।
- टट. प्राधिकृत अधिकारी घरेलू उद्योग को हुए नुकसान का विश्लेषण करने के लिए कोविड-19 महामारी से पहले के पिछले वर्षों का विकल्प चुन सकते हैं।
- ठठ. आधार वर्ष 2019-20 की तुलना में 2022-23 के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार हुआ है, इस प्रकार, घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में सुधार हुआ है, जिससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
- डड. प्राधिकृत अधिकारी अंतिम निष्कर्ष में पुष्टि करेगा कि उपाय, केवल एक वर्ष के लिए होंगे और मध्यावधि या निर्णायक समीक्षा के माध्यम से कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा क्योंकि कोई व्यवहार्य समायोजन योजना प्रस्तुत नहीं की गई है।
- ढढ. आयात में बढ़ोतरी अंतरिम है और घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं की जा रही है। याचिकाकर्ताओं ने स्वयं कहा है कि आयात में वृद्धि अस्थायी है।
- णण. याचिकाकर्ता वर्तमान में भारतीय उद्योग की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं और सुरक्षा उपाय लागू करने से नियमित आपूर्ति के स्रोत में कटौती होगी और भारत के सार्वजनिक हित पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

- तत. प्राधिकृत अधिकारी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से 40 मिमी तक के आकार वाले मेट कोक को बाहर न करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।
- थथ. प्राधिकृत अधिकारी ने एएमएनएस के इस तर्क का मूल्यांकन नहीं किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया कोक निम्न गुणवत्ता का है।
- दद. सुरक्षा उपायों पर समझौते के साथ पढ़े गए एफटीडीआर अधिनियम की धारा 9ए(4)(बी) के तहत, घरेलू उद्योग को "सीधे प्रतिस्पर्धी सामान" के उत्पादक के रूप में परिभाषित किया गया है, न कि "सीधे प्रतिस्पर्धी सामान" के रूप में।
- धध. यदि केवल "सीधे प्रतिस्पर्धी" उत्पादकों को घरेलू उत्पादकों का हिस्सा माना जा सकता है, तो ईओयू को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि वे आयात के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। फिर भी सौर सुरक्षा जांच में, अधिकृत अधिकारी ने ईओयू को घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल किया, भले ही ईओयू आयातित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता था।
- नन. अमेरिका में - कॉटन यार्न, अपीलीय निकाय ने प्रतिस्पर्धी और प्रतिस्पर्धी के बीच अंतर समझाया। अपीलीय निकाय ने माना कि भले ही निर्माता दूसरे के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हों, प्रतिस्पर्धा करने की संभावना ही उन उत्पादकों की उत्पादन मात्रा को 'कुल घरेलू उत्पादन' में शामिल करने के लिए पर्याप्त है। व्यापारी बाजार में बिक्री न होने के बावजूद कैप्टिव उत्पादक आयातित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धी संबंध में हैं।
- पप. लंबवत रूप से एकीकृत उत्पादक भी व्यापारी बाजार में प्रवेश कर सकते हैं, जैसा कि नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड ने अपने इस्पात संयंत्र के बंद होने के कारण किया था।
- फफ. डोमिनिकन गणराज्य - सुरक्षा उपायों में, पैनल ने माना कि उत्पाद के उत्पादकों के केवल एक सीमित हिस्से के आधार पर घरेलू उद्योग को परिभाषित करना स्वीकार्य नहीं है।
- बब. हालिया अवधि के दौरान आयात की मात्रा 35,15,654 मीट्रिक टन है, जबकि 2013-14 के दौरान आयात की मात्रा 39,26,125 मीट्रिक टन थी। हालिया अवधि के दौरान आयात की मात्रा एक दशक पहले मौजूद आयात की मात्रा से कम है।
- भभ. सस्ते विकल्प उपलब्ध होने पर घरेलू उद्योग ऑस्ट्रेलिया से उच्च कीमत वाले कोकिंग कोयले का आयात करता है। महंगे कच्चे माल के कारण, मेट कोक के उत्पादन की लागत मेट कोक के आयात मूल्य से अधिक है। हालाँकि, यह एक ऐसी परिस्थिति है जो घरेलू उद्योग के लिए अद्वितीय है और यह कोई सामान्य अप्रत्याशित विकास नहीं है।
- मम. चूंकि भारत ने रूस से आयात के खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, इसलिए यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है कि केवल चीनी उत्पादकों को रूसी कोयले से लाभ हुआ है।
- यय. अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच कोकिंग कोयले की कीमत में गिरावट आई है, इस प्रकार, इस दलील पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए कि कोकिंग कोयले की कीमत में वृद्धि हुई है।
- ककक. आधार वर्ष से नवीनतम अवधि तक घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में 97% की असामान्य वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान मेट कोक की पहुंच कीमत में 79% की वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग को नुकसान कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी के कारण हुआ है।
- खखख. घरेलू उद्योग ने हाल की अवधि के दौरान अपनी स्थापित क्षमता में वृद्धि की है, जिससे उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है।
- गगग. केवल रुपये के प्रभाव का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। हॉट मेटल (पिग आयरन) की कीमतें प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 68/MT निर्धारित की गई हैं। प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी संख्या तक पहुंचने के लिए उन साक्ष्यों का खुलासा करना होगा जिन पर उसने भरोसा किया है। डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं पर वास्तविक प्रभाव कहीं अधिक है।
- घघघ. इस्पात मंत्रालय ने 2030-31 तक 300 मिलियन मीट्रिक टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है, कोई भी उपाय भारत को कुछ साल पीछे धकेल देगा।

- डडड. प्राधिकृत अधिकारी से अनुरोध है कि 30 मिमी के आकार के साथ 0.030% तक फॉस्फोरस सामग्री के साथ कम राख वाले धातुकर्म कोक को शामिल करने के लिए बहिष्करण का कवरेज बढ़ाया जाए। उत्पाद बहिष्करण के दायरे की परिभाषा में आकार के लिए 5% तक की सहनशीलता।
- चचच. कोई समर्पित टैरिफ आइटम नहीं है जिसके तहत 18% से कम राख सामग्री वाले मेटलर्जिकल कोक के आयात को विशेष रूप से वर्गीकृत किया जा सके। यह स्पष्ट नहीं है कि वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आयात डेटा पर कैसे भरोसा किया जा सकता है।
- छछछ. घरेलू उद्योग ने अपनी टिप्पणियों को 40 मिमी तक के आकार वाले मेट कोक की उपलब्धता तक सीमित कर दिया है, और यह किस मात्रा में उपलब्ध है, इसके संबंध में कोई टिप्पणी नहीं दी है। '40 मिमी तक के लैम कोक' की सीमित उपलब्धता से मिनी ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग करने वाले पिग आयरन उत्पादकों के संचालन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
- जजज. प्राधिकृत अधिकारी ने बाजार की स्थितियों और कोविड के बाद विचाराधीन उत्पाद की मांग में देखे गए परिवर्तनों की पुष्टि नहीं की है, और वृद्धि अवधि से पहले तीन वर्षों में औसत आयात के आधार पर कोटा तय करना कैसे उचित है।
- झझझ. घरेलू उद्योग लगातार अपनी आधी से भी कम क्षमता पर काम कर रहा है। यहां तक कि जब चीन और ऑस्ट्रेलिया से आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लागू था, तब भी घरेलू उद्योग अपनी क्षमता उपयोग बढ़ाने में असमर्थ था।
- ञञञ. उत्तरदाताओं को यह भी आशंका है कि भले ही घरेलू उत्पादक घरेलू मांग को पूरा करने के लिए अपना उत्पादन बढ़ाते हैं, लेकिन यह भारत में एलएएम कोक की मांग में वृद्धि के अनुरूप नहीं हो सकता है।
- टटट. मेट कोक फेरो मिश्र धातु, स्टील और पिग आयरन जैसे तैयार माल के उत्पादन के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है। भारत इन डाउनस्ट्रीम उत्पादों का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है।
- ठठठ. प्रकटीकरण विवरण में दर्ज आंकड़ों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में महत्वपूर्ण अंतर हैं।
- डडड. प्राधिकृत अधिकारी ने घरेलू उद्योग के समग्र डेटा के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- ढढढ. कोकिंग कोयले की कीमतों में वृद्धि रूस-यूक्रेन युद्ध से पहले की है। घरेलू उद्योग द्वारा संदर्भित रिपोर्टों ने इस बिंदु को रेखांकित किया।
- णणण. घरेलू उद्योग 2021 के मध्य से कोकिंग कोयले की तंग आपूर्ति से अच्छी तरह वाकिफ था। घरेलू उद्योग 2021 से यह भी जानता था कि सीमित आपूर्ति और माल दुलाई संबंधी चुनौतियों के प्रभाव के कारण कोकिंग कोयले की कीमतें 2021 के मध्य और फरवरी 2022 के बीच उच्च स्तर पर पहुंच गईं। फरवरी 2022 वह महीना था जिसमें रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया जिससे यह स्वयं स्पष्ट है उस समय तक कीमतों पर कोकिंग कोल और माल दुलाई से संबंधित प्रभाव पहले से ही एक पुरानी घटना थी।
- ततत. याचिकाकर्ताओं द्वारा वहन की गई कच्चे माल की लागत की तुलना आयात की पहुंच कीमत से उचित रूप से नहीं की जा सकती है या इसमें समान वृद्धि की उम्मीद नहीं की जा सकती है क्योंकि भारत में कोकिंग कोयले के प्राकृतिक भंडार की कमी है और आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। घरेलू उत्पादकों के लिए लागत संरचना स्वाभाविक रूप से समुद्री माल दुलाई लागत जैसे अतिरिक्त कारकों से प्रभावित होती है और इसे निर्यातकों के उत्पादन की लागत के बराबर नहीं माना जा सकता है।
- थथथ. घरेलू उद्योग की शिकायतें पूरी तरह से उत्पादन की लागत और चीन से आयात की कीमत से संबंधित हैं, और सुरक्षा उपाय लागू करने के कानूनी मानक पर इसका कोई असर नहीं है।

M2. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

155. प्रकटीकरण विवरण जारी होने के बाद घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं।

- क. 0.03% से कम फॉस्फोरस सामग्री और 30 मिमी से कम आकार वाले अल्ट्रा-लो फॉस्फोरस मेटलर्जिकल कोक को केवल फेरोलॉय अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए बाहर रखा जाना चाहिए। कोटा लागू किए बिना उत्पाद आयात करने के लिए आयातकों को उत्पाद का वास्तविक उपयोग दिखाना होगा।

- ख. कोक फाइन्स और अल्ट्रा-लो फॉस कोक को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है लेकिन आयात डेटा में शामिल किया गया है। प्रस्तावित कोटा की गणना के लिए इसे बाहर रखा जाना चाहिए।
 - ग. याचिकाकर्ताओं की बाजार जानकारी के अनुसार आयात की मात्रा और प्रकटीकरण विवरण में दी गई आयात की मात्रा के बीच बहुत बड़ा अंतर है। अंतर इस तथ्य के कारण है कि प्रकटीकरण विवरण में दिए गए आयात की मात्रा में कोक फाइन और अल्ट्रा-लो फॉस कोक शामिल हैं।
 - घ. याचिकाकर्ताओं ने प्राधिकृत अधिकारी से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया है कि कोकिंग कोयले की कीमत उन विदेशी उत्पादकों के लिए नहीं बढ़ी है जो उन देशों में स्थित हैं जहां कोकिंग कोयला घरेलू स्तर पर उपलब्ध है।
 - ङ. अन्य इच्छुक पक्ष मौखिक सुनवाई के दौरान सहमत हुए कि यूक्रेन-रूस संघर्ष एक अप्रत्याशित विकास है। उक्त अप्रत्याशित विकास के कारण, भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयात बढ़ गया है और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है।
 - च. चूंकि मेट कोक के उत्पादन की लागत का 90% हिस्सा कोकिंग कोयले का होता है, इसलिए मेट कोक की कीमतें कोकिंग कोयले की लागत के अनुरूप होनी चाहिए। हालाँकि, उद्घाल की अवधि के दौरान, मेट कोक की पहुँच कीमत में कोकिंग कोयले की कीमतों में वृद्धि के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है, जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान हुआ है।
 - छ. जबकि भारतीय उद्योग ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद कुछ मात्रा में रूसी कोकिंग कोयले का भी आयात किया है, मात्रा बहुत कम है और ऐसे आयात की कीमत चीन में आयात की कीमत से अधिक है।
 - ज. चीनी उत्पादकों ने ऑस्ट्रेलियाई कोयले का लाभ उठाने के लिए इंडोनेशिया में निवेश किया है। चूंकि ऑस्ट्रेलिया चीन की तुलना में इंडोनेशिया के करीब है, इसलिए इंडोनेशिया में ऑस्ट्रेलियाई कोयले की खरीद की लागत चीन की तुलना में बहुत कम है।
 - झ. वैश्विक कोकिंग कोयले और घरेलू स्तर पर उपलब्ध कोकिंग कोयले की कीमतों के बीच असमानता के कारण, ऑस्ट्रेलियाई मेट कोक उद्योग कम कीमतों पर मेट कोक का उत्पादन करने और उसे कम कीमतों पर भारत में निर्यात करने में सक्षम था।
 - ञ. अधिकांश घरेलू उत्पादक प्रकाशित कीमतों के आधार पर कोकिंग कोयला खरीदते हैं। भारत में मेट कोक के आयात में वृद्धि के कारण, घरेलू उद्योग खरीदे गए उच्च मूल्य वाले कोकिंग कोयले का उपयोग करने में सक्षम नहीं था क्योंकि घरेलू उद्योग को हाल की अवधि के दौरान उत्पादन कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसलिए, जब कोकिंग कोयले की कीमत में गिरावट आई, तब भी घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत ऊंची बनी रही।
 - ट. यदि आयात नहीं बढ़ा होता, तो घरेलू उत्पादकों को ऑर्डर मिल गए होते और उन्होंने योजना के अनुसार कोयले की खपत कर ली होती। मेट कोक के आयात में वृद्धि के कारण ऑर्डर की अनुपलब्धता के कारण कोयले का भारी भंडार जमा हो गया।
 - ठ. कई देशों से आयात में वृद्धि हुई है। जापान और पोलैंड जैसे देशों में मात्रा में कमी आई है और प्रस्तावित उपायों से उन्हें लाभ होगा।
 - ड. घरेलू उत्पादन में याचिकाकर्ताओं की बड़ी हिस्सेदारी है। आवेदकों और समर्थकों को छोड़कर अन्य घरेलू उत्पादकों में वे शामिल हैं जो उत्पाद के निर्माण के साथ-साथ निर्यात बाजार और व्यापार में रुचि रखते हैं।
 - ढ. अन्य घरेलू उत्पादकों में से एक के पास कैप्टिव कोयला खदान है और चूंकि भारत में कम राख वाला कोकिंग कोयला उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह उच्च राख वाले मेट कोक का उत्पादक है जो विषय वस्तु में एनपीयूसी है।
 - ण. जांच अवधि के बाद भी विचाराधीन उत्पाद के आयात में वृद्धि हुई है।
156. प्राधिकृत अधिकारी ने विभिन्न देशों की सरकारों, घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातक, उपयोगकर्ताओं और अन्य इच्छुक पार्टियों सहित सभी इच्छुक पार्टियों द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है। प्राधिकृत अधिकारी ने पहले ही इस अंतिम निष्कर्ष में विस्तृत जांच कर ली है। अंतिम निष्कर्षों के इस खंड में केवल नए अनुरोधों पर ही विचार किया जा रहा है।

157. जबकि अन्य इच्छुक पार्टियों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग को नुकसान यूक्रेन-रूस संघर्ष के कारण नहीं हो सकता है क्योंकि भारतीय उत्पादकों ने रूसी कोयले का आयात नहीं किया है, प्राधिकृत अधिकारी का कहना है कि घरेलू उद्योग को नुकसान आयात में वृद्धि के कारण हुआ है अप्रत्याशित परिस्थितियों, यानी रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण विचाराधीन उत्पाद का। रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण कई देशों द्वारा ऐसे आयात पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूस से कोकिंग कोयले की मांग में गिरावट आई। इसके संपार्श्विक प्रभाव के रूप में, अन्य देशों से कोकिंग कोयले की मांग बढ़ने से वैश्विक स्तर पर कोकिंग कोयले की कीमतों में वृद्धि हुई। चूंकि मेट कोक की कीमतें कोकिंग कोयले की कीमत में वृद्धि के अनुरूप नहीं बढ़ीं, इसलिए मेट कोक और कोकिंग कोयले के बीच डेल्टा में गिरावट आई, जिससे मेट कोक के आयात में वृद्धि हुई।
158. इस तर्क के विपरीत कि इंडोनेशियाई उत्पादकों को रूस और ऑस्ट्रेलिया से दूरी में समानता के कारण उच्च माल ढुलाई लागत के प्रभाव का भी सामना करना पड़ता है, यह ध्यान दिया जाता है कि इंडोनेशिया 2019-20 में भारत को कोकिंग कोयले का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता था। हालाँकि इंडोनेशिया भारत को भारी मात्रा में कोकिंग कोयले का निर्यात कर रहा था, इंडोनेशिया से भारत को कोकिंग कोयले के निर्यात में गिरावट आई है जबकि इंडोनेशिया से भारत को मेट कोक के निर्यात में वृद्धि हुई है। इंडोनेशिया को रूस-यूक्रेन संघर्ष से लाभ हुआ क्योंकि विश्व स्तर पर कोकिंग कोयले की कीमतें बढ़ गईं, हालाँकि, मेट कोक की कीमतों में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई क्योंकि इंडोनेशियाई उत्पादकों के पास घरेलू कोकिंग कोयले तक पहुंच थी और कोयले और कोक के बीच डेल्टा में गिरावट आई, इंडोनेशियाई उत्पादकों ने कोयले का निर्यात करना शुरू कर दिया। भारत को कोक. इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि इंडोनेशियाई उत्पादक आयातित कोकिंग कोयले पर निर्भर हैं और भारतीय उत्पादकों के समान इसके लिए उच्च माल ढुलाई लागत वहन करते हैं।
159. प्राधिकृत अधिकारी का कहना है कि रूस-यूक्रेन संघर्ष के अप्रत्याशित विकास के कारण वैश्विक स्तर पर कोकिंग कोयले की कीमत में वृद्धि हुई है। हालाँकि, उन देशों में कोकिंग कोयले की कीमत वैश्विक कोकिंग कोयले की कीमत के अनुरूप नहीं बढ़ी, जहाँ यह घरेलू स्तर पर उपलब्ध था। चूंकि ऑस्ट्रेलिया में घरेलू स्तर पर प्रचुर मात्रा में कोकिंग कोयला उपलब्ध है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के उत्पादकों को अन्य देशों और विशेष रूप से भारत के उत्पादकों पर तुलनात्मक लाभ था, जहां उत्पादक बड़े पैमाने पर ऑस्ट्रेलियाई कोयले के आयात पर निर्भर हैं। ऑस्ट्रेलियाई उत्पादक कम कीमत पर मेट कोक का उत्पादन करने में सक्षम थे और इसे इतनी बढ़ी हुई मात्रा में और कम कीमतों पर भारत में निर्यात करने में सक्षम थे जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान हो सकता था।
160. प्राधिकृत अधिकारी इस तथ्य का संज्ञान लेता है कि 2019-20 के दौरान घरेलू उद्योग को चोट एनआईएनएल द्वारा व्यापारी बाजार में कम कीमतों पर मेट कोक की बिक्री के कारण हुई थी और ऐसी क्षति भारत में आयात के कारण नहीं थी जो कि भी है घरेलू उद्योग द्वारा कहा गया। हालाँकि, उद्योग अवधि, यानी 2022-23 में ऐसा नहीं है। 2022-23 के दौरान घरेलू उद्योग को नुकसान अप्रत्याशित विकास के कारण भारत में आयात में वृद्धि के कारण हुआ।
161. यह भी ध्यान दिया जाता है कि यद्यपि भारत में घरेलू उत्पादकों ने कुछ अनुकूल कीमतों पर रूस से कोकिंग कोयला आयात किया होगा, लेकिन रूसी कोकिंग कोयला भारत में कोकिंग कोयले के कुल आयात का एक नगण्य हिस्सा है। अन्य इच्छुक पार्टियों का तर्क है कि जिंदल कोक लिमिटेड ने अपनी संबंधित इकाई से कोकिंग कोयला खरीदा होगा, प्राधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि जिंदल कोक लिमिटेड ने जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड से कोकिंग कोयला नहीं खरीदा है, जिसका दावा घरेलू उद्योग द्वारा किया गया है और द्वारा सत्यापित किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी।
162. प्राधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उत्पादकों ने उच्च कीमतों पर कोकिंग कोयला खरीदा है, लेकिन भारत में मेट कोक के आयात की मात्रा में वृद्धि के कारण मेट कोक के उत्पादन के लिए इसका उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। जब कोकिंग कोयले की कीमतों में गिरावट आई, तो घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत ऊंची रही क्योंकि उसके पास ऊंची कीमतों पर खरीदे गए कोकिंग कोयले का भंडार था। यदि भारत में आयात नहीं बढ़ा होता, तो घरेलू उद्योग उसी अवधि के दौरान खरीदे गए कोकिंग कोयले का उपभोग करने और बाजार में मेट कोक बेचने में सक्षम होता। इस प्रकार, मेट कोक के आयात में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
163. प्रभाव मूल्यांकन पर प्रस्तुतीकरण के संबंध में, प्राधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि वर्तमान जांच मात्रात्मक प्रतिबंधों के रूप में उपायों को लागू करने के संबंध में है, न कि शुल्क लगाने के लिए, ऐसे प्रतिबंधों से पिग आयरन जैसे डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।, स्टील आदि। इसके अलावा, चूंकि लौह मिश्र धातु उद्योग द्वारा उपयोग किए जा रहे उत्पाद को पहले ही उपायों के दायरे से बाहर रखा गया है, इसलिए ऐसे उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, उपायों की सिफारिश केवल एक वर्ष की अवधि के लिए की जाती है और भारत में मांग-

आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है, जिससे भारत में उत्पाद की कमी या मनमानी कीमत हो सकती है। इसके अलावा, जबकि मात्रात्मक प्रतिबंधों से भारत में आयात की मात्रा कम हो जाएगी, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित कोटा मांग-आपूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखता है। मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी भारत में विचाराधीन उत्पाद की पर्याप्त आपूर्ति होगी।

164. देश विशिष्ट कोटा देने और सुरक्षा उपाय (क्यूआर) से पोलैंड को बाहर करने के संबंध में अन्य इच्छुक पार्टियों के तर्क को उपरोक्त निष्कर्षों में पहले ही संबोधित किया गया है। आगे यह दोहराया गया है कि विवाद के विपरीत, अधिसूचना सं. 12/2021 - सीमा शुल्क (एनटी) दिनांक 1 फरवरी 2021 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि टैरिफ दर कोटा वैश्विक या देश विशिष्ट हो सकता है लेकिन वर्तमान जांच टैरिफ दर कोटा के संबंध में नहीं है बल्कि मात्रात्मक कोटा के संबंध में है। वर्तमान जांच विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत शुरू की गई है, न कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के तहत। सुरक्षा (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमों के नियम 11, उपायों को गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर लागू किया जाना है।
165. अन्य इच्छुक पार्टियों का यह तर्क कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उचित मात्रा में विचाराधीन उत्पाद का आयात घरेलू उत्पादकों को होने वाली क्षति के लिए जिम्मेदार है, तर्कसंगत नहीं है। इसके अलावा, अन्य इच्छुक पार्टियों ने घरेलू उद्योग द्वारा आयात के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्राधिकृत अधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। किसी भी मामले में, घरेलू उद्योग द्वारा आयात उन्हें सुरक्षा उपायों के लिए याचिका दायर करने से अयोग्य नहीं ठहराता है।
166. अन्य हितबद्ध पक्षों का यह तर्क कि सस्ते विकल्पों की उपलब्धता के बावजूद महंगे ऑस्ट्रेलियाई कोकिंग कोयले की खरीद के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ, बिना किसी सबूत के महज एक दावा है। जैसा कि ऊपर पैराग्राफ में बताया गया है, ऑस्ट्रेलिया से कोकिंग कोयले का भारतीय कोकिंग कोयले के आयात में बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने कहा है कि कोकिंग कोयले के ग्रेड या किस्म का आयात विचाराधीन उत्पाद की तकनीकी आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। इसे निम्न ग्रेड या प्रकार के सस्ते विकल्पों से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।
167. अल्ट्रा-लो फॉस मेट कोक को बाहर करने के संबंध में अन्य इच्छुक पार्टियों का तर्क स्वीकार किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया उत्पाद "0.030% तक फॉस्फोरस सामग्री के साथ कम राख धातुकर्म कोक, 30 मिमी के आकार के साथ फेरोलॉयल विनिर्माण में उपयोग के लिए 5% आकार सहनशीलता के साथ है"। इसके अलावा, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विचार किए गए आयात डेटा और पृथक्करण पद्धति के संबंध में प्रस्तुतियाँ, यह नोट किया गया है कि DGCIS डेटा 4-अंकीय स्तर पर खरीदा गया था और विचाराधीन उत्पाद के विवरण के आधार पर विश्लेषण किया गया था। केवल 18% से कम राख सामग्री वाले कम राख वाले धातुकर्म कोक से संबंधित लेनदेन पर विचार किया गया है।
168. अल्ट्रा-लो फॉस मेट कोक को बाहर करने के संबंध में अन्य इच्छुक पार्टियों के तर्क को स्वीकार कर लिया गया है। विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया उत्पाद "0.030% तक फॉस्फोरस सामग्री के साथ कम राख धातुकर्म कोक, 30 मिमी के आकार के साथ फेरोलॉयल विनिर्माण में उपयोग के लिए 5% आकार सहनशीलता के साथ है"। उक्त उत्पाद को आयात करने के लिए, आयातक को फेरोलॉयल के निर्माण के लिए उत्पाद का वास्तविक उपयोग दिखाना होगा। 18% से कम राख सामग्री वाले मेट कोक के अधिकृत अधिकारी द्वारा विचार किए गए डेटा के संबंध में अन्य तर्क यह है कि 4 अंकों के स्तर पर खरीदे गए डीजीसीआई एंड एस डेटा का विचाराधीन उत्पाद के विवरण के आधार पर 8 अंकों के स्तर पर विश्लेषण किया गया था।
169. इस तर्क के संबंध में कि ब्लास्ट फर्नेस के लिए उपयोग किए जाने वाले 40 मिमी आकार के मेट कोक को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, प्राधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि अन्य इच्छुक पार्टियों ने स्वयं प्रस्तुत किया है कि ऐसे उत्पाद का निर्माण और आपूर्ति की जा रही है घरेलू उद्योग द्वारा। उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में, प्राधिकृत अधिकारी का कहना है कि आयातित मेट कोक की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। हालाँकि, एक प्रीमियम गुणवत्ता वाला उत्पाद आम तौर पर उच्च कीमतों पर बेचा जाता है, न कि वर्तमान स्थिति में कम कीमतों पर। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि आयातित उत्पाद उच्च गुणवत्ता का है। तदनुसार, इस संबंध में किसी बहिष्कार की आवश्यकता नहीं है।
170. इस तर्क के संबंध में कि ब्लास्ट फर्नेस के लिए उपयोग किए जाने वाले 40 मिमी आकार के मेट कोक को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, प्राधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि अन्य इच्छुक पार्टियों ने स्वयं प्रस्तुत किया है कि ऐसे उत्पाद का निर्माण और आपूर्ति की जा रही है घरेलू उद्योग द्वारा। उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में,

प्राधिकृत अधिकारी का कहना है कि आयातित मेट कोक की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। हालाँकि, एक प्रीमियम गुणवत्ता वाला उत्पाद अधिक कीमतों पर बेचा जाता है, न कि कम कीमतों पर। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि आयातित उत्पाद उच्च गुणवत्ता का है। तदनुसार, इस संबंध में किसी बहिष्कार की आवश्यकता नहीं है।

171. समग्र डेटा प्रदान न करने के लिए प्रकटीकरण विवरण में गोपनीयता के संबंध में, यह कहा गया है कि प्रासंगिक आर्थिक मापदंडों को प्रभावित करने वाले प्रमुख रुझान सभी इच्छुक पार्टियों को प्रदान किए गए हैं। इच्छुक पक्ष इस पर टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र थे। इसलिए, किसी भी इच्छुक पार्टी पर ऐसी गोपनीयता का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
172. समग्र डेटा प्रदान न करने के लिए प्रकटीकरण विवरण में गोपनीयता के संबंध में, यह कहा गया है कि प्रासंगिक आर्थिक मापदंडों को प्रभावित करने वाले प्रमुख रुझान सभी इच्छुक पार्टियों को प्रदान किए गए हैं। इच्छुक पक्ष इस पर टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र थे। हालाँकि, प्राधिकृत अधिकारी नोट करता है कि प्रासंगिक आर्थिक मापदंडों का समग्र डेटा प्रदान किया जाना चाहिए और इस अंतिम निष्कर्ष में इसका खुलासा किया गया है।
173. अन्य इच्छुक पार्टियों ने प्रस्तुत किया है कि लंबवत एकीकृत उत्पादक भी बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। प्राधिकृत अधिकारी का कहना है कि नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड ने अपने इस्पात संयंत्र के बंद होने के कारण ही व्यापारिक बाजार में प्रवेश किया। इसके अलावा, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से पता चलता है कि उसे केवल अपने कोक ओवन संयंत्रों को बनाए रखने के लिए व्यापारी बाजार में मेट कोक बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिन्हें लगातार संचालित करना पड़ता है। इसके अलावा, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा विषय वस्तु को बहुत कम कीमत पर बेचने के बाद से संबद्ध वस्तु के व्यापारी उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अलावा, स्टील प्लांट को बंद करना और ऐसे उत्पादकों का व्यापारी बाजार में प्रवेश एक काल्पनिक तर्क है और भारतीय उद्योग, चाहे वह व्यापारी हो या बंदी, को उसी रूप में देखा जाना चाहिए जैसे वह अस्तित्व में है।
174. प्राधिकृत अधिकारी अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा स्थिति के संबंध में प्रस्तुतियों पर विचार न करने के संबंध में प्रस्तुतियों को नोट करता है। प्राधिकृत अधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग की स्थिति सबसे हाल की अवधि के आधार पर निर्धारित की जाती है, न कि संपूर्ण क्षति अवधि के आधार पर। यह प्राधिकृत अधिकारी की पिछली प्रथा रही है और वर्तमान जांच में भी इसका पालन किया गया है। घरेलू उद्योग की स्थिति से संबंधित अन्य मुद्दों को संबंधित अनुभागों में उचित रूप से निपटाया गया है।
175. इच्छुक पार्टियों ने अनुच्छेद 4.1(सी) के तहत समान या सीधे प्रतिस्पर्धी शब्द की व्याख्या के संबंध में प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणियों के माध्यम से एक तर्क उठाया है, जिसमें यह प्रस्तुत किया गया है कि अनुच्छेद 4.1(सी) के तहत "या" शब्द का उपयोग किया गया है। ग) को "और" के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, जो इंगित करता है कि उत्पादित सामान या तो समान या सीधे प्रतिस्पर्धी होना चाहिए और दोनों नहीं होना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) पैनल - बड़े आवासीय वांशर के आयात पर सुरक्षा उपाय के पास एक तुलनीय मुद्दे को संबोधित करने का अवसर था। अपने विचार-विमर्श में, पैनल ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"उस निर्धारण को करने में, हमें विस्तृत रूप से यह परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है कि अनुच्छेद 4.1 (सी) के तहत "पसंद" का क्या मतलब हो सकता है या क्या नहीं, विशेष रूप से यह देखते हुए कि मसौदा तैयार करने वालों ने सुरक्षा उपायों पर समझौते में इस शब्द को परिभाषित नहीं करने का विकल्प चुना है। इसके बजाय, हमें यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या अनुच्छेद 4.1(सी) यूएसआईटीसी को यह पता लगाने से रोकता है कि आयातित और घरेलू हिस्से उत्पाद की तरह थे, यह देखते हुए कि दोनों प्रतिस्पर्धी नहीं करते थे। अनुच्छेद 4.1(सी) की समग्र रूप से अनुच्छेद 4 के संदर्भ में व्याख्या करने से हमें पता चलता है कि जो उत्पाद एक-दूसरे के साथ किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी संबंध में नहीं हैं, वे एक-दूसरे को गंभीर चोट या खतरा पैदा नहीं कर सकते हैं। विशेष रूप से, हम ध्यान दें कि अनुच्छेद 4.1(सी) "चोट या उसके खतरे का निर्धारण करने में" वाक्यांश के साथ खुलता है, जो अनुच्छेद 4, विशेष रूप से अनुच्छेद 4.2(ए) और 4.2(बी) द्वारा प्रदान किए गए समग्र संदर्भ के साथ, सुझाव देता है कि घरेलू उद्योग को इस तरीके से परिभाषित किया जाना चाहिए जिससे जांच प्राधिकारी यह निर्धारित कर सके कि क्या बड़े हुए आयात के कारण उस उद्योग को गंभीर क्षति होने का खतरा है या नहीं। जिस हद तक एक जांच प्राधिकारी को पता चलता है कि दो उत्पाद किसी भी प्रतिस्पर्धी संबंध में नहीं हैं, हम यह नहीं देखते हैं कि एक घरेलू उद्योग को इस तरह से कैसे परिभाषित किया जाता है जो बाद में यह निर्धारित करने की संभावना को बाहर कर देता है कि बड़े हुए आयात के कारण गंभीर क्षति हुई है या होने का खतरा है। वह घरेलू उद्योग (समान उत्पाद के उत्पादकों के आधार पर परिभाषित, जिसके यहां कवर किए गए हिस्से हैं) अनुच्छेद 4.1(सी) के अनुरूप होगा।"

176. विवाद में डब्ल्यूटीओ पैनल द्वारा प्रदान की गई व्याख्या सुरक्षा जांच प्रक्रिया के भीतर प्रतिस्पर्धा पर विचार करने के महत्व को रेखांकित करती है। यह पहलू विचाराधीन उत्पाद और परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग दोनों को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण है। सुरक्षा समझौते के अंतर्गत घरेलू उद्योग की परिभाषा "चोट या उसके खतरे का निर्धारण करने में" वाक्यांश से शुरू होती है, जो प्राधिकृत अधिकारी को प्रश्न में उत्पाद की प्रतिस्पर्धात्मकता का आकलन करने के लिए सशक्त बनाती है। यह मूल्यांकन यह निर्धारित करने के लिए अभिन्न है कि चोट लगी है या नहीं।
177. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और व्याख्या में सुसंगतता बनाए रखने के लिए, यह पुष्टि की जाती है कि कैप्टिव उत्पादन, आयात के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं होने के कारण, आयातित वस्तुओं के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में लगे घरेलू उत्पादकों को होने वाली क्षति में योगदान नहीं देता है। इसलिए, वर्तमान संदर्भ में कुल घरेलू उत्पादन का निर्धारण करने में, केवल उन उत्पादकों को ध्यान में रखा जाता है जो ऐसी वस्तुओं की बिक्री करते हैं जो सीधे प्रतिस्पर्धी हैं और कानून के तहत परिकल्पित हानिकारक प्रभावों के अधीन हैं। इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों में घरेलू उद्योग का गठन करने वाले समान या सीधे प्रतिस्पर्धी सामानों का एक बड़ा हिस्सा कैप्टिव उत्पादन को छोड़कर व्यापारी बाजार में उद्योग के उत्पादन के आधार पर मूल्यांकन करने का प्रस्ताव है।
178. प्रतिस्पर्धात्मकता और प्रतिस्पर्धा की अवधारणाओं के बारे में प्रकटीकरण के संबंध में, और संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में अपीलीय निकाय रिपोर्ट पर निर्भरता - पाकिस्तान से कॉम्ब्ड कॉटन यार्न पर संक्रमणकालीन सुरक्षा उपाय, यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त मामला कपड़ा और परिधान पर समझौते के तहत लगाए गए उपायों से संबंधित है। हालाँकि, यह ध्यान रखना उचित है कि कपड़ा और परिधान पर समझौता 2005 में समाप्त कर दिया गया था और अब प्रभावी नहीं है। दूसरे, अपीलीय निकाय द्वारा प्रदान की गई व्याख्या एक अलग संदर्भ में थी और कपड़ा और परिधान पर समझौते का पाठ भी सुरक्षा उपायों के समझौते के पाठ से अलग है।
179. इसके विपरीत, वर्तमान जांच सुरक्षा उपाय समझौते के तहत एक सुरक्षा उपाय से संबंधित है। विशेष रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) पैनल - बड़े आवासीय वांशर के आयात पर सुरक्षा उपाय ने सुरक्षा समझौते के अनुच्छेद 4.1 (सी) के तहत एक समान मुद्दे को संबोधित किया। यह देखते हुए कि वर्तमान जांच में एक सुरक्षा उपाय भी शामिल है, उपरोक्त डब्ल्यूटीओ निर्णय कपड़ा और वस्त्र पर निष्क्रिय समझौते की तुलना में अधिक प्रासंगिकता और महत्व रखता है।
180. इसलिए, सुरक्षा उपायों से संबंधित डब्ल्यूटीओ के निर्णय पर भरोसा करना और विचार करना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि यह सीधे वर्तमान जांच के संदर्भ और प्रकृति से मेल खाता है, जबकि कपड़ा और वस्त्र पर समझौता अब लागू नहीं है।
181. अन्य इच्छुक पार्टियों ने प्रस्तुत किया है कि यदि कम कीमत वाले आयात का घरेलू उद्योग पर प्रभाव पड़ता हुआ पाया जाता है, तो उचित उपाय एंटी-डंपिंग उपाय या सब्सिडी-विरोधी उपाय होने चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति अप्रत्याशित विकास के कारण आयात में अचानक, तेज, महत्वपूर्ण और हालिया वृद्धि के कारण हुई है।

N. निष्कर्ष

182. आवेदन के विश्लेषण के आधार पर, यह देखा गया है कि:

- क. भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात में अचानक, तीव्र, महत्वपूर्ण और हाल ही में वृद्धि हुई है।
- ख. अप्रत्याशित विकास के कारण पूर्ण और सापेक्ष रूप से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- ग. विचाराधीन उत्पाद के आयात से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही थी और घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर दबाव पड़ रहा था।
- घ. भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।
- ङ. घरेलू उद्योग को हाल की अवधि में वित्तीय लाभ, नकद लाभ, नियोजित पूंजी पर नकारात्मक रिटर्न जैसे विभिन्न मापदंडों पर गंभीर चोट लगनी शुरू हो गई है।
- च. घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात में वृद्धि के कारण हुई है।
- छ. मात्रात्मक प्रतिबंधों के रूप में सुरक्षा उपाय लागू करना सार्वजनिक हित में होगा। इससे घरेलू उद्योग को होने वाली गंभीर क्षति से बचाया जा सकेगा, जबकि डाउनस्ट्रीम उद्योग पर नगण्य और सहनीय प्रभाव पड़ेगा क्योंकि

आयात के साथ-साथ भारतीय उद्योग के पास बड़ी क्षमताओं के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं की मांग पूरी होती रहेगी।

ण. सिफारिश:

183. उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि:

- क. विचाराधीन उत्पाद, यानी कम राख वाले मेटलर्जिकल कोक को भारत में इतनी बड़ी हुई मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में आयात किया गया है, जिससे समान वस्तु का निर्माण करने वाले घरेलू उद्योग को गंभीर चोट लगने का खतरा है या हो सकता है।
- ख. हाल के समय में घरेलू उद्योग को गंभीर चोट लगनी शुरू हो गई है।
- ग. मौजूदा परिस्थितियाँ घरेलू उद्योग को और गंभीर क्षति से बचाने के लिए मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने को उचित ठहराती हैं।

184. तदनुसार, प्राधिकृत अधिकारी निम्नलिखित उपायों की सिफारिश करता है:

- (i) विचाराधीन उत्पाद के आयात को विनियमित किया जाता है और नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित स्तरों से अधिक की अनुमति नहीं है। यह मात्रा सुरक्षा उपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमों के नियम 9(1) के संदर्भ में निकाली गई है, जो जांच की अवधि के दौरान तीन प्रतिनिधि वर्षों में आयात के औसत के आधार पर, यानी 2019-20, 2020-21 है। और 2021-22, वृद्धि अवधि, यानी 2022-23 पर विचार किए बिना। हालाँकि, कोटा को समायोजित किया गया है और वृद्धि की अवधि से पहले की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उच्चतम क्षमता उपयोग के अनुरूप मांग-आपूर्ति, मांग वृद्धि और मांग-आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया गया है। घरेलू उद्योग की क्षमता का उपयोग।
- (ii) विचाराधीन उत्पाद, यदि अन्य विकासशील देशों में उत्पादित किया जाता है (नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित को छोड़कर), अनुशंसित उपायों के अधीन नहीं होगा क्योंकि वे नियमों के तहत निर्धारित सीमा से नीचे हैं।
- (iii) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने फ़ाइल संख्या वाली एक अधिसूचना जारी की थी। 01/92/180/106/एएम-11/पीसी-VI/पीआरए दिनांक 31 जनवरी 2013 जिसमें इसने एफटीडीआर अधिनियम, 1992 की धारा 9ए(4)(ए) के तहत विकासशील देशों की एक सूची अधिसूचित की थी। यह अधिसूचना आधारित थी राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना पर। हालाँकि, प्राधिकृत अधिकारी ने नोट किया है कि विकासशील देशों की सूची को बाद में राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 19/2016-सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 5 फरवरी 2016 के माध्यम से संशोधित किया गया है। नीचे सूचीबद्ध विकासशील देशों से आयात के मामले में उक्त अधिसूचना संख्या 19/2016-सीमा शुल्क (एन.टी.), व्यक्तिगत रूप से 3% और सामूहिक रूप से 9% से अधिक नहीं है, ऐसे आयात पर विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 9 ए (1) के संदर्भ में मात्रात्मक प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
- (iv) प्राधिकृत अधिकारी लो एंश मेटलर्जिकल कोक के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करता है।
- (v) आवंटित कोटा की इलेक्ट्रॉनिक/वास्तविक समय निगरानी की सुविधा के लिए केवल ईडीआई बंदरगाहों के माध्यम से आयात की अनुमति दी जाएगी। कोटा की निगरानी त्रैमासिक आधार पर की जाएगी। किसी भी तिमाही में अनुमत कुल आयात उस तिमाही और अगली तिमाही के कुल आयात से अधिक नहीं होगा। किसी तिमाही के लिए कोई भी अप्रयुक्त कोटा अगली तिमाही में जोड़ा जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्यातक और संबंधित आयातक वॉल्यूम को सुचारू रूप से विनियमित करने में सक्षम होंगे। इस प्रकार, इस तरह से कोटा का आवंटन यह सुनिश्चित करेगा कि उपयोगकर्ताओं, आयातकों और निर्यातकों को कोई अनुचित कठिनाई न हो। यदि आवश्यक हो, तो प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के अनुसार, ऐसे मात्रात्मक प्रतिबंधों को नियंत्रित करने के लिए और तौर-तरीके अधिसूचित किए जा सकते हैं।
- (vi) तदनुसार, प्राधिकृत अधिकारी, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9ए(1) के अनुसार, एक वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित उत्पाद के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करता है। एफटीडीआर अधिनियम के तहत अधिसूचना की तारीख।

“कम ऐश मेटलर्जिकल कोक, यानी, मेटलर्जिकल कोक जिसमें 18% से कम राख सामग्री होती है, जो एचएस कोड 2704 के अंतर्गत आता है, जिसमें कोक फाइन्स / कोक ब्रीज़ और 0.030% तक फॉस्फोरस सामग्री के साथ अल्ट्रा-लो फॉस्फोरस मेटलर्जिकल कोक और 30 मिमी के आकार के साथ 5 शामिल नहीं हैं। लौहमिश्र धातु निर्माण में उपयोग के लिए % आकार सहनशीलता”

देश	Q1	Q2	Q3	Q4	कुल
ऑस्ट्रेलिया	25,638	25,638	25,638	25,638	1,02,553
चीन पीआर	39,323	39,323	39,323	39,323	1,57,292
कोलंबिया	1,24,886	1,24,886	1,24,886	1,24,886	4,99,542
इंडोनेशिया	33,182	33,182	33,182	33,182	1,32,729
जापान	1,04,990	1,04,990	1,04,990	1,04,990	4,19,960
पोलैंड	2,53,168	2,53,168	2,53,168	2,53,168	10,12,672
कतर	810	810	810	810	3,239
रूस	44,591	44,591	44,591	44,591	1,78,365
सिंगापुर	23,239	23,239	23,239	23,239	92,955
स्विट्ज़रलैंड	40,887	40,887	40,887	40,887	1,63,549
यूके	38	38	38	38	152
अन्य	22,831	22,831	22,831	22,831	91,325
कुल	7,13,583	7,13,583	7,13,583	7,13,583	28,54,334

विकासशील देशों की सूची

- क. अफ़ग़ानिस्तान
- ख. अल्बेनिया
- ग. अल्जीरिया
- घ. अंगोला
- ङ. अर्मेनिया
- च. अज़रबैजान
- छ. बांग्लादेश
- ज. बेलारूस
- झ. बेलीज़
- ञ. बेनिन
- ट. भूटान
- ठ. बोलीविया (बहुसंख्यक राष्ट्र)
- ड. बोस्निया और हर्ज़ेगोविना
- ढ. बोत्सवाना
- ण. ब्राजील

त.	बल्गारिया
थ.	बुर्किना फ़ासो
द.	बुरुंडी
ध.	कैबो वेर्दे
न.	कंबोडिया
त.	कैमरून
प.	मध्य अफ़्रीकी गणराज्य
फ.	चाड
ब.	कोमोरोस
भ.	कांगो
म.	कोस्टा रीका
य.	कोट डी आइवोआर
र.	क्यूबा
र.	उत्तर कोरिया की लोकतांत्रिक गणराज्य
ल.	कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य
ळ.	जिबूती
ळ.	डोमिनिका
व.	डोमिनिकन गणराज्य
श.	इक्वाडोर
ष.	मिस्र
स.	अल साल्वाडोर
ह.	इरिट्रिया
कक.	इथियोपिया
खख.	फ़िजी
गग.	गैबोन
घघ.	गाम्बिया
ङङ.	जॉर्जिया
चच.	घाना
छछ.	ग्रेनाडा
जज.	ग्वाटेमाला
झझ.	गिनी
ञञ.	गिनी-बिसाउ
टट.	गुयाना
ठठ.	हैती

डड.	होंडुरास
ढढ.	ईरान (इस्लामी गणराज्य)
णण.	इराक
तत.	जमैका
थथ.	जॉर्डन
दद.	कजाखस्तान
धध.	केन्या
नन.	किरिबाती
तत.	किर्गिज़स्तान
पप.	लाओ लोकतांत्रिक गणराज्य
फफ.	लेबनान
बब.	लेसोथो
भभ.	लाइबीरिया
मम.	लीबिया
यय.	मादागास्कर
रर.	मलावी
रर.	मलेशिया
लल.	मालदीव
ळळ.	माली
ळळ.	मार्शल द्वीपसमूह
वव.	मॉरिटानिया
शश.	मॉरिशस
षष.	मेक्सिको
सस.	माइक्रोनेशिया (संघीय राज्य)
हह.	मंगोलिया
ककक.	मोंटेनीग्रो
खखख.	मोरक्को
गगग.	मोजांबिक
घघघ.	म्यांमार
डडड.	नामीबिया
चचच.	नेपाल
छछछ.	निकारागुआ
जजज.	नाइजर
झझझ.	नाइजीरिया

जजज.	पाकिस्तान
टटट.	पालाऊ
ठठठ.	पालेस्टाइन
डडड.	पनामा
ढढढ.	पापुआ न्यू गिनी
णणण.	पारागुए
ततत.	पेरू
थथथ.	फिलीपींस
ददद.	मोल्डोवा गणराज्य
धधध.	रोमानिया
ननन.	रवांडा
ततत.	सेंट लूसिया
पपप.	सेंट विन्सेंट और ग्रेनाडाईस
फफफ.	सामोआ
बबब.	साओ टोमे और प्रिंसिपे
भभभ.	सेनेगल
ममम.	सर्बिया
ययय.	सियेरा लियोन
ररर.	सोलोमन द्वीपसमूह
ररर.	सोमालिया
ललल.	दक्षिण अफ्रीका
ळळळ.	दक्षिण सूडान
ळळळ.	श्रीलंका
ववव.	सूडान
शशश.	सूरिनाम
षषष.	स्वाज़ीलैंड
ससस.	सीरियाई अरब गणराज्य
हहह.	ताजिकिस्तान
कककक.	थाईलैंड
खखखख.	पूर्वी युगोस्लाव गणराज्य का मैसेडोनिया
गगगग.	तिमोर-लेस्ते
घघघघ.	टोगो
डडडड.	टोंगा
चचचच.	ट्यूनीशिया

छछछछ. तुर्की
जजजज. तुर्कमेनिस्तान
झझझझ. तुवालू
ञञञञ. संयुक्त अरब अमीरात
टटटट. युगांडा
ठठठठ. यूक्रेन
डडडड. संघीय गणराज्य तंजानिया
ढढढढ. उज़्बेकिस्तान
णणणण. वानुआतू
तततत. वियतनाम
थथथथ. यमन
दददद. जाम्बिया
धधधध. ज़िम्बाब्वे

अनन्त स्वरूप, प्राधिकृत अधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2024

Case No - SG (QR) - 04/2023

FINAL FINDING

Subject: Safeguard (Quantitative Restrictions) investigation concerning imports of Low Ash Metallurgical Coke into India.

A. BACKGROUND OF THE CASE

- F. No. 22/4/2023-DGTR.**—1. An application dated 04th April 2023 was filed before the Authorized Officer under Section 9A of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (hereinafter also referred to the “Act”) read with the Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012 (hereinafter also referred to as the “Quantitative Restrictions Rules” or the “Rules”) by BLA Coke Private Ltd., Jindal Coke Ltd., Saurashtra Fuels Private Ltd., Vedanta Malco Energy Ltd. and VISA Coke Ltd. (hereinafter also referred to as the “applicants” or the “domestic industry”) seeking imposition of safeguard measures in the form of quantitative restrictions on imports of “Low Ash Metallurgical Coke” (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or “PUC” or “subject goods” or “Met Coke”) into India.
2. The applicants have alleged that the product under consideration is being imported into India in such increased quantities and under such conditions as to cause injury to the domestic industry that is producing like or directly competitive goods in India. For this reason, the applicants had requested for imposition of Safeguard (Quantitative Restrictions) as a measure to mitigate its injury, for a period of one year.

3. In view of the duly substantiated petition filed by the applicants and sufficient *prima facie* evidence submitted regarding recent, sudden, sharp and significant increase in imports of the subject goods and consequent serious injury to the domestic industry, a safeguard investigation against imports of the product under consideration into India under the provisions of Section 9A of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 and Rule 5 of the Quantitative Restrictions Rules, for examining the need for imposition of safeguard measures in the form of quantitative restrictions, was initiated vide Notification No 22/4/2023-DGTR dated 30th June 2023.

B. PROCEDURE

4. In accordance with sub-rules (2) and (3) of Rule 6 of the said Rules, a copy of the initiation notification dated 30th June 2023 and a copy of a non-confidential version (NCV) of the application filed by the applicants were forwarded to the Central Government in the Ministry of Commerce & Industry, the Governments of major exporting countries through their embassies in India, and the interested parties mentioned in the said application.
5. A questionnaire to be answered by the exporters / importers / domestic producers as prescribed under Rule 6(4) of the said Rules, was forwarded to the known interested parties with a request to make their views known in writing within 30 days from the date of issue of the Notice of Initiation.
6. In response to the Notification of Initiation the following interested parties filed a response to the exporters' questionnaire:
 - i. Balta GmbH
 - ii. BlueScope Steel (AIS) Pty Ltd.
 - iii. Cheongfuli (Xiamen) Co. Ltd.
 - iv. China National Minerals Co. Ltd.
 - v. PT. Detian Coking Indonesia
 - vi. PT. Kinrui New Energy Technologies Indonesia
 - vii. PT. Kinxiang New Energy Technologies Indonesia
 - viii. PT. Risun Wei Shan Indonesia
 - ix. Qingdao Sion Coke Rich International Trade Co. Ltd.
 - x. Risun Marketing Ltd.
 - xi. Sinochem International Corporation
 - xii. Union Yiwua International Trade Co., Ltd.
 - xiii. Xiamen Guqiyang Supply Chain Co., Ltd.
 - xiv. Xiamen ITG Dynamic Co., Ltd
7. In response to the Notification of Initiation the following interested parties filed response to users' / importers' questionnaire:
 - i. Orissa Metaliks Private Ltd.
 - ii. Jayaswal Neco Industries Ltd.
 - iii. Tata Steel Ltd.
 - iv. Tata Steel Mining Ltd.
 - v. Sunflag Iron and Steel Company Ltd.
 - vi. Mukand Ltd
 - vii. ArcelorMittal Nippon Steel India Ltd.
 - viii. Balmukund Sponge and Iron Private Ltd.
 - ix. Indian Metals and Ferro Alloys Ltd.
 - x. Narsingh Ispat Ltd.
 - xi. Neo Metaliks Ltd.
 - xii. SMC Power Generation Ltd.
 - xiii. Sree Metaliks Ltd.
 - xiv. Swati Concast and Power Private Ltd.
8. In response to the Notification of Initiation the following interested parties filed submissions:
 - i. Alloy Steel Producers Association of India (ASPA)

- ii. Balta GmbH
 - iii. BlueScope Steel (AIS) Pty Ltd
 - iv. China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers and Exporters
 - v. Government of Indonesia
 - vi. Jayaswal Neco Industries Ltd.
 - vii. Mukand Ltd.
 - viii. Orissa Metaliks Private Ltd.
 - ix. Sunflag Iron and Steel Co. Ltd
 - x. Tata Steel Ltd &. Tata Steel Mining Ltd.
9. In response to the Notification of Initiation the following interested parties filed response to economic interest questionnaire:
- i. Domestic industry
 - ii. Narayani Coke Private Ltd.
 - iii. ArcelorMittal Nippon Steel India Ltd.
 - iv. Balmukund Sponge and Iron Private Ltd.
 - v. Balta GmbH
 - vi. BlueScope Steel (AIS) Pty Ltd
 - vii. Cheongfuli (Xiamen) Co. Ltd.
 - viii. China National Minerals Co. Ltd.
 - ix. Indian Metals and Ferro Alloys Ltd.
 - x. Narsingh Ispat Ltd.
 - xi. Neo Metaliks Ltd.
 - xii. Qingdao Sion Coke Rich International Trade Co. Ltd.
 - xiii. Risun Marketing Ltd.
 - xiv. Sinochem International Corporation
 - xv. SMC Power Generation Ltd.
 - xvi. Sree Metaliks Ltd.
 - xvii. Swati Concast and Power Private Ltd.
 - xviii. The Indian Ferro Alloy Producers' Association (IFAPA)
 - xix. Union Yiwua International Trade Co., Ltd.
 - xx. Xiamen Guqiyang Supply Chain Co., Ltd.
 - xxi. Xiamen ITG Dynamic Co., Ltd
10. The Authorized Officer has considered the most recent period as 1st April 2022 – 31st March 2023 and the period of investigation as 1st April 2019 – 31st March 2023.
11. A list of interested parties was published on the DGTR website to enable access of all non-confidential version (NCV) submissions made by all interested parties. All interested parties were advised to exchange the non-confidential version of their submissions with each other through email.
12. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authorized Officer provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 17th January 2024 in hybrid mode i.e. both virtual and physical. The parties which wished to join online participated through Digital Video Conferencing. All the interested parties who participated in the oral hearing were requested to file written submission of the views presented orally. Interested parties were also given an opportunity to file rejoinders, if any, to the written submissions of other interested parties. The following interested parties had filed written submissions and rejoinder submissions post the oral hearing.
- i. Domestic industry
 - ii. Alloy Steel Producers Association
 - iii. Arcelor Mittal Nippon Steel Ltd.

- iv. Balmukund Sponge and Iron Private Ltd.
 - v. Balta GmbH
 - vi. BlueScope Steel (AIS) Pty Ltd.
 - vii. China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters
 - viii. European Commission
 - ix. Government of Indonesia
 - x. Indian Metals and Ferro Alloys Ltd
 - xi. Jayaswal Neco Industries Ltd.
 - xii. Mukand Ltd.
 - xiii. Narsingh Ispat Ltd.
 - xiv. Neo Metaliks Ltd.
 - xv. Orissa Metaliks Pvt. Ltd.
 - xvi. PT. Detian Coking Indonesia
 - xvii. PT. Kinrui New Energy Technologies Indonesia
 - xviii. PT. Kinxiang New Energy Technologies Indonesia
 - xix. PT. Risun Wei Shan Indonesia
 - xx. Russian Federation
 - xxi. SMC Power Generation Ltd.
 - xxii. Sree Metaliks Ltd.
 - xxiii. Sunflag Iron and Steel Co. Ltd.
 - xxiv. Swati Concast and Power Private Ltd.
 - xxv. Tata Steel Ltd.
 - xxvi. Tata Steel Mining Ltd.
13. The submissions made by all interested parties pursuant to the oral hearing or otherwise, to the extent the same are substantiated with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authorized Officer in this disclosure statement.
 14. The Authorized Officer, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this disclosure statement to the extent possible and verified the data/ documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant, practicable and necessary.
 15. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authorized Officer has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non- confidential version of the information filed on confidential basis.
 16. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authorized Officer considered such interested parties as non-cooperative and recorded this disclosure statement on the basis of the facts available.
 17. Request was made to the Director General (Systems) to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the period of investigation.
 18. *** in this final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authorized Officer under the Rules.
 19. The exchange rate adopted by the Authorized Officer for the subject investigation is 1US\$ = ₹ 81.06.
- C. SCOPE OF PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**
- C1. SUBMISSIONS BY THE OTHER INTERESTED PARTIES**
20. The following submissions were made by the other interested parties with regards to product under consideration and like article.

- a. Since domestic industry is unable to produce Low Ash Metallurgical Coke with phosphorous content upto to 0.030% and size upto 30 mm with oversize limited to 5%, it should be excluded from the scope of the PUC. The exclusion was agreed by the domestic industry during the oral hearing.
- b. Ultra-Low Phos. Coke (ULP) [Phos: $\leq 0.007\%$, S:0.65%, FC:84-86%, 10-30mm]; Ultra Ultra Low Phos. Coke (UULP), [Phos: $\leq 0.005\%$, S:0.65%, FC:84-86%, 10-30 mm]; Ultra Low Phos. Coke Fines (ULPC) [Phos: $\leq 0.007\%$, S:0.65%, FC:85-89%, 0-6mm] should be excluded.
- c. While the applicants agreed on exclusion of low phos coke having phosphorus content less than 0.03 and particle size upto 30 mm during the oral hearing, the condition of particle size upto 30 mm is not relevant and should not be considered.
- d. Met coke with size upto 40 mm with 5% tolerance should be excluded as it is not available in abundant quantities domestically. Since only this size can be used in mini-blast furnaces and limited volume is imported, quantitative restrictions will have an adverse impact on the pig iron manufacturers as they will be forced to break bigger size coke to smaller sizes leading to increase in cost.
- e. The domestic industry is not involved in production of coke fines / coke breeze. Coke fines supplied by the domestic industry have high ash and volatile matter content. The related party of one of the applicants itself imports coke fines to supply to the other interested parties. Thus, such coke fines with low ash content should be excluded from the scope of the product under consideration as agreed by the domestic industry during the oral hearing.
- f. The met coke supplied by the Indian industry is of inferior quality as compared to imported coke. The domestic coke contains higher moisture leading to higher fuel demand, has lower coke strength after reduction and higher coke reactivity index, mean particle size is on lower side and the -30 mm and -25 mm fractions are on higher side, size of domestic coke was below norms set by Arcelormittal Nippon Steel India Limited. Using sub-standard quality of met coke in the production process results in reduced hot metal production. There are other safety concerns as well including taphole choking, coke rush, personnel safety, equipment damage, operational disruptions etc.
- g. Considering of HS code 2704 for analysis of met coke import is not appropriate as it consists of various types of coal and the product under consideration is classified only under 2704 00 30.
- h. HS code 2704 does not indicate the ash content. In India coke with low ash content contains ash up to 11%, with middle ash content contains up to 18% and with high ash content contains upto 25%. Since coke with up to 14% ash content can be used in blast furnaces. It seems that the applicants have incorrectly used customs data on 4-digit code to include all types of coke.

C2. SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

21. The submissions of the domestic industry with regard to the product under consideration and like article are as follows:
 - a. The product under consideration in the present investigation is Low Ash Metallurgical Coke having ash content below 18%. In order to produce met coke with low ash content, the only requirement is low ash coking coal.
 - b. The product under consideration is imported under various names such as coke, nut coke, semi-coke of coal, BF coke, foundry coke, coke breeze, metallurgical breeze coke, coke fines, coke dust, coke ash powder, coke powder and carbon coque / coque.
 - c. The products imported under the names carboflux, carbon block, carbon anode butts, carbon raiser, carbon raised, bags, semi coke of lignite or peat, lignite special coke, non-activated charcoal, carbolux, CTF065 SASCARB are not a part of the product under consideration.
 - d. The domestic industry has not manufactured ultra-low phos metallurgical coke with phosphorous content below 0.03% and size below 30 mm for use in ferroalloy applications due to economic unviability and such product may be excluded from application of quota when the importers show the use of said product for manufacturing of ferroalloys.
 - e. Coke breeze / fines are not produced by any manufacture globally but is a by product generated while producing coke. Since the domestic industry has not produced low-ash coke breeze / fines, the same may be excluded from the scope of the product under consideration.
 - f. As opposed to the contentions of the other interested parties, quality cannot be the reason for surge in imports. Further, in case the imports were of superior quality the prices of the product would have been higher.

- g. With regard to the submissions on exclusion of met coke with size upto 40 mm, the said product is being produced by the Indian industry and does not call for exclusion.
- h. For the purposes of the present investigation, the HS classification is only indicative in nature, as has been provided in the initiation notification. The information submitted is relevant only to the product under consideration and the application has in no manner reported any statistic on an article which is not representative of the product under consideration.
- i. Met coke is classified under the HS Code 2704 0030. However, it is also being imported under HS Codes 2704 0010, 2704 0020, 2704 0030 and 2704 0090. Accordingly, HS Code 2704 may be considered for notification of measures.
- j. As opposed to the submissions of the other interested parties, only transactions pertaining to low ash metallurgical coke with ash content below 18% have been considered for determination of increase in imports, and injury to the domestic industry.

C3. EXAMINATION BY THE AUTHORISED OFFICER

- 22. The product under consideration for the purpose of the present investigation is Low Ash Metallurgical Coke, that is, Metallurgical Coke having ash content below 18%. The product is commonly known as Met Coke or Coke in the market parlance. Metallurgical Coke with high ash content, that is, ash content above 18% is outside the scope of the product under consideration.
- 23. The other interested parties have requested exclusion of ultra-low phosphorous low ash metallurgical coke with low phosphorous content upto 0.030% and size below 30 mm. The domestic industry has submitted that the production of such product does not need any new equipment or plant; and requires only a specific type of coking coal. The domestic industry has however accepted exclusion of metallurgical coke with low phosphorous content upto 0.030% and size upto 30 mm with oversize tolerance of 5%. The Authorized Officer notes that the domestic industry has not manufactured the said product stating commercial unviability of the same. Such product is used for manufacturing of ferroalloys. Hence, the Authorized Officer proposes to hold that ultra-low phosphorous metallurgical coke with phosphorous content below 0.03% and size upto 30 mm with oversize tolerance of 5% will not be subject to any quantitative restrictions.
- 24. With regard to the coke fine / coke breeze, the Authorized Officer notes that the domestic industry has agreed for exclusion of low ash coke fines / coke breeze, as the same is not produced by it. Accordingly, the Authorized Officer proposes to hold that the scope of product under consideration does not include low-ash coke fines / coke breeze, that is, coke fines / coke breeze with ash content of upto 18%.
- 25. The other interested parties have submitted that met coke with size upto 40 mm should be excluded from the scope of product under consideration. The Authorized Officer notes that the other interested parties have themselves stated that the said product is available in India and is being supplied by the domestic industry. The other interested parties have not substantiated their claims with regards to availability of such product in limited quantities. Accordingly, it is considered that the need for exclusion of the met coke with size upto 40 mm has not been substantiated.
- 26. With regard to the submissions of the other interested parties regarding the HS Codes, it is noted that the product under consideration is being imported under various HS Codes. The import data under 4-digit level at 2704 pertaining to metallurgical coke has been segregated on the basis of description of the product as 'low ash Metallurgical Coke having ash content below 18%' at 8-digit level.
- 27. The other interested parties have submitted that the quality of the product supplied by the domestic industry is inferior. The Authorized Officer notes that the other interested parties have not substantiated their claims by providing evidence for the same. Further, in case of superior quality product, a producer usually charges a premium as the users will not switch to an inferior quality product due to pricing policy. In the present case, the imports are undercutting the prices of the domestic industry and hence, the submissions with regard to superior quality of imports is not justified.
- 28. It is also noted that in past anti-dumping investigations pertaining to the product, the Authorised Officer had found that the domestic industry was producing like article to the imported product. In a safeguard investigation, it is required to be examined whether the domestic industry has produced like or directly competitive product, to the imported goods. No evidence has been placed by the interested parties to displace or dispute the conclusions reached in the past investigations. Further, no party has claimed that the goods produced by the domestic industry are not, competing with the imported products. Therefore, the Authorized Officer finds that the information on record does not indicate a difference in quality of the products.
- 29. On the basis of the information on record the following is the product under consideration for the present investigation

“Low Ash Metallurgical Coke, that is, Metallurgical Coke having ash content below 18% excluding coke fines / coke breeze and ultra-low phosphorous metallurgical coke with phosphorous content up to 0.030% with size of 30 mm with 5% size tolerance for use in ferroalloy manufacturing”

There is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and those imported into India. They are comparable in terms of physical characteristics, manufacturing process, functions and uses, product specifications, distribution and marketing, and tariff classifications of the goods. The goods produced by the domestic industry are also technically and commercially comparable to the product being imported. The consumers have used and are using the two interchangeably. The Authorised Officer proposes to hold that the product manufactured by the applicants constitutes like goods to the subject goods being imported into India in terms of Rule 2(e) of the Rules.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D1. SUBMISSIONS BY THE OTHER INTERESTED PARTIES

30. The following submissions were made by the other interested parties with regards to domestic industry and standing:

- a. In a safeguard investigation, the only condition for constitution of domestic industry is a major share in total production. There are no exclusions to be considered as that in an anti-dumping investigation. The Authorised Officer, in the safeguard investigation into imports of Isopropyl Alcohol held that there is no exclusion of a producer who imports the subject goods.
- b. The Authorised Officer may re-examine the standing in the present case after including the producers that manufacture the subject goods as an intermediate product.
- c. In order to determine standing, the production of all entities producing met coke, regardless of captive or merchant market, should be considered. The Appellate Body in US – Cotton Yarn held that while determining the major share of domestic production, captive consumers cannot be excluded. The captive producers import 73% of coking coal in India and produce majority of the product under consideration.
- d. Captive consumers of the product cannot be excluded for determination of total production of met coke in India. The applicants have relied upon the decision of the Authorised Officer and CESTAT decision in the anti-dumping investigation on imports of met coke. The definition of domestic industry under Safeguard Rules does not allow for consideration of two or more competitive markets where producers could be considered as separate industry, as opposed to the definition under the Anti-Dumping Rules.
- e. While the applicants have claimed that the captive producers do not mention met coke as a product on their website, RINL and Sathavahana Ispat Ltd. have mentioned the product on their website. Sathavahana Ispat Ltd. and Bengal Energy Ltd. is engaged in sales of met coke in merchant market as evident from the final findings issued by the Authorised Officer in anti-dumping investigation on imports of met coke from Australia and China. In case, production of such producers is added to total domestic production, the share of applicants will be even lower.
- f. A share of 33.46% cannot be considered as a major share in the total domestic production. The present industry is not a fragmented industry as evident from the fact that the applicants have provided a list of all domestic producers. A low share in domestic production will not permit representative and objective examination of serious injury to the domestic industry.
- g. The applicants have not provided information regarding their share in total domestic production during April 2019 – March 2023. Standing should be determined based on the share in production during the complete injury period.
- h. The share in domestic production of applicants in the anti-dumping investigation was higher than that in the present investigation. Further, the applicants in the anti-dumping investigation, are still operational (barring Gujarat NRE Coke Ltd) but have not participated in the present investigation. Since the information required in a safeguard investigation is less burdensome, it is not clear why other producers have not provided the information.
- i. In Argentina – Poultry, the Panel held that major means important, serious, or significant and the domestic industry refers to domestic producers whose collective output constitutes more than 50% of domestic production. In EC-Fasteners (China), the Appellate Body held that a proportion of 36% of total domestic production is low, even in the context of the fragmented fasteners industry. In EC Steel Fasteners, the Appellate Body held that a major proportion should be understood as a relatively high proportion of the total domestic production. In the present investigation major share implies more than 51% of total domestic production, however, the applicants hold only 33.63% of the total domestic production.

- j. In more than 35 safeguard investigations conducted by the Authorised Officer, the Authorised Officer has held major share as constituting more than 50% of total production. As per para 4.9.2 of the Manual of Operating Practices, total domestic production should consist of entire production in India including production for domestic sales, exports as well as captive consumption. In anti-dumping investigation into imports of O-Acid, the Authorised Officer held that absence of actual merchant sales in the period of investigation should not deprive the company from being treated as domestic industry.
- k. While the applicants have identified supporters, there is no concept of supporters in a safeguard investigation. Thus, production of such producers cannot be considered for the purpose of determining standing.
- l. Supporters have not provided their data. The Authorised Officer must conduct a further examination into the state of performance of the additional producers and Indian industry as a whole. This is necessary since the sales of other domestic producers is higher than the sales of the domestic industry.
- m. The supporters have not provided information as per Trade Notice No. 13/2018.
- n. The applicants have admitted that the information regarding total domestic production is estimated, however, the basis of such estimation has not been provided.

D2. SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

31. Following submissions have been made by the applicants with regard to the domestic industry and standing:

- a. The petition has been filed by BLA Coke Private Ltd., Jindal Coke Ltd., Saurashtra Fuels Private Ltd., Vedanta Malco Energy Ltd., and VISA Coke Ltd.
- b. The petition has been supported by Bhatia Coke and Energy Ltd., Krishna Coke India Private Ltd., Mothersons Consolidate, M V International Ltd., Nilachal Carbo Metalicks Private Ltd., Tirupati Traders, Coromandel Met Coke Industries and Narayani Coke Private Ltd.
- c. The applicants constitute 39% of Indian merchant production. Along with the supporters, the applicants account for 49% of the total production in India.
- d. Contrary to the submissions of the other interested parties, Trade Notice 13/2018 is not applicable to safeguard investigations.
- e. As opposed to the contentions of the other interested parties, the WTO Panel in Argentina – Poultry held that there is no need for the Members to define domestic industry as producers pertaining to more than 50% of domestic production. Appellate Body in EC-Fasteners (China) dealt with self-selection of producers.
- f. While the other interested parties have submitted that the scope of domestic industry in an anti-dumping investigation was larger, there is no requirement for the constitution of domestic industry to remain the same in a safeguard investigation.
- g. Contrary to the submissions of the other interested parties, the domestic industry has provided its production during the period of investigation as well total Indian production.
- h. While production of Tata Steel Ltd. and members of Dhanbad association were considered for the purpose of standing while filing the petition, these should not be considered as Tata Steel produces for captive consumption and members of Dhanbad Association produce NPUC.
- i. As opposed to the submissions of other interested parties, production of Bengal Energy Ltd. and Sathavahana Ispat Ltd. to the tune of that for the merchant market have been considered in total Indian production. Mere listing of product by RINL does not mean that all steel manufacture recognize it as a product and show it on the their website.
- j. There are three types of producers in India which include MSME industry producing high ash met coke, organised sector and few MSME companies producing the like goods for merchant market and captive producers of the product.
- k. There are at least 17 producers of the product producing met coke captively. Steel manufacturers producing met coke for captive use must not be considered for the purpose of the present investigation as they are essentially consumers of the product, they do not recognize met coke as a product, they do not compete in the merchant market and are insulated from the merchant market situation.
- l. The steel manufacturers do not specify met coke as a product on their website. The merchant market prices for met coke vis-à-vis coking coal does not impact the steel manufacturers.
- m. Captive producers should not be treated as the domestic industry which is consistent as per the objective of safeguard laws, anti-dumping laws and practice of the Authorised Officer.

- n. In the anti-dumping investigation on imports of low ash metallurgical coke, producers who were captively consuming the product were not treated as part of the domestic industry.
- o. There are notable differences in the economics of merchant producers and captive producers. The merchant producers face competition from other merchant producers, both domestic and foreign, while captive producers faced no such competition. Merchant producers are required to gain a return on investment on the subject goods produced and sold in the market to maintain viability of their plant, the captive producers require profits and return on investment on the downstream product.
- p. As opposed to the contentions of the other interested parties, major share of domestic production has to be defined on case-to-case basis. The Authorised Officer has considered less than 50% as major share in safeguard investigations.
- q. The application has been filed by the major producers of like goods in India. All other producers are small in terms of individual production of the product.

D3. EXAMINATION BY THE AUTHORISED OFFICER

32. The submissions made by the domestic industry and other interested parties with regard to the domestic industry and their standing were considered and the main issues raised were definition of domestic industry, meaning of major proportion and the locus standi of the applicants.

Domestic industry: Section 9A4(b) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 defines domestic industry as:

*“(b) domestic industry means the **producers of goods** (including producers of agricultural goods) –*

*(i) as a whole of the **like goods or directly competitive goods in India; or***

*(ii) whose **collective output of the like goods or directly competitive goods in India constitutes a major share of the total production of the said goods in India.**”.*

33. The Agreement on Safeguards under Article 4 i.e. Determination of Serious Injury or Threat Thereof has defined that for the purpose of this agreement:

*(c) in determining injury or threat thereof, a domestic industry shall be understood to mean the producers as a whole of the **like or directly competitive products** operating within the territory of a Member, or those whose collective output of the **like or directly competitive products** constitutes a major proportion of the total domestic production of those products*

It is noted that comprehending the precise delineation of the term "a major proportion of the total production" as stipulated within the safeguard agreement necessitates a thorough comprehension of the contextual framework of production so as to ascertain what constitutes total domestic production and thereby a major proportion.

34. It is noted that neither the safeguard agreement nor the FTDR Act defines the term production. The term domestic industry in the agreement on safeguards has been defined under the Heading Serious Injury and therefore the interpretation of the term production and a major proportion cannot be done in isolation.
35. It is noted that though the Agreement on Safeguards and FTDR Act is silent with regards to the definition of the term production but there are other statutes encompassing such definitions which include, among others, the Factories Act of 1948, the Special Economic Zone Act of 2005, the Central Excise Act of 1944, the Consumer Protection Act of 1986, the Beedi and Cigar Workers Act of 1966, the Standard of Weights and Measures Act of 1976, and the Foreign Trade Policy. Notably, the definitions of production articulated within these statutes exhibit substantial variations. These diverse laws and regulations have attributed differing meanings to the concept of production, as discernible from the disparate interpretations evident across various legislative provisions. It is further noted that the determination of production's meaning necessitates due consideration of the specific laws and regulations in question, including the definitions and interpretations proffered therein, alongside an examination of the underlying objectives and purposes for which said laws were promulgated. Of particular relevance is the observation that under excise law, the completion of certain ancillary activities, such as packaging, labeling, or treating goods for consumer marketability, suffices to qualify as production. However, such activities do not necessarily fulfill the criteria for production under safeguard law or FTDR Act. Therefore, imposition of a universal definition of the term production would be untenable and needs to be determined or ascertained on a case-by-case basis with underlying objectives of the different statutes.
36. In the Agreement on Safeguards under Article 4.1(c) the domestic industry has been referred to as producers of the like or **directly competitive products**. While there is no issue with respect to like goods, the Agreement stipulates that the goods shall be directly competitive. Since, the domestic industry has been defined under the heading **Serious Injury or Threat Thereof**, the purpose of the determination of the domestic production shall mean to be those domestic goods which are in direct competition with the imports and facing serious injury or threat thereof.

37. While arguments have been posited advocating the inclusion of captive production within the ambit of total domestic production, it is noted that such goods, by their nature, do not enter the merchant market and thus do not directly compete with imported products. Captively produced goods, not being in competition with imports, do not meet the criteria delineated for directly competitive goods under the Agreement, Act and associated Rules.
38. Moreover, a strict literal interpretation of the term "total domestic production," divorced from the overarching purpose and legislative intent encapsulated within the Act, engenders ambiguity. The potential for ambiguity arises in situations where the majority (80%) of a like article is produced captively, with only a minority portion of the domestic production by the domestic producers (20%) being in the merchant market and thus facing competition from the imported product under consideration. Such an interpretation of total domestic production to include captive production would render the domestic producers constituting the 20% minority share of total domestic production, who are actively engaged in merchant market sales and thus directly competing with the imported product under scrutiny, devoid of any recourse under the Law. This outcome would be antithetical to the underlying purpose and intent of the FTDR Act, which is designed to redress serious injury inflicted upon domestic producers by sudden sharp and significant import surges.
39. In *US – Lamb*¹, the Appellate Body concurred with the finding of the Panel that, in the context of an investigation in which the relevant like product was defined as lamb meat, the term "domestic industry" could not be interpreted as including growers and feeders of live lambs. The Appellate Body began by identifying the analytical approach towards defining "domestic industry"

"[A] safeguard measure is imposed on a specific 'product', namely, the imported product. The measure may only be imposed if that specific product ('such product') is having the stated effects upon the 'domestic industry that produces like or directly competitive products'. (emphasis added) The conditions in Article 2.1, therefore, relate in several important respects to specific products. In particular, according to Article 2.1, the legal basis for imposing a safeguard measure exists only when imports of a specific product have prejudicial effects on domestic producers of products that are 'like or directly competitive' with that imported product. In our view, it would be a clear departure from the text of Article 2.1 if a safeguard measure could be imposed because of the prejudicial effects that an imported product has on domestic producers of products that are not 'like or directly competitive products' in relation to the imported product. Accordingly, the first step in determining the scope of the domestic industry is the identification of the products which are 'like or directly competitive' with the imported product. Only when those products have been identified is it possible then to identify the 'producers' of those products."

40. It is further noted that the Authorised Officer in the past has also underscored the same principle while excluding the producers of SEZ from total domestic production while determining the standing in terms of major proportion under safeguard agreement in the matter of safeguard investigation concerning imports of "Solar Cells whether or not assembled in modules or panels"² into India which is as under:

"Though section 2(i) of SEZ Act does not specifically mention about DTA clearances by a SEZ unit as an import in the DTA, but such clearances are subjected to duties like Anti-dumping duty, Countervailing duty and Safeguard duty as applicable in accordance with section 9A and section 8B of the Custom tariff Act, 1975. Section 30 of SEZ Act, 2005 stipulating collection of applicable Anti-dumping, Countervailing and Safeguard duties requires filing of a bill of entry which validates the fact that such DTA clearances are infact to be treated as imports. Therefore, the following is concluded:

- (i) *The fundamental objective of establishing SEZ units is promotion of exports governed by a specific SEZ Act, 2005. The area of SEZ are excluded from the definition of DTA under section 2(i) of SEZ Act, 2005. Supply of goods from DTA to SEZ constitutes exports.*
- (ii) *DTA sale of goods manufactured by a SEZ unit can be made only on submission of import licence, as applicable to the import of similar goods into India. Sale or clearance of goods from SEZ to DTA is subject to various duties i.e. Anti-dumping duty, Countervailing duty and Safeguard duty imposed as per section 9 and 8B respectively as per Custom Tariff Act, 1975 and levied as per Section 30 of SEZ Act, 2005. 126*
- (iii) *(EOU's are governed by specific Foreign Trade Policy provisions and its sales to SEZ units are considered as export. The Foreign Trade Policy provisions also apply to DTA units as well as to those who wish to undertake imports/exports. Further DTA clearances by an EOU are liable for payment of applicable Excise duties/taxes. They operate outside the SEZ territories quite analogous to normal DTA units in the same ecosystems*

¹Appellate Body Report, *US – Lamb*, paras. 86-87

²<https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Solar-Final-Finding-English-0.pdf>

- (iv) *Therefore, on the basis of the above, I hold that the provision of Sales to DTA by a SEZ unit as an exception with features varying in different cases, does not justify a SEZ unit to be considered as a domestic producer in the context of trade remedial measures keeping in view the context of the larger framework of SEZ Act, 2005.*

Therefore, the scope of DI in this investigation is restricted only to the producers i. e. M/s Indosolar Limited (EOU) and M/s Jupiter Solar Power Limited, which includes the EOU unit also, since they are physically located in DTA governed by Foreign Trade Policies though with export orientation. (v) With the exclusion of 3 SEZ units, the DI is now restricted to M/s Indosolar Limited and M/s Jupiter Solar Power Limited which collectively account for 38% of the total domestic production in the DTA”.

41. It is further noted that even the references sought from the decisions of WTO reports establish important principle regarding the inclusion and assessment of captive consumption in domestic industry production for safeguard investigations. The Appellate Body has also acknowledged that captive consumption can be included in production calculations. However, it emphasized the need for proportionality. What is inferred through a reading on the decisions of WTO panel and appellate body reports is that the captive consumption shouldn't automatically be added, it needs justification. Authorities must assess the proportion of captive consumption relative to total production. Only significant proportions that distort the analysis should be excluded. Including disproportionately large amounts of captive consumption could artificially inflate the domestic industry's size and its apparent injury from imports. This could lead to unjustified safeguard measures harming legitimate trade.

42. In consonance with the precedent and to maintain coherence in interpretation, it is affirmed that captive production, not being in competition with imports, does not contribute to injury faced by domestic producers **engaged in direct competition** with imported goods. Hence, in determining total domestic production within the present context, only producers vending like goods which are directly competitive and are subject to the injurious effects envisioned under the law are factored. Therefore, a major proportion of the like or directly competitive goods constituting the domestic industry in the facts of the present case is assessed based on the production of the industry in the merchant market excluding the captive production.

43. As regards the issue of major proportion, it is noted that The Panel in *US –Wheat Gluten*³ addressed the link between the phrase "major proportion" and the question of data coverage

"The Agreement expressly envisages that, in certain circumstances, the 'domestic industry' may consist of those domestic producers 'whose collective output of the like or directly competitive products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products'. This implies that complete data coverage may not always be possible and is not required. While the fullest possible data coverage is required in order to maximize the accuracy of the investigation, there may be circumstances in a particular case which do not allow an investigating Authorised Officer to obtain such coverage."

44. The Panel in *US – Lamb*⁴ also pointed out that an incorrect determination of what constitutes the "domestic industry" will likely vitiate also the representativeness of data related to such incorrectly determined domestic industry:

"This lack of representativeness is likely compounded by the fact that the USITC defined the domestic industry broadly as including growers and feeders, as the conclusions drawn from the data pertaining to only a small proportion of US growers and feeders are central to the USITC's overall finding of threat of serious injury."

45. Based on the above precedents and interpretations established by the World Trade Organization (WTO) Appellate Body, it can be deduced that the concept of "a major proportion" in defining the domestic industry does not adhere to a strict threshold. Rather, the crux lies in ensuring that the data provided by domestic producers is sufficiently representative to evaluate the criteria of serious injury and the potential threat thereof.

46. As regards the contention of major proportion in view of the standing of the domestic industry under Article 4 (c) of the Safeguard Agreement, it is noted that Article 4 of Agreement on Safeguard Measures reads as under:

47. "For the purposes of this Agreement:

- a) "serious injury" shall be understood to mean a significant overall impairment in the position of a domestic industry;
- b) "threat of serious injury" shall be understood to mean serious injury that is clearly imminent, in accordance with the provisions of paragraph 2. A determination of the existence of a threat of serious injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility; and;

³ Panel Report, *US – Wheat Gluten*, paras. 8.54-8.56

⁴ Panel Report, *US – Lamb*, para. 7.219

- c) In determining injury or threat thereof, a "domestic industry" shall be understood to mean the producers as a whole of the like or directly competitive products operating within the territory of a Member, or those whose collective output of the like or directly competitive products constitutes a major proportion of the total domestic production of Those products.
48. As can be seen from the above, Article 4.1(c) of the Agreement on Safeguards provides two options for the definition of the "domestic industry" (i) "the producers as a whole of the like or directly competitive products"; or (ii) the producers whose output constitutes "a major proportion" of the total domestic production of the like or directly competitive products. It is noted that unlike anti-dumping agreement, the Agreement on Safeguards does not provide any specific percentage or share of the domestic production, which would meet the requirement of "a major proportion". Neither does it establish any methodology or procedure that competent authorities must follow for determining a major proportion of the total domestic production. The consideration as to what constitutes "a major Proportion" depends on the specific circumstances of each case.
49. "The Appellate Body has also clarified, in the context of a similar provision in the Anti-Dumping Agreement, that the term "major proportion" means "a relatively high proportion of the total domestic production". The term "major proportion" has both "quantitative and qualitative connotations". The qualitative element aims to ensure that "the domestic producers of the like product that are included in the definition of domestic industry are representative of the total domestic production". The Appellate Body has stated that there is "an inverse relationship" between the proportion of total production included in the domestic industry and the existence of a material risk of distortion in the definition of domestic industry and in the assessment of injury.
50. Specifically, "the lower the proportion, the more sensitive an investigating Authorized Officer will have to be to ensure that the proportion used substantially reflects the total production of the producers as a whole". At the same time, "the higher the proportion, the more producers will be included, and the less likely the injury determination conducted on this basis would be distorted".
51. Further the Panel in US - Wheat Gluten addressed the link between the phrase "major proportion" and the question of data coverage: "[T]he Agreement expressly envisages that, in certain circumstances, the 'domestic industry' may consist of those domestic producers 'whose collective output of the like or directly competitive products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products'. This implies that complete data coverage may not always be possible and is not required. While the fullest possible data coverage is required in order to maximize the accuracy of the investigation, there may be circumstances in a particular case which do not allow an investigating Authorized Officer to obtain such coverage.
52. The Panel in US - Lamb made clear that a national Authorized Officer is not under an obligation to collect information from all domestic producers so as to ensure the representativeness of the data used for its final determination. Nevertheless, the Panel invoked, among other things, the need for a "statistically valid sample. "Major proportion relates to the representativeness of the data pertaining to the condition of the industry. "
53. Hence, the primary concern for an investigating Authorized Officer lies in the condition of the industry, and the data utilized should sufficiently reflect the true status of domestic producers. This entails both quantitative and qualitative analyses. It could be argued that when the data coverage of domestic producers falls below 50%, there is a heightened risk of inaccurately assessing serious injury, however in absence of any percentage threshold it is the quantitative and qualitative analyses that acquires primacy.
54. In the current investigation, the applicants previously furnished a roster of producers detailing their production capacities and respective shares in the overall domestic production. Subsequently, a revised list has been provided by the applicants wherein certain industries have been excluded from the scope of domestic producers for the product under consideration, either due to their status as traders or their non-production of the subject goods. Upon revising such data, the percentage share of the applicant producers in total domestic production rises to 53%, while that of supporters ascends to 14%. Even if the argument raised by other interested parties regarding percentage thresholds is considered, the applicant producers still comprise 53% of the total domestic production and when combined with the supporters, their collective percentage share reaches 67% as per the revised data, thereby meeting the criteria for standing of the domestic industry.
55. However, at this juncture, even though the domestic industry has provided a revised production data, the Authorized officer does not take it into consideration as it has been revised at the fag end of the investigation i.e. post issuance of the disclosure statement. Nevertheless, the Authorized Officer, in alignment with the jurisprudential framework delineated by the World Trade Organization (WTO) concerning Article 4(c) of the Safeguards Agreement, maintains that the applicant producers encompass a blend of large-scale enterprises and Micro, Small, and Medium-sized Enterprises (MSMEs). This composition resembles the roster of non-participating producers, thereby rendering the applicant industry sufficiently representative to delineate the current state of domestic producers in its entirety. Further, it is worth noting, that no specific percentage threshold has been defined by the legislature concerning the standing of the domestic industry under the

principle of major proportion, as outlined in Article 4(c) of the safeguards agreement. Rather, it is the representativeness of the industry that requires scrutiny to ensure that the applicant industries accurately reflect the prevailing conditions of the existing industry, thereby enhancing the precision of the injury determination process. In the instant investigation, the amalgamation within the cohort of applicant producers mirrors the extant state of the industry, satisfying both qualitative and quantitative analyses. Consequently, it cannot be precluded on grounds of standing pursuant to the principle of major proportion as outlined in Article 4(c) of the safeguards agreement. In light of the foregoing, the Authorized Officer holds that the applicant producers indeed constitute a major proportion as stipulated under Article 4(c) of the Safeguard Agreement.

E. CONFIDENTIALITY

E1. Submissions by other interested parties

56. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality.

- a. The applicants have claimed excessive confidentiality as aggregate data for sales value, employees, productivity per day, inventories, PBIT, interest / finance cost, depreciation and amortisation expense have not been shared.

E2. Submissions by the domestic industry

57. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality:

- a. As opposed to the submissions of the other interested parties, actual information regarding prices, cost and profitability would allow the customers to negotiate on the prices of the applicants and would have an adverse impact on the performance of the petitioners. Hence, the same has not been shared.

E3. Examination by the Authorised Officer

58. With regard to confidentiality of the information, the Rule 7 of the Rules provides as follows:

“Confidential information-

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (3) and (7) of rule 6, and sub-rule (5) of rule 9, any information which is by nature confidential or which is provided on a confidential basis shall, upon cause being shown, be treated as such by the Authorised Officer and not be disclosed without specific authorisation of the party providing such information.

(2) The Authorised Officer may require the parties providing information on confidential basis to furnish non confidential summary thereof and if, in the opinion of the party providing such information, such information cannot be summarised, such party may submit to the Authorised Officer a statement of reasons why summarisation of such information is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the Authorised Officer is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is unwilling either to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information unless it is demonstrated to its satisfaction from appropriate sources that such information is correct.”

59. The non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties has been made available by directing the interested parties to share the non-confidential version of the submissions with each other through e-mails.
60. The domestic industry has provided some information in its application on confidential basis and has requested that it be treated as confidential. The domestic industry has also provided a non-confidential version (NCV) of its application, as required under the Rules. Further, the domestic industry has submitted reasons justifying their claim of confidentiality of this information.
61. Some of the interested parties have claimed that the applicants have claimed excessive confidentiality by not providing aggregate data regarding profitability, interest / finance cost, depreciation and amortization expenses. The Authorized Officer holds that sharing of confidential parameters will have an adverse impact on the business interests of the domestic industry and provide competitive advantage to the competitors and consumers. It will allow the customers to evaluate whether they are paying higher or lower prices other than customers and it may lead to customers demanding lower prices. Further, as a practice, the Authorised Officer has allowed interested parties to claim such information as confidential, on good cause being shown. In view of the same, the Authorized Officer has accepted the confidentiality claimed by the domestic industry.
62. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the confidentiality claims have been accepted, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties.

F. MISCELLANEOUS ISSUES**F1. Submissions by other interested parties**

63. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties:
- The applicants have not produced substantive evidence for initiation of the investigation and the Authorised Officer has not carried out appropriate and enough scrutiny to the facts available.
 - The domestic industry is a habitual user of trade remedies and intends to limit import competition by permanently seeking trade remedial measures.
 - The applicants have not disclosed the source of import data. The import data seems unreliable as the applicants have stated that certain descriptions have not been considered as imports of the product under consideration. However, published DGCI&S data does not disclose the description of the product.
 - Since the volume of imports prior to 2019-20 was higher than the imports in the injury period, determining quota based on imports in 2019-20, 2020-21 and 2021-22 will severely impact the availability of the product under consideration in India. The Authorised Officer may kindly consider three representative years prior to 2019-20.
 - The applicants have not provided clarification regarding the duration for measures requested in post-initiation submissions. In case, the measures requested are for more than one year, an adjustment plan should be provided by the applicants.
 - There is no legal basis to determine quota without including the surge period. There has been a recent increase in demand for the product under consideration, quota which is not representative of demand-supply gap will be detrimental to the downstream industry.

F2. Submissions by the domestic industry

64. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:
- The other interested parties have not pointed out the evidence which has not been provided by the domestic industry.
 - As opposed to the contentions of the other interested parties, the Authorised Officer recommended anti-dumping duty only after conducting a detailed investigation and concluded that the exporters are engaged in unfair trade practices.
 - The applicants have provided DGCI&S published data, however, the Authorised Officer will rely on DGCI&S transaction by transaction data.
 - Contrary to the submissions of the other interested parties, historical data is irrelevant in the present investigation and quota should be based on the past practice of the Authorised Officer.
 - The applicants have requested measures for a period of one year.
 - It is a consistent practice of the Authorised Officer to determine quota based on previous three years.

F3. Examination by the Authorised Officer

65. With regards to the contention that the investigation was initiated based on information unsubstantiated with evidence, it is noted that the applicants have provided a duly substantiated application, based on which the present investigation was initiated. The investigation was initiated only after *prima facie* satisfaction regarding the existence of sufficient evidence. No evidence has been provided by interested parties to dispute any material information provided by the domestic industry at the stage of initiation, or to dispute the *prima facie* conclusions drawn by the Authorized Officer at such stage.
66. The other interested parties have submitted that the domestic industry is a habitual user of trade remedies. It is however, noted that the domestic industry has filed an application with substantive evidence of increased imports, due to unforeseen developments, causing serious injury to the domestic industry. The remedial measures will be taken as per the safeguard rules on case by case basis.
67. With regards to the source of import data, as stated in the procedure part hereinabove, transaction-wise data received from DGCI&S has been relied upon for the purpose of the present investigation.
68. The other interested parties have submitted that the quota should be based on imports prior to 2019-20. The Authorized Officer notes that the practice of the Authorised Officer is to determine quota based on average imports in three years prior to the surge period. The imports may have been higher prior to 2019-20. However, the market situation has changed post COVID-19. The demand in India has also changed substantially pre and post COVID-19. The Authorized Officer would recommend any measures as per prevailing rules.

G. INCREASE IN IMPORTS**Submissions by the other interested parties**

69. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to increase in imports:
- a. The Appellate Body in Argentina – Footwear held that the increase in imports should be recent, sudden, sharp, and significant, both quantitatively and qualitatively. Thus, such requirements must be cumulatively satisfied, and it is not sufficient if only one or two of these criteria are met.
 - b. The Authorised Officer must determine surge based on the complete injury period and not just the previous year. The Appellate Body in US –Lamb held that entire trend for the period of investigation should be taken into consideration, rather than isolating the data of the most recent period and evaluating it separately.
 - c. Imports from Poland did not undergo any sudden, sharp and recent increase as opposed to imports into India from other countries. The applicants have not explained how increase in prices of coal leads to increase in imports from Poland to India. Imports from Russia have declined over the injury period and imports from all other sources are also declining.
 - d. The exporter from Poland has exported under long-term agreement and such exports have not been impacted by any unforeseen development. The imports from the exporter actually declined and was lowest during the most recent period. Thus, Poland / exporter should be excluded from imposition of quantitative restrictions.
 - e. Imports have primarily increased from China, thus, Quantitative Restrictions on all imports into India is not the appropriate remedy.
 - f. Imports have increased majorly from China. The exports from China had declined in 2020-21 and 2021-22 due to COVID-19 but as soon as the economy recovered, the exports from China increased. Such increase was also due to the reason that demand for met coke had increased in Indian steel industry.
 - g. There is no surge in the volume of imports since imports did not increase in comparison to the total period of investigation. Increase in imports during the most recent period is only due to normalization of trade post COVID-19. The imports have actually declined as compared to imports in 2016-17, 2017-18 and 2018-19.
 - h. The imports from Indonesia account for a very low share of total imports. The price of imports from Indonesia fluctuated with the market condition but remained stable overall.
 - i. Imports into India have increased due to increase in production of crude steel.
 - j. The imports in 2020-21 and 2021-22 declined due to effect of COVID-19. The imports in India increased by only 20% as compared to 2019-20 which is normal rate of increase considering the growth in demand.
 - k. Since Rule 9 of the Safeguard (QR) Rules states that the Authorized Officer should recommend the extent and nature of Quantitative Restrictions adequate for prevention of serious injury, the Authorised Officer may exclude a specific country from imposition of Quantitative Restrictions. Even the global safeguard (tariff-rate quota) may be imposed against specific country.

G.2 SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

70. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to increase in imports:
- a) There is a sudden, sharp, and significant increase in imports of the product under consideration as a consequence of unforeseen developments.
 - b) The share of the product under consideration has increased significantly in relation to the production and consumption in India.
 - c) Imports have primarily increased from China, Australia, Indonesia, Switzerland, Singapore and UAE. However, Switzerland, Singapore and UAE do not have manufacturing facilities, hence, such imports are transshipment of goods.
 - d) As opposed to the contention of the other interested parties, the imports from China have increased significantly even when compared to 2019-20, which was not impacted by COVID-19.
 - e) The demand for the product under consideration has increased by 5% as compared to the previous year while the imports have increased by 46%. Thus, such increase is not due to increase in production of steel.
 - f) As opposed to the submissions of the other interested parties, the imports from Indonesia have increased significantly in India and is priced below the raw material cost of the domestic industry.

- g) As opposed to the submissions of the other interested parties, there is no requirement that the imports should have increased from all sources.
- h) There is no provision under the Act or the Rules to exclude imports from a particular country or exporter from the purview of the present investigation.

G3. Examination by the Authorised Officer

G3.1 Meaning of “increased quantity”

71. Under the provisions of Section 9A of the Act, safeguard measures may be invoked where a product is being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry. As per Rule 2(c) of the Quantitative Restrictions Rules, "increased quantity" includes increase in import, whether in absolute terms or relative to domestic production.

G3.2 Increase in imports in absolute terms

72. The volume of imports over the period of investigation was as follows.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Australia	MT	1,44,573	18,002	1,16,925	2,55,530
Bahrain	MT	453	552	1,711	-
Bhutan	MT	-	-	91	100
Chile	MT	-	11,364	11,800	12,408
China PR	MT	3,13,567	32,690	82,431	8,29,732
Colombia	MT	3,99,682	5,22,275	4,39,508	4,39,850
Egypt	MT	42,675	-	-	-
Finland	MT	40,812	-	-	-
Germany	MT	3	-	-	-
Hong Kong	MT	3,565	56	1,934	-
Indonesia	MT	1,50,521	1,34,267	76,956	2,56,699
Iran	MT	17,384	610	-	-
Italy	MT	-	32	-	-
Japan	MT	4,19,909	3,79,058	3,45,603	3,00,245
Korea RP	MT	-	-	36,371	-
Malaysia	MT	597	-	-	-
Netherland	MT	-	-	38,418	-
New Zealand	MT	-	291	-	-
Oman	MT	-	-	-	10,000
Poland	MT	7,49,967	9,56,636	10,53,358	8,60,925
Puerto Rico	MT	4,000	-	-	-
Qatar	MT	956	2,842	5,031	3,367
Russia	MT	3,22,561	1,18,850	44,710	85,144
Saudi Arab	MT	-	-	-	237
Singapore	MT	1,76,351	51,878	25,112	1,98,182
South Africa	MT	-	-	-	312

Spain	MT	259	97	94	-
Switzerland	MT	46,019	1,96,647	2,03,074	2,09,586
UAE	MT	24	5,831	2,558	53,112
UK	MT	87	98	229	225
USA	MT	-	-	653	0
Ukraine	MT	-	-	25,000	-
Venezuela	MT	940	504	218	-
Total	MT	28,34,905	24,32,580	25,11,786	35,15,654

73. It is seen that the volume of imports declined in 2020-21, as compared to 2019-20. The same may be attributable, at least partly, to the effects of Covid-19, as claimed by other interested parties. However, thereafter, the imports increased on a year-on-year basis, upto the most recent period. However, the imports increased by 40% during 2022-23 as compared to 2021-22. Further, the volume of imports in 2022-23 was higher than that in all the earlier years. The imports increased by 24% in 2022-23 as compared to the base year.
74. The other interested parties have submitted that imports have increased from China only and the same is due to normalization of business post COVID-19. It is however seen that the imports from China increased by 907% as compared to the previous year. Further, even when compared to the base year, such imports have increased by 165%. Since 2019-20 was not impacted by COVID-19, it cannot be said that the increase in imports is only due to normalization of Indian economy. Further, in any case, the total imports of the product under consideration into India have increased. The increase is not merely from China. In fact, China was not the largest supplier of coke in the Indian market and constituted only 11% of total imports over the investigation period (12.58 lac against total imports of 112.95 lacs, cumulatively from all sources in the investigation period). Further, as compared to total increase in imports by 6,80,749 MT in 2022-23 as compared to the base year, imports from China account for an increase of 5,16,165 MT. The rest is on account of increase in imports from, *inter alia*, Australia, Indonesia and Switzerland.
75. The other interested parties have submitted that imports from Indonesia account for a small share in the Indian market and the price of such imports have remained stable. It is however seen that the imports from Indonesia have increased by 234% in 2022-23, as compared to the previous year. Thus, there is a clear increase in imports from Indonesia. The domestic industry has submitted that (a) there was further increase in imports from Indonesia after the investigation period, (b) exports to India constitutes majority of its exports, (c) the price of imports from Indonesia is below the raw material price of the domestic industry.

Particulars	Units	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Import Volume from Indonesia	MT	1,50,521	1,34,267	76,956	2,56,699
Import price from Indonesia	₹/MT	22,024	22,574	35,340	37,142
Cost of RM	₹/MT	18,427	15,713	24,539	39,312

76. regards to the contention that the imports from Poland has declined and the exporter has exported under long-term agreement, it is seen that imports from Poland did decline in 2022-23. However, despite this decline, imports from Poland continue to account for a significant share (24%) of the total imports. Article 2.2 of the Agreement on Safeguards provides that “*safeguard measures shall be applied to a product being imported irrespective of its source*”. The only exception is in respect of developing countries, having import volumes below the prescribed levels. However, the imports from Poland do not fall under such exception. Imports were significant in relation to total demand in the country, accounting for a share of 14%. Therefore, an adequate case has not been made out for exclusion of the imports from Poland from the scope of levy. In view of the same, no exclusion can be made for imports from Poland.

G3.3 Increase in imports in relative terms

77. The volume of imports have also been examined in relation to Indian production and consumption over the period. It is seen that the imports have increased significantly in relation to domestic production and consumption.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Imports from various sources (As per DGCI&S data)	MT	28,34,905	24,32,580	25,11,786	35,15,654
Sales by applicants	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	90	93	106
Sales of Other Domestic Producers	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	80	113	104
Total Indian Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	84	106	105
Total Merchant Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	85	97	115
Total Merchant Installed capacities in India	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	100	100	100
Imports in relation to					
Imports in relation to Indian Merchant Sales	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	103	84	119
Imports in relation to Indian Demand	%	53%	53%	48%	57%

It is seen that:

- the imports in relation to merchant sales have increased by 41% in relation to the preceding year.
- the imports in relation to consumption have increased by 18% in relation to the preceding year.
- It is also seen that the above increases in imports in relation to production and consumption is despite existence of sufficient capacities with the Indian industry. It is thus seen that there has been a sudden, sharp, significant increase in imports in the recent period.

H. UNFORESEEN DEVELOPMENTS

H1. SUBMISSIONS BY OTHER INTERESTED PARTIES

78. The following submissions were made by the other interested parties with regard to the unforeseen developments.

- The domestic industry has not provided any justified reasons for claiming unforeseen development as Russia-Ukraine conflict has been settled and no logical connection between the development and increase in imports has been provided.
- While the domestic industry has submitted that coking coal prices in Australia have remained low, the same is not true. There has been a significant increase in coal prices even in Australia.
- The increase in prices of Australian coal had similar impact on the Indian market, global market and local market in Australia.
- The prices of coal had increased globally and not just for India, even the Indonesian producers purchased coal at increased prices. Thus, it does not amount to unforeseen development.
- Even if increase in price of coal is considered as unforeseen development, it is applicable in case of imports from countries like Australia and China and not for all countries.
- The price of coking coal increased prior to Russia-Ukraine conflict, hence, the same cannot be the reason for increase in coal prices. Prices of coking coal has declined in 2022-23 and is further expected to decline in 2024. The purchase price of coal for the applicants have declined during 2022-23.
- The coal prices declined in 2020 due to supply constraints resulting from COVID-19. The price of coal showed volatility in 2021 and 2022 due to recovery of global economy. The price of coal has started declining again in 2023.
- Coal prices increased due to strong demand of coal which was foreseen. Since increase in coal prices applied globally, the prices in India followed the same trend.
- Since India is also a major producer of coking coal, the fact that the producers which procure coal locally were not affected is without merit.

- j. Increase in freight rates happened in 2021 and declined thereafter. Further, freight rates have affected both imports of coking coal as well as met coke in India. The Authorised Officer in safeguard investigation into imports of PVC Suspension Resins held that increase in freight rate impacts both raw material as well as imports of finished goods, thus, neutralizing the injurious impact.
- k. Miniscule quantity of coking coal was imported by the domestic industry during 2021-22 and 2022-23. Any increase in international coking coal prices and freight prices should not cause serious injury to the domestic industry.
- l. The factors identified by the domestic industry are not unforeseen. The inherent disparity in natural resources, such as coal, between various countries are ordinary geographical variations. Increase in freight rate as well cannot be considered since freight rates are bound to fluctuate due to demand-supply dynamics.
- m. The applicants have submitted that Chinese producers have benefitted by procuring Russian coal as no sanctions were placed by China on imports from Russia. India also did not place any sanction on imports of coal from Russia and the domestic industry was also free to do so. As opposed to this, the report of International Energy Agency shows that the Indian industry has benefitted from imports of Russian coal.
- n. The applicants have not provided information to establish that import surge has occurred due to effect of obligations undertaken by India under the GATT. Appellate Body in Korea - Dairy held that WTO Members must comply with both the Agreement on Safeguards as well as Article XIX of the GATT prior to imposition of safeguard measures.
- o. The evidence submitted by the domestic industry to show unforeseen development pre-dates the unforeseen developments.
- p. Surge in imports is mainly from Australia and China. Such surge is not due to unforeseen development but only due to expiry of anti-dumping duty on such countries.
- q. Appellate Body in Argentina-Footwear held that unforeseen development means unforeseen or unexpected at the time of entry into force of WTO Agreement on Safeguards and at the time of incurring tariff concessions. The domestic industry has not explained how increase in price of coal or freight were unforeseen at the time of entry in force of WTO Agreement on Safeguards.
- r. The increase in volume of imports is due to tariff concessions offered by India under FTAs. The Panel in India – Iron and Steel Products held that providing concessions on customs duty is not an obligation incurred under the GATT.
- s. Imports have increased due to absence of customs duty for a period of 6 months. Reduction in customs duty cannot be considered as unforeseen development. The Authorised Officer in safeguard investigation into imports of Flexible Slabstock Polyol considered Indo-Singapore CECA as a reason for increase in imports and held that the same is not an unforeseen development.
- t. The exemption on imports of Met Coke has been withdrawn on 19th November 2022. Thus, the primary reason for increase in imports does not exist and thus, there is no need for imposition of measures.
- u. The situations identified by the domestic industry are temporary in nature and unforeseen developments claimed did not exist in the most recent period.

H2. SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

- 79. The following submissions were made by the applicants with regard to the unforeseen developments causing increase in imports:
 - a. The imports have increased in India as a consequent of unforeseen development.
 - b. The Appellate Body in Argentina – Safeguard Measures on imports of footwear noted that unforeseen developments are unexpected developments and not unpredictable development.
 - c. The increase in imports is a consequent effect of the Russia-Ukraine conflict which led to significant increase in international price of coal and higher cost of production in India. The cost of production of producers in countries which had coal locally available did not increase commensurate to international price of coal.
 - d. Contrary to the claims of the other interested parties, Russia-Ukraine conflict is ongoing. Since met coke was being imported into India at prices below the raw material cost of the domestic industry, the importers were motivated to import met coke.

- e. A number of countries-imposed restrictions on imports from Russia leading to decline in demand of Russian coal and as a consequent decline in prices of Russian coal.
- f. Due to decline in Russian supply of coal, demand for coal from other countries increased leading to increase in price of coal.
- g. Coking coal in countries such as Australia and China is available domestically and the producers in such countries did not face increase in cost of production to the extent faced by Indian producers.
- h. The other interested parties have not provided any evidence of price of coking coal in Australia. The landed price of imports from Australia is lower than the cost of raw material of the domestic industry.
- i. Coking coal is available in China at prices below the international prices.
- j. Chinese producers started importing cheaper coking coal from Russia at prices below the international prices.
- k. As opposed to the submissions of the other interested parties, the unforeseen development identified by the producers is based on increase in cost of coal without commensurate increase in landed price of met coke.
- l. Due to disparity between the cost of production in India and the producers situated in countries where coking coal was available domestically, exporters were able to export subject goods at lower prices.
- m. As opposed to the contention of the other interested parties, the price of coking coal has increased in India post Russia-Ukraine conflict. However, the landed price of subject goods has not increased commensurate to increase in cost of coal. While the cost of sales of the domestic industry has declined post most recent period, landed price declined more.
- n. The cost of production of the Indian producers increased due to increase in freight rates, however, the producers in countries where coal was available domestically did not face such increase.
- o. As opposed to the submissions of the other interested parties, freight rates have remained high in 2022-23.
- p. Due to geographical closeness of China to Russia, the Chinese producers have been able to import coal through rail routes from Russia.
- q. Import of coal by China from Russia have tripled post the Russia-Ukraine conflict while import from Russia into other countries have declined.
- r. While India has also imported coal from Russia, the price of such imports is higher than the import price in China.
- s. Chinese producers have set up plants in Indonesia to take advantage of Australian coking coal as cost of procurement of Australian coal in Indonesia is less than that in China.
- t. Indonesia has exported mainly to India and Vietnam.
- u. The other interested parties have not provided data for prices of coal in Indonesia. Indonesia has imported coal from Russia at prices below the international prices.
- v. Contrary to the submissions of the other interested parties that the evidence for unforeseen development is for a period pre Russia-Ukraine conflict, the evidence provided pertains to post Russia-Ukraine conflict period.
- w. As opposed to the submissions of the other interested parties, the imports have surged from Indonesia as well which were not subject to any anti-dumping duty.
- x. Contrary to the submissions of the other interested parties, the increase in imports is not due to FTA concessions as imports from China also surged and there are no FTA concessions applicable to China. The imports from Indonesia increased only in the most recent period, while concession was given in 2019.

H3. EXAMINATION OF THE AUTHORISED OFFICER

80. The submissions made by the domestic industry and other interested parties with regard to the unforeseen circumstances were considered and the Authorized Officer finds that:

81. Article XIX of GATT obligates the investigating authorities to examine “unforeseen developments” that led to the increase in imports and the consequent serious injury to the domestic industry. Further, Rule 9(1) of the Rules also provides that increased imports must be as a result of unforeseen developments as under:

“The Authorised Officer shall, within eight months from the date of initiation of the investigation or within such extended period as the Central Government may allow, determine whether, as a result of unforeseen developments the increased imports of the goods under investigation has caused or threatened to cause serious injury to the domestic industry, and a causal link exists between the increased imports and serious injury or threat of serious injury.”

82. The Authorised Officer notes that the increase in imports must be on account of developments that were unforeseen or unexpected. Further, the development must have been unforeseen at the time of incurring the obligations, that is, accession to WTO, resolving to abide by the commitments under various WTO Agreements, and providing tariff concessions.
83. The applicants have submitted that the unforeseen development leading to increase in imports of the product under consideration in India was Russia-Ukraine conflict, increase in global freight rates and the Chinese producers have benefitted due to sanctions imposed by countries on imports from Russia.

H3.1 COKING COAL AVAILABILITY GLOBALLY

84. The domestic industry has submitted that there are two types of coal that are mined globally. These are thermal coal and coking coal. While thermal coal is available widely in India, coking coal is not available in India. Production of met coke requires coking coal, and thermal coal is not useful for the purpose. In order to produce met coke, the Indian industry is totally dependent upon imports of coking coal.
85. Coking coal is widely available in countries like Australia, China, Russia and Indonesia. Some quantity of coking coal is also available in countries such as USA and Canada.
86. The other interested parties have submitted that the price of coal and other natural resources may change due to limited availability and the same cannot be classified as unforeseen development. It is however noted that while the prices of raw materials may fluctuate, it is reasonably expected that the prices of met coke would also vary accordingly and proportionately in a normal market situation. Therefore, the price movement of coal and coke were examined during the investigation period. It is seen that in the present investigation, there was increase in cost of coking coal, without commensurate increase in landed price of met coke. Since coking coal commands 90% of the cost of production of met coke, the price of met coke should have increased commensurate to increase in cost of coking coal. However, the difference between the cost of raw material of domestic industry and landed price of coke has declined over the period of investigation.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Cost of RM	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	85	133	213
Landed price of Coke	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	88	157	179
Difference	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	106	339	-79

It is thus seen that there has been a very significant decline in the difference between the price of coal and coke in the most recent period. The domestic industry submitted that this decline in the difference is the cause of increased imports and serious injury to the domestic industry. The domestic industry has further submitted that this decline in the difference was due to the fact that Indian industry was faced with increase in coal price materially higher than the increase in the coal price faced by the foreign producers. Since these foreign producers faced increase in coal price materially lower than the Indian industry, these foreign producers were able to export much higher volumes than in the past, leading to increased imports and serious injury to the domestic industry.

H3.2 RUSSIA-UKRAINE CONFLICT LEADING TO INCREASE IN PRICES OF COAL

86. The information provided by the domestic industry shows that due to the Russia-Ukraine conflict, the prices of coking coal increased globally. The domestic industry has provided evidence showing that Russia was the third largest producer of coking coal and second largest exporter of coking coal prior to the Russia-Ukraine conflict.

87. Due to the Russia-Ukraine conflict, a number of countries imposed restrictions on imports of coal from Russia. Due to this, the demand for Russian coal declined in these markets. This constrained Russian producers to sell coal at a lower prices in the markets where they were able to get the orders. At the same time, this created an additional burden on other coking coal producing countries. The demand for coking coal from other countries increased due to this shift in procurement of coal by a number of consumers globally. This led to disproportionately significant increase in the prices of coking coal by suppliers in countries other than Russia.
88. The domestic industry has submitted that it primarily imports coal from Australia. Due to the situation identified hereinabove, the landed price of coal for the Indian industry increased. Resultantly, the cost of production of the domestic industry increased. It has been further submitted that coking coal accounts for approximately 90% of cost of production of met coke.
89. It is seen that while the coking coal prices increased globally, the price of coking coal in certain countries did not increase commensurate to increase in international prices in countries where it was not available domestically, or who were not able to source coal from Russia at comparable prices. Thus, producers in Australia, Indonesia and China did not face increase in cost of production commensurate to increase in cost of production of producers in India.
90. Due to the disparity between the cost of production in India and producers situated in countries where coking coal was either available domestically, or who were able to source Russian coal at comparatively lower prices, the foreign producers, largely in China, Indonesia and Australia were able to undercut the prices of Indian industry in the market and were able to export significantly higher volume of material in the Indian market. Resultantly, the subject goods have been imported into India at prices below the cost of sales and selling price of the domestic industry, leading to increased imports. The petitioner has claimed that they have not imported coal from Russia citing higher freight cost.
91. It is seen that whereas landed price of imports was higher than the selling price and cost of sales of the Indian industry in the year preceding the most recent period, the difference reversed in the most recent period, leading to surge in imports.

Particulars	Units	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Landed price of imports	₹/MT	20,872	18,294	32,830	37,381
Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	104	157	202
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	89	124	197
Difference between import price and					
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	-100	2,203	-215	3,060
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	128	-814	691

92. With regard to submissions by the other interested parties that price of coking coal has increased in Australia, the Authorized Officer considers that the relevant consideration is how the prices of metcoke have moved and whether the same have moved in tandem with the prices of coal. Comparison of the cost of raw material of the domestic industry and the landed price of imports of metcoke from Australia shows that the landed price of metcoke imported from Australia was below the raw material cost of the domestic industry except in year 2021-22.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Cost of RM	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	85	133	213
Landed price of imports from Australia	₹/MT	17,699	8,816	34,655	36,083

Difference	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	947	-1,390	444

H.3.3 CHINESE PRODUCERS HAVE DISPROPORTIONATELY BENEFITTED FROM RUSSIA-UKRAINE CONFLICT

94. The domestic industry provided information showing that the Chinese producers have significantly increased imports of Russian coal post the Russia-Ukraine conflict. While Chinese producers already have access to low priced domestic coal, they have procured coal from Russia at lower prices in order to benefit from the lower landing price at which Russian coal was selectively available to the Chinese producers. While India has also increased its procurement of Russian coal, the advantage available to the Chinese producers – both volume and price account far outstripped the benefit availed by Indian industry. This has led to lower cost of production of the Chinese producers enabling them to export higher quantities of met coke at lower prices in markets such as India.
95. The Authorised Officer has taken cognizance of the submissions made by the domestic industry that the landed price of imports of Russian coal into China was lower than the landed price of imports of coking coal by rest of the world. Further, the quantity of coking coal imported into China from Russia has increased by 2.8 times as compared to the period prior to the Russia-Ukraine conflict.

Particulars	UOM	Pre-Conflict*	Present**
Russian exports to China			
Volume	MT	***	***
Value	In Lakhs	***	***
Price	₹/MT	***	***
Global imports except imports into China			
Volume	MT	60,06,14,011	39,65,30,737
Value	In Lakhs	5,17,84,161	8,75,97,015
Price	₹/MT	8,622	22,091

*Annualised figures based on April 2019 – March 2022

**Annualised figures based on April 2022 – October 2023

H.3.4 INCREASE IN GLOBAL FREIGHT RATES

96. The domestic industry has further stated that since it is totally dependent upon import of coking coal, the cost of procurement of coking coal increased significantly due to increase in freight rates. However, the producers in the countries where coking coal was available locally did not face this increase, as these producers do not pay for ocean freight for such procurement.
97. The domestic industry further submitted that whereas the freight costs were higher in both 2021-22 and 2022-23, the higher freight costs in 2021-22 did not cause any damage to the Indian industry for the reason that the increase price of met coke in this period allowed the Indian industry to bear the increased cost of coal. However, in 2022-23 whereas the cost of coal increased because of these two factors, price of coke did not increase due to producers such as Chinese offering coke at lower prices.
98. The other interested parties have submitted that freight rates declined post 2021. It is however seen that domestic industry has submitted report by UNCTAD regarding freight rates on coal. The evidence on record shows that the freight rates remained high till May 2022. Although, the freight rates declined post May 2022, the same increased once again in early 2023 due to Russia-Ukraine conflict.

H.3.5 ADVANTAGE OF DOMESTIC COAL AVAILABILITY AND DUAL ADVANTAGE OF CHINA FOR BUYING CHEAPER RUSSIAN COAL AND FREIGHT

99. It is noted that the Chinese producers have imported low priced coking coal from Russia via rail routes. Hence, the cost of procurement for the Chinese producers was much less than that of any other producer who have imported coal through sea routes.
100. Other interested parties have submitted that even Indian producers have imported coal from Russia and benefitted from such imports. The Authorised Officer notes that the domestic industry has submitted that the landed price of imported Russian coal into India was much higher than the landed price of imports into China.

H3.6 AS A RESULT OF OBLIGATION INCURRED AT THE TIME OF ENTRY INTO GATT

101. With regard to effect of obligations, the Appellate Body, in Argentina – Footwear, noted that this phrase simply means that it must be demonstrated, as a matter of fact, that the importing Member has incurred obligations under the GATT 1994, including tariff concessions. It is further noted that India incurred obligations with respect to the product under consideration under the GATT. The product under consideration is one of the products listed under the Schedule of Concessions, and thus, India incurred obligations with respect to the product under the provisions of GATT. In view of the same, it is considered that the requirements of Article XIX with regard to effect of obligations is satisfied.

H3.7 INCREASE IN IMPORTS AS A RESULT OF REMOVAL OF ADD, CUSTOMS DUTIES AND FTAS.

102. **Removal of ADD:** With regard to issues raised regarding the removal of ADD in November 2021 and the impact of same felt in 2022-23, the ADD was in force against imports from China and Australia. However, the increase in imports is not just from Australia and China even imports from Indonesia have witnessed a major surge. Thus, removal of ADD cannot be said to be the reason for increase in imports into India.
103. **Customs Duty:** The Authorised Officer proposes that the increase in imports was not due to removal of customs duty. The Central Government vide Notification No. 26/2022 dated 21st May 2022, removed the customs duty on imports of the product under consideration in India. However, such customs duty was restored vide Notification No. 59/2022 dated 18th November 2022. The Authorised Officer notes that the increase in imports is majorly from Australia, China PR and Indonesia. The subject goods from Indonesia are imported duty free under Customs Notification No. 41/2019 – Customs. Thus, removal of customs duty should not have led to increase in imports from Indonesia. Further, the subject goods can be imported from countries such as Japan, Korea RP and members of ASEAN nations, duty free. However, imports from such countries have not shown any major increase. Major imports into India are from countries such as Poland and Colombia, however, the imports from such countries did not increase even after removal of customs duty. Thus, it is evident that the increase in imports is from the countries where the raw material, that is, coking coal was available domestically and not from countries from where the subject goods can be imported duty-free.
104. **FTAs:** The Authorised Officer proposes that the increase in imports is not due to FTA in force. This is evident from the fact that major increase in imports is from Australia, China PR and Indonesia. The subject goods can be imported from Indonesia, duty free under Notification No. 41/2019 – Customs dated 31st December 2019. While the customs duty was reduced to 0 in 2020, the imports have increased only during the most recent period and hence, the FTA cannot be considered as a reason for increase in imports into India. Further, India and China PR have not entered into a Free Trade Agreement with respect to the product under consideration. Thus, the increase in imports from China PR also cannot be a result of concessions under the FTA.

H3.8 INCREASE IN IMPORTS DUE TO SURGE IN STEEL DEMAND

105. The Authorised Officer notes that the other interested parties have submitted that the imports into India have increased due to increase in demand of steel. The Authorised Officer proposes that the merchant capacities in India are enough to cater to the merchant demand in India. Given that the Indian industry is operating at low-capacity utilization, the increase in demand could have been catered by the domestic industry. Hence, the increase in demand in India cannot be the reason for increase in imports especially when the Indian industry has enough capacities and is operating at a low-capacity utilization.

Particulars	Unit	2022-23
Merchant Capacity	MT	***
Merchant Demand	MT	61,86,991
Difference	MT	***

106. Further, the demand in India has increased by 19% during the most recent period as compared to the previous year, however, the imports have increased by 40%. Thus, the increase in imports is much more than the increase in demand.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Imports into India	MT	28,34,905	24,32,580	25,11,786	35,15,654
Imports into India	Indexed	100	86	89	124
Demand in India	MT	53,82,045	45,64,092	52,02,880	61,86,991
Demand in India	Indexed	100	85	97	115

107. Having regard to the facts on record, the imports of the product under consideration have increased as a result of unforeseen developments and not due to other factors as mentioned above.

Serious Injury and Causal Link

I SERIOUS INJURY TO THE DOMESTIC INDUSTRY

II Submissions by the other interested parties

108. The following submissions were made by the other interested parties with regard to injury to the domestic industry.
- a. The information on total capacity is unreliable as the total Indian capacity has remained stable throughout the injury period, the capacities of the domestic industry have increased.
 - b. The market share of the domestic industry declined merely by 1% between 2021-22 and 2022-23, while installed capacity, production, domestic sales and profits of the domestic industry increased during the most recent period as compared to 2019-20. The capacity utilization of the domestic industry declined only due to increase in capacities.
 - c. The domestic industry has performed better during the most recent period as compared to the base year in terms of profitability. The Authorised Officer terminated the anti-dumping investigation into imports of Metronidazole as the profitability of the domestic industry declined only during the second half of the period of investigation and it was profitable throughout the injury period.
 - d. While the landed price increased by 15% as compared to 2021-22, the selling price of the domestic industry increased by 66%. Hence, price undercutting is on account of extreme increase in selling price of the domestic industry.
 - e. Since price undercutting was negative in 2019-20 and 2021-22, domestic industry cannot claim injury due to price undercutting.
 - f. The data provided by the domestic industry does not seem reliable as both landed price of imports and selling price of the domestic industry has increased but price undercutting has turned positive.
 - g. There is no price suppression / depression as the cost of sales of the domestic industry declined more than decline in selling price in 2020-21 as compared to 2019-20, further, the selling price increased more than increase in cost of sales during 2021-22.
 - h. The increase in cost of production identified by the applicants was not caused by imports into India.
 - i. The applicants are comparing performance in 2020-21 and 2021-22 with the performance in the period of investigation, however, 2020-21 and 2021-22 were abnormal period due to impact of COVID-19 which is evident from the annual reports of the applicants. All applicants have performed better than the base year as per their annual reports.
 - j. The landed price of imports was highest during 2022-23 and thus, cannot be claimed to be a reason for losses to the domestic industry. While the landed price was lowest in 2020-21, the profitability was the highest.
 - k. The profitability parameters of the domestic industry have improved in 2022-23 as compared to April-December 2022. Thus, the domestic industry is on a positive trajectory.
 - l. The Authorised Officer must analyse the profitability of the domestic industry month by month during the most recent period. The domestic industry has earned adequate profits in three months in April 2023 – December 2023.
 - m. Price effect is irrelevant in a safeguard investigation and hence, pricing behaviour of imports cannot be considered. The Safeguard Rules state that when any factors other than increase in imports is causing injury to the domestic industry, such injury shall not be attributed to imports.
 - n. The applicants have not provided evidence to demonstrate that the prices in Chinese and Australian markets have not moved in tandem with the international prices.
 - o. There is no causal link between increase in imports and injury to the domestic industry. The domestic industry undertook capacity expansion in 2022-23 and the depreciation as well as salaries and wages increased. Causation should be determined by excluding self-inflicted effects of interest, wages and depreciation.
 - p. There should be a separate analysis of imports from Poland and these imports should not be clubbed with imports from China. The causal link should be evaluated separately as imports from Poland has not caused injury to the domestic industry.

- q. The loss of market share cannot be attributed to imports from Poland, which declined by 18%, in comparison to decline of 2% in market share of domestic industry.
- r. The injury to the applicants, if any, is due to increase in price of coal and freight rates, increase in exchange rates, interest and depreciation, and not due to imports.
- s. The credit rating of Mahalaxmi Ennore Coke & Power Pvt. Ltd., Vimla Fuels and Metals Private Limited and Genus Paper and Coke Limited shows that they have earned profits during FY 2023.
- t. India has become a net exporter of the met coke in 2021 due to better realization of price. The Authorised Officer must examine the export trend of the domestic industry to determine the cause of injury.
- u. The data submitted by the domestic industry is unreliable since capacity of the domestic industry increased in 2021-22 by 2%, however, the capital employed increased by 50%. While capacity increased in 2022-23, the capital employed declined.
- v. The applicants have not provided post period of investigation data as committed during the oral hearing.
- w. The applicants have not provided revised data for April 2022-March 2023.

12 Submissions by the domestic industry

109. The following submissions were made by the domestic industry with regard to injury.

- a. The domestic industry has suffered serious injury due to increase in imports into India.
- b. Contrary to the submissions of the other interested parties, the imports during the most recent period are even higher than the imports in 2019-20. Such period was not impacted by COVID-19. Imports have further increased in April-December 2023.
- c. The imports have increased in absolute as well as in relation to domestic production and demand in India.
- d. The increase in demand as well as the market share of the Indian industry has been taken over by imports. While the demand has increased by 13%, imports have increased by 46% over the injury period.
- e. While the Indian industry catered to the majority share of demand in India in the previous year, the imports have taken over the majority of the Indian market during the most recent period.
- f. As opposed to the contention of the other interested parties, imports from Poland cannot be considered separately from other imports.
- g. The imports were undercutting the prices of the domestic industry even though the domestic industry has sold at financial losses.
- h. The price of imports was below the selling price as well as cost of sales of the domestic industry during the most recent period.
- i. Due to the low-priced imports, the domestic industry was forced to sell at prices below the cost of sales.
- j. In a normal business cycle, the price of met coke changes with change in price of coking coal. However, in 2022-23, the landed price of subject goods has not increased commensurate to increase in price of coking coal. The difference between the cost of raw material and landed price of the subject goods has declined.
- k. The domestic sales of the domestic industry have not increased commensurate to increase in capacities or demand in India, while production and capacity utilization declined.
- l. The plants of two of the petitioners were shut down post the most recent period due to inventory pile up and lack of market share.
- m. The selling price of the domestic industry has not increased commensurate to increase in its cost of sales.
- n. The domestic industry has incurred losses, cash losses and recorded a negative return on investment in the most recent period. Even during the post most recent period, the domestic industry has incurred losses, cash losses and negative return on investment.
- o. Due to the surge in imports at prices below the cost of sales of the domestic industry, the profitability of the domestic industry has suffered significantly.
- p. While the landed price increased during 2022-23, such increase was much lower than the increase in raw material prices of the domestic industry.
- q. Landed price of met coke cannot be considered in isolation to price of coking coal since coking coal commands for 90% cost of production of the subject goods.

- r. The other interested parties have not followed a consistent approach in comparing to most recent period, some parameters have been compared to previous year and others to the base year.
- s. Surge in imports happened in 2019-20 as well due to which the domestic industry suffered injury. The domestic industry could not reach the Authorised Officer at that time since the subsequent year was impacted by COVID. Since the increase in imports is recent, the injury to the domestic industry is also recent due to such surge in imports.
- t. As opposed to the contention of the other interested parties, the annual reports of the petitioners show decline in performance in 2022-23 as compared to 2021-22.
- u. As opposed to the submissions of the other interested parties, the data for post period of investigation has been provided and circulated vide email dated 25th January 2024.
- v. Contrary to the submissions by other interested parties, the domestic industry has filed revised data for April 2022 – March 2023 on 3rd August 2023.
- w. Contrary to the submissions of the other interested parties, the decline in profits of the domestic industry is higher than the increase in interest and depreciation cost. Further, the EBIDTA of the domestic industry has declined. Thus, the injury is not due to increase in interest and depreciation cost.
- x. Since the Authorised Officer has verified the data of the domestic industry, no arguments can be made regarding the reliability of the information provided.
- y. The facts of the present case are different from the anti-dumping investigation on Metronidazole relied upon by other interested parties, wherein the Authorised Officer held that profitability of the domestic industry declined only temporarily but it has earned sufficient profits during the period of investigation. However, in the present investigation, the domestic industry has been suffering continuous losses.
- z. Contrary to the submissions of the other interested parties, there is no requirement under the law to undertake month-wise profitability analysis.
- aa. Credit rating of a company depends upon overall performance of the company and not with regard to performance of the subject goods. The companies identified by other interested parties are multi-product companies and are involved in exporting to other countries.
- bb. Contrary to the submissions of the other interested parties, the capital employed has increased as a new producer started production in 2021-22.
- cc. As opposed to the contentions of the other interested parties, the injury cannot be due to exchange rates as both coke and coal were equally impacted by it.
- dd. Contrary to the submissions of the other interested parties, India is a net importer of subject goods and not an exporter. In any case, the petitioners have segregated the performance of the company with regards to domestic operations only.

I3. Examination by the Authorised Officer

110. The Authorised Officer is required to examine whether the increased imports of the product have caused or are threatening to cause serious injury to the domestic industry of like or directly competitive products. As per Section 9A(4) of the Act, serious injury means an injury causing significant overall impairment in the situation of a domestic industry, while threat of serious injury means a clear and imminent danger of serious injury. Rule 8(a) of the Quantitative Restrictions Rules provides as under for determination of injury.

"The Authorised Officer shall determine serious injury or threat of serious injury to the domestic industry taking into account, inter alia, the following principles, namely:

(a) in the investigation to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to a domestic industry, the Authorised Officer shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the goods concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic, market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilisation, profits and losses, and employment;"

111. In view of the above, the parameters relating to injury have been analysed hereinbelow.

I3.1 Assessment of demand/consumption

112. For the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India has been determined as the sum of domestic sales of like product produced by the Indian producers and imports of the product under consideration into India.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Domestic industry sales	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	90	93	106
Other producers sales	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	80	113	104
Imports into India (as per DGCI&S Data)	MT	28,34,905	24,32,580	25,11,786	35,15,654
Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	85	97	115
Installed capacities	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	100	100	100

113. It is seen that the demand for the product has increased in the most recent period. Further, demand in the most recent period was higher as compared to the demand in any other period. However, so significant was the increase in the volume of imports of the subject goods that whereas the demand increased by 19% in the most recent period as compared to the previous year, the imports increased by 40%, which is more than the entirety of the increase in demand. Thus, the growth in consumption was encapsulated by imports of the subject goods.

13.2 The rate and amount of the increase in imports in absolute and relative terms

114. Analysis of information contained hereinabove with regard to the increased imports and table below clearly shows that imports of the product under consideration have increased in both absolute terms and in relation to production and consumption in India. It is seen that both the rate and amount of increase in imports over the injury period is significant.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Imports in absolute terms	MT	28,34,905	24,32,580	25,11,786	35,15,654
Increase in imports	MT		(4,02,325)	79,206	10,03,868
Rate of increase in imports	%		-14%	3%	40%

13.3 Market share

115. The market share of the domestic industry, other Indian producers and imports of product under consideration was as follows.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	106	94	89
Other Indian producers	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	93	117	90
Indian industry as a whole	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	100	111	91
Imports into India	%	53%	53%	48%	57%
Demand	%	100%	100%	100%	100%

It is seen that the market share of the domestic industry as well as Indian industry as a whole declined in 2022-23 as compared to 2019-20, 2020-21 as well as 2021-22. The market share of imports has increased significantly in India in the most recent period. It is seen that the imports have taken away the market share of the Indian industry.

116. The domestic industry contended that the Indian industry holds capacities sufficient enough to meet the entire demand for the product in the country. It is however seen that majority of the demand was catered by the imports, while the Indian industry catered to a minority share.
117. The other interested parties have claimed that the imports from Poland have reduced and thus, cannot be the reason for decline in market share. It is however noted that injury is required to be examined in respect of imports of the product under consideration from all sources, and not imports from a particular country. Thus, imports from Poland have to be seen cumulatively with imports from all other countries.

I.3.4 Price undercutting

118. It was examined whether imports of the subject product were priced below the selling price of the domestic industry and causing price undercutting in the market. Table below shows the factual position.

Particulars	Unit	Amount
Net sales realisation	₹/MT	***
Landed price	₹/MT	37,381
Price undercutting	₹/MT	***
Price undercutting	%	***%
Price undercutting	Range	10-20

119. It is seen that the imports were undercutting the prices of the domestic industry. The price undercutting is significant and positive.
120. The other interested parties have submitted that the price undercutting was negative in the previous years. It is noted that the price undercutting was negative during 2019-20 and 2021-22. However, during the most recent period, the imports started undercutting the prices of the domestic industry. This increased the demand for the imported goods, leading to increased imports, and created a strain on the prices and market share of the domestic industry.

I.3.5 Price suppression / depression

121. It was examined whether the imports of the subject goods were suppressing or depressing the prices of the domestic industry. For the purpose, the trends in the costs and prices were examined over the injury period. The table below shows factual position.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
	Indexed	100	89	124	197
Landed price	₹/MT	20,872	18,294	32,830	37,381
	Indexed	100	88	157	179
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
	Indexed	100	104	157	202

It is seen that in 2020-21, the cost of sales of the domestic industry declined. However, the domestic industry was able to increase its selling price in this period, as the imports declined in this period. Though the price of imports was lower, such imports did not create a pressure on the volumes or prices of the domestic industry due to covid related disturbances. Thereafter, in 2021-22, both the cost of sales and the selling price of the domestic industry increased. Even then, the increase in selling price was higher than the increase in cost of sales, as the import prices increased even beyond the levels kept by the domestic industry. Since the price of imports was higher, such imports did not create a pressure on the volumes or prices of the domestic industry. The domestic industry in fact was able to increase its volumes in proportion to increase in consumption. During 2022-23, the cost of sales increased by ***%. However, the increased influx of imported goods prevented the domestic industry from increasing its prices in tandem with the cost of sales. The large volume of goods entering the market at cheaper prices prevented the domestic industry from increasing its prices in tandem with the increase in costs. The domestic industry was able to increase its prices only by ***%. Therefore, during the most recent period, the imports prevented price increases, which otherwise would have occurred.

I.3.6 Comparison of raw material cost and landed price

122. Since coking coal accounts for the major cost of production of the subject goods and commands approximately 90% of the cost of production, it was examined whether the landed price of the subject goods have moved in tandem with the cost of coking coal.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Cost of RM	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	85	113	213
Landed price of Coke	₹/MT	20,872	18,294	32,830	37,381
Difference	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	106	339	-79
Mark-up	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	117	208	-42

123. It is seen that the price of coking coal has increased in India over the injury period. The landed price of met coke has also increased in India. However, the difference between the cost of raw material of the domestic industry and landed price of met coke has declined steeply. Further, it is seen that compared to a mark-up of ***-***% in the previous years, the mark-up between the raw material cost and landed price of coke become negative during the most recent period. Considering that a producer would have to incur conversion costs, selling, general and administrative expenses and would also normally earn a reasonable profit; a negative mark-up is grossly insufficient to sustain any business.

I.3.7 Capacity, production, capacity utilization and domestic sales

124. The performance of the domestic industry with regard to installed capacity, production, capacity utilization and domestic sales over the injury period were analysed.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Capacities	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	100	103	110
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	80	113	104
Capacity utilization	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	80	110	95
Domestic sales	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	90	93	106

It is seen that

- the installed capacities with the domestic industry have increased over the injury period. The domestic industry submitted that in light of increasing demand, some of the domestic producers have set up or increased their capacities. It is seen that the demand for the product in the country increased by 15%. The domestic industry increased capacities by 10%.
- production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry declined during 2020-21. The same was in view of Covid and decline in demand during this period.
- During 2021-22, the production, capacity utilization and sales recovered. The landed price of imports in this period were relatively higher. Resultantly, the domestic industry was able to increase its sales, and consequently production and capacity utilization.
- In 2022-23, the period when the imports of the product surged, production capacity utilization and domestic sales of the domestic industry suffered again. While the sales of the domestic industry increased by 15%, such increase was not commensurate with the increase in demand, which increased by 22%.

I.3.8 Inventories

125. The inventory position of the domestic industry over the period of investigation was as below.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Opening Inventory	MT	***	***	***	***
Closing Inventory	MT	***	***	***	***
Average Inventory	MT	93,478	71,287	82,241	1,09,285
Trend	Index	100	76	88	117

It is seen that the inventories with the domestic industry increased over the injury period. The inventories have increased by 33% in the most recent period as compared to the previous year, and by 17% as compared to the base year. Further, the inventory holding period of the domestic industry has also increased by 10% as compared to the base year.

I.3.9 Employment and Productivity

126. Employment and productivity situation of the domestic industry was as follows.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
No of employees	No.	***	***	***	***
Trend	Index	100	94	123	116
Productivity per employee	MT/No.	***	***	***	***
Trend	Index	100	85	92	89
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
Trend	Index	100	80	114	135

It is seen that the number of employees and productivity per day have increased over the injury period. The productivity per employee has dipped, since the production did not increase in tandem with the increased capacities and employment.

I.3.10. Profit / Loss

127. The profitability of the domestic industry was as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Profits/Losses	₹/MT	(***)	***	***	(***)
	Indexed	(100)	252	646	(79)
Cash profits	₹/MT	(***)	***	***	(***)
	Indexed	(100)	658	1,493	(36)
Return on investment	%	(***)	***	***	(***)
	Indexed	(100)	1,352	1,941	(45)

128. The domestic industry has submitted that it suffered injury and financial losses in 2019-20 due to closure of blast furnace by Neelachal Ispat Nigam Limited (“NINL”). NINL was a public sector iron and steel manufacture and had its own captive coking coal plant. However, NINL was forced to operate coke oven plant even after shutting down the steel plant, in order to prevent damage to the same. Thus, it had no other option other than to sell met coke in the merchant market. MMTC and NINL started selling met coke in the merchant market at low prices, thereby driving the price down in the market. The price offered was extremely low due to which the domestic producers of the product were forced to sell at lower prices in order to compete in the market. Thus, the domestic industry incurred losses during the period.

129. It is seen that the domestic industry has suffered financial losses in the most recent period as compared to the previous year. The profitability of the domestic industry has declined steeply. While the domestic industry was

earning profits, cash profits and adequate return on investment in the previous year, the profitability of the domestic industry has crashed in the most recent period. The domestic industry has incurred cash losses and a negative return on capital employed.

130. Some of the opposing interested parties have submitted that the losses to the domestic industry is due to increase in interest and depreciation costs. It is however seen that the profitability of the domestic industry has declined much more than the increase in depreciation and interest cost. While depreciation and interest cost increased by Rs. 783 lacs and Rs. 1906 lacs, the profitability declined by Rs. 55,656 lacs from year 2021-22 to most recent period. Hence, the decline in profitability cannot be due to increase in the said costs. Further, the EBIDTA of the domestic industry has declined steeply in the most recent period, as compared to 2021-22 and with the surge in imports in this period.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
EBIDTA	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	1,128	2,203	147
	Rs lacs	***	***	***	***
Trend	Index	100	1,012	2,040	156

I.3.11 Shut down of plant due to imports

131. The domestic industry has submitted that plants of two of the petitioners were shut down due to inventory pile up and lack of market share. The producers were unable to sell their product in the market and were forced to completely shut down the production.

J. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

132. As per Rule 8(b) of the Rules, the Authorised Officer is required to determine whether increased imports were a cause of the serious injury or threat of serious injury to the domestic industry. Therefore, for the purpose of causal link assessment, all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of the domestic industry were examined, and it was ascertained whether the increased imports of the subject goods were one of the primary causes of serious injury to the domestic industry. In addition, it was examined whether factors other than increased imports were a cause of injury to the domestic industry. While there are no laid down "other factors" that are required to be evaluated, it was examined whether factors such as developments in technology, export performance, productivity, contraction in demand, possible dumping of the product, were principal cause of injury to the domestic industry.

J1. CONTRACTION IN DEMAND

133. It is noted that there is no contraction in demand of the subject goods in the country.

J.2. PATTERN OF CONSUMPTION

134. No interested party has alleged that there has been a change in the consumption pattern for the goods.

J.3. CONDITIONS OF COMPETITION AND TRADE RESTRICTIVE PRACTICES

135. The investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices have changed.

J.4. DEVELOPMENT IN TECHNOLOGY

136. It is seen that there is no significant change in technology.

J.5. EXPORT PERFORMANCE OF THE DOMESTIC INDUSTRY.

137. The injury analysis is limited only to domestic performance and for the product under consideration.

138. The other interested parties have submitted that the performance of other Indian producers have improved; and, thus, the Indian industry is not suffering injury. The other interested parties have relied upon the credit ratings of the producers. It is noted that the credit ratings do not provide the correct picture regarding the performance of the producer in respect of product under consideration. Further, the evidence on record shows that some of the producers mentioned by the other interested parties are engaged in exporting the product. Since the data with regard to performance of product under consideration in the domestic market was not available, the same has not been considered by the Authorized Officer.

ADJUSTMENT PLAN AND PUBLIC INTEREST**K. ADJUSTMENT PLAN****K.1. Submissions by the other interested parties**

139. The following submissions were made by the other interested parties with regard to adjustment plan.

- a. The applicants have not provided an adjustment plan. There is no exception to the requirement of the adjustment plan even if the measures are requested for less than one year. In a number of safeguard investigations, including those on Phthalic Anhydride, Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel, Not alloyed Ingot of Unwrought Aluminium and Flexible Slabstock Polyol, the Authorised Officer has held that the adjustment plan submitted by the domestic industry was not viable or lacks evidence.
- b. In the absence of an adjustment plan, the initiation is erroneous as the accuracy and adequacy of the evidence provided has not been examined.

K.2. Submissions by the domestic industry

140. The following submissions were made by the domestic industry with regard to adjustment plan.

- a. The domestic industry has requested measures only for a period of one year. Accordingly, no adjustment plan has been submitted.
- b. The findings of the Authorised Officer stated by the other interested parties were those where measures were requested for more than one year.

K.3. Examination of the Authorised Officer

141. Rule 9 of the Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012 states as follows.

“9. Final findings.-- (1) The Authorised Officer shall, within eight months from the date of initiation of the investigation or within such extended period as the Central Government may allow, determine whether, as a result of unforeseen developments the increased imports of the goods under investigation has caused or threatened to cause serious injury to the domestic industry, and a casual link exists between the increased imports and serious injury or threat of serious injury and recommend --

(iv) the duration of imposition of quantitative restrictions and where the duration of imposition of quantitative restrictions is more than one year, the progressive liberalisation adequate to facilitate positive adjustment.”

142. According to Rule 9, the Authorized Officer shall provide for progressive liberalization adequate to facilitate positive adjustment in case measures being recommended are for a period of more than one year. Since the measures requested by the domestic industry are for a period of one year, there is no requirement for providing an adjustment plan.

L. PUBLIC INTEREST**L.1. Submissions by the other interested parties**

143. The following submissions were made by the other interested parties with regard to public interest.

- a. Imposition of measures is not in public interest as it will artificially alter the demand-supply situation, offset comparative advantages, induce inefficiency in manufacturing, disrupt export competitiveness, increase cost of production artificially and force inconsistency in decision making by downstream industry.
- b. The applicants are unable to fulfill the demand in India and any measures will cut the source of regular supply to the consumers.
- c. The production of domestic industry is only half the total demand in India. The maximum capacity utilization of the domestic industry has been only 52% during the period when anti-dumping duty was in force. Thus, the Indian industry will not be able to fulfil the demand in India.
- d. While the applicants have claimed high capacities in the country, the production volume is very low. It cannot be assumed that all producers are operating at less than 50% capacity utilization.
- e. The demand for the product under consideration is expected to increase in India which will lead to further increase in the demand-supply gap.
- f. Imposition of measures will not be in public interest as met coke is an important element to produce iron, steel, aluminium, titanium and silicon. The quality of met coke influences the efficiency, productivity and overall cost of steel production.

- g. While the applicants have submitted that captive producers are insulated from market situations, the cost of production of captive producers have also increased during the most recent period due to increase in prices of coal. If measures are imposed, captive producers who also import met coke will be adversely impacted.
- h. Imposition of quantitative restrictions may have an adverse impact on the performance of the steel manufacturers. Increase in prices of met coke will lead to increase in price of steel making the Indian industry uncompetitive globally.
- i. Imposition of measures will impact export competitiveness of the downstream industry as it will not be able to import product under consideration for production of product meant for exports without application of quota.
- j. Increase of 10% in the landed price of met coke will have an impact of 3-5% on the total cost of pig iron, 2-3% of total cost of alloy steel, 3-5% on total cost of rounds and billets. An increase of 50% in the landed price of met coke will have an impact of 18-25% impact on the total cost of Pig Iron, 10-11% of total cost of alloy steel and 18-20% of total cost of rounds and billets.
- k. The applicants are already enjoying the benefit of 5% customs duty on imports of met coke from Indonesia.
- l. The Government of India has already provided relief to the producers of met coke by removing the import duty and Agriculture Infrastructure and Development Cess on imports of coking coal.
- m. The Authorised Officer in methyl acetoacetate held that imposition of safeguard duty is not in public interest and hence did not impose any duties in the said case.
- n. A Memorandum of Understanding has been signed between the Government of India and Russian Federation regarding coking coal. This MoU will help the steel manufacturers in procuring high quality coking coal from Russia. Thus, any measures on met coke will be against the vision of the government.
- o. In case of imposition of quantitative restrictions the import volume will be capped at 2.69 million MT which is 8,50,000 MT less than the demand in Indian market. Such demand would be catered by the Indian industry. However, Indian industry has produced only 1.04 million MT and thus, it is unclear if the Indian industry will be able to fulfil the demand in India.
- p. The domestic industry is not impacted by volume of imports but only by the price of imports. Thus, limiting the total volume of imports is not an appropriate remedy.
- q. Quantitative restriction will disrupt the target of Ministry of Steel to achieve capacity of 300 million tons and production of 255 million tons of crude steel by 2030-31.
- r. Government has implemented PLI 1.0 scheme for specialty steel and is working towards PLI 2.0. Any restriction on imports of met coke will be detrimental to government vision.

L.2. Submissions by the domestic industry

144. The following submissions were made by the domestic industry with regard to public interest.
- a. There will be no price effect on the downstream industry as no duty will be levied pursuant to the present investigation.
 - b. The product under consideration is not a raw material but only a source of energy. The cost of product under consideration is not a substantial cost in for the downstream industry.
 - c. The impact of imposition of measures on imports of the product under consideration will be negligible.
 - d. Fair prices will be maintained in India as there are a number of producers in the market which compete *inter se* in India.
 - e. There is no demand-supply gap as the merchant capacities in India are more than the merchant demand.
 - f. The quota determined by the Authorised Officer will majorly impact only Australia, China and Indonesia. Typical suppliers such as Poland, Columbia and Russia will get quota more than their imports in the most recent period.
 - g. The major segment of the industry is catered by captive producers. Thus, imposition of measures on imports will not impact such industry.
 - h. The plants of two of the petitioners were shutdown due to increase in imports into India at prices below the cost of sales of the domestic industry.

- i. The measures requested are for only a period of one year.
- j. There was no adverse impact on the downstream industry during the period where anti-dumping duty was in force on imports from Australia and Indonesia.
- k. The Indian industry provides employment to 12,500 people directly and 62,500 people indirectly. In case of unviability of operations, livelihood of a number of people will be lost.
- l. As opposed to the contention of the other interested parties, imports from Indonesia are duty free under Notification No. 41/2019 – Customs dated 31st December 2019.
- m. As opposed to the contention of the other interested parties, the Authorised Officer in methyl acetoacetate concluded in the abovementioned investigation that the performance of the domestic industry has not deteriorated and increase in imports was not due to unforeseen development.
- n. Even if concessions have been provided by the Government of India, such concessions did not have any positive impact on the performance of the domestic industry.
- o. Contrary to the submissions of the other interested parties, the Government of India has always promoted domestic manufacturing in India.

L.3. Examination of the Authorised Officer

145. Article 3.1 of the Agreement on Safeguards states as follows:

“A Member may apply a safeguard measure only following an investigation by the competent authorities of that Member pursuant to procedures previously established and made public in consonance with Article X of GATT 1994. This investigation shall include reasonable public notice to all interested parties and public hearings or other appropriate means in which importers, exporters and other interested parties could present evidence and their views, including the opportunity to respond to the presentations of other parties and to submit their views, inter alia, as to whether or not the application of a safeguard measure would be in the public interest. The competent authorities shall publish a report setting forth their findings and reasoned conclusions reached on all pertinent issues of fact and law.”

146. In view of the aforesaid, there is a need to examine whether imposition of safeguard measures shall be in public interest. Though Article 3.1 does not provide any guidance on the manner of evaluation, the same, however, requires, *inter alia*, evaluation of impact of measures on various stakeholders, and taking a balanced view keeping in view competing interests of different interested parties.
147. With regard to the submissions of the other interested parties, that there is demand-supply gap in India, it is noted that the domestic industry is operating at low-capacity utilization even though there is ample of demand in India. Further, the merchant capacities in India are higher than the total merchant demand in the country. Further, the volume of imports shall be regulated only to the extent of surge in imports in 2022-23. The extent to which the volume shall be regulated shall be very easily made up even by the petitioning domestic industry. Accordingly, imposition of measures would not lead to scarcity of availability of product in India.

Particulars	Volume
Merchant demand in India (2022-23)	61,86,991
Merchant capacity in India (2022-23)	63,69,455
Demand-Supply Gap	(1,82,464)

148. It is noted that met coke is important in the production process of a number of products such as iron, steel, ferro alloys, chemicals etc. Since met coke is not a principal raw material and is not a significant cost to the downstream industry, any change in cost of met coke would not have unbearable impact on the costs of the downstream industry.

149. The information on record shows that even if the prices of met coke increase post imposition of measures on imports of the product, the impact of such measures will be negligible.

Particulars	Unit	Rate
Price of downstream product		
Hot Rolled Coil Steel	₹/MT	62,138
Hot Metal (for pig iron)	₹/MT	41,000
Selling price of domestic industry	₹/MT	41,675

Total production by Indian merchant producers	MT	26,99,115
Total Imports into India	MT	36,39,492
Captive Production	MT	2,29,44,282
Total Consumption (total production + Imports)	MT	2,92,82,889
Share of merchant producers	%	9%
Average margins in previous three years / increase in prices	₹/MT	2,081
Selling price in case of increase in price	₹/MT	43,756
Consumption of Met Coke for		
Hot Rolled Coil Steel	Kg/MT	304
Merchant Share in Hot Rolled Coil Steel	Kg/MT	28
Hot Metal (for pig iron)	Kg/MT	357
Merchant Share for hot metal	Kg/MT	33
Impact		
Hot Rolled Coil Steel	₹/MT	58
Hot Metal (for pig iron)	₹/MT	68
Hot Rolled Coil Steel	%	0.09%
Hot Rolled Coil Steel	%	0.17%

150. It is also noted that there is a history of trade remedial measures on the imports of the product. However, none of the users have demonstrated an adverse impact of the earlier measures on their performance. Therefore, there is no basis to conclude that the imposition of measures would adversely affect the performance of the downstream industry.
151. The Authorised Officer takes cognizance of the submissions made by the domestic industry that the product is either manufactured by the producers for selling in the merchant market or is captively consumed. The captive market for the product is much bigger than the merchant market. Any imposition of measures will not impact the larger segment of the market.

Segment	Consumption				Segment-wise Share %	
	Gross (KT)	Captive (KT)	Merchant (KT)	% Merchant Share	Overall	Merchant
Steel	***	***	***	11%	89%	54%
Pig Iron	***	***	***	47%	5%	14%
Zinc, Soda Ash & Others	***	***	***	100%	2%	11%
Ferro Alloys	***	***	***	100%	1%	8%
Foundry	***	***	***	100%	1%	4%
Others	***	***	***	100%	2%	9%
Total	38,320	31,586	6,734		100%	100%

152. The domestic industry has submitted that there are a number of producers in the Indian market which compete *inter se*. Accordingly, the prices will remain fair and competitive in India.
153. The essential facts gathered during the course of the investigation, and as established on the basis of information received from various sources are hereby being disclosed in order to enable various interested parties to offer their comments on these facts so gathered. The Authorized Officer will, however, make the

final determination on various aspects of the investigation on the basis of the comments received thereof from the interested parties to this disclosure statement to the extent they are relevant.

M. POST DISCLOSURE SUBMISSIONS

M.1 Submissions by the other interested parties

154. The following submissions were made by the other interested parties with regard to disclosure statement.
- a. Since the domestic industry imports coal from Australia, there should not be any adverse impact of Russia - Ukraine Conflict especially as India has not imported coal from Russia due to high freight cost.
 - b. While the Authorized Officer has placed heavy reliance on prices of coking coal, in a safeguard investigation, it is necessary to analyse the global supply of subject goods and import restriction policy in other countries.
 - c. Indonesian producers also faced impact of high freight cost as it has similar distance with Russia and Australia as that of India. The Indonesian producers are also dependent heavily upon imported coking coal.
 - d. The domestic industry was able to increase its production, sales while the market share of domestic industry faced a marginal decline, hence there is no injury to the domestic industry.
 - e. The price of imports as well as selling price of the domestic industry has increased in 2021-22 and 2022-23. The cost of sales of the domestic industry has increased due to which its profitability has declined. Thus, serious injury to the domestic industry is due to internal factors.
 - f. The injury caused to the domestic industry was not due to imports but due to shutdown of NINL and met coke sold in the merchant market by NINL and MMTC at low prices.
 - g. There is no price suppression since the landed price has increased more than increase in selling price of the domestic industry in 2022-23 as compared to 2019-20.
 - h. Increase in prices of coking coal does not have a direct relationship with dynamics of increase in imports of met coke and cannot be considered as an unforeseen development.
 - i. Since Indian companies have bought Russian coal at favorable prices, they could not have suffered from excessively high prices of raw material. Jindal Coke Limited has bought coking coal from Jindal Steel and Power Limited which may have been mined by its related entity in Mozambique.
 - j. The names of producers whose production has been taken into account for determining the total Indian domestic production, total domestic production of met coke in India, methodology for determining total production, share of applicants in such total production and names of producers who are considered ineligible have not been shared in the disclosure statement.
 - k. While the Authorized Officer has proposed to conclude that exclusion of captive production is not of directly competing article, the captive producers are also producers of like product in India. Therefore, such producers should be considered eligible. The term 'directly competitive article' is meant to cover article that may not be like article per se but is competing with the product under consideration. Thus, 'directly competitive article' referred to in the Rules is with regard to the product being manufactured and not regarding the producer of the product whether captive or merchant.
 - l. The Authorized Officer has misinterpreted "or" in the definition of domestic industry with "and". Each component of the definition has to be read independently. The two conditions "like article" and "directly competitive goods" are not mandated to be fulfilled together.
 - m. While the Authorized Officer has relied upon the Appellate Body Report in US-Lamb, the case is not applicable to the present investigation as the issue in the case was regarding the product while the issue in the present investigation is regarding the producer of the product.
 - n. The facts of safeguard investigation into imports of Solar Cells is not applicable on the present investigation as domestic producers producing the subject goods for captive production cannot be treated on an equal footing as that to the producers situated in the SEZ.
 - o. While the Authorized Officer has relied upon a number of statutes, only a general reference has been made to them. None of the statutes provide for any special treatment for domestic producers engaged in production of goods for captive production.
 - p. There is no WTO Appellate Body Report in India-Safeguard Measures on Certain Hot-Rolled Flat Products of Stainless Steel and the citation provided by the Authorized Officer refers to Appellate Body Report in China – Measures Related to the Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybdenum.

- q. Even if the production of captive consumers is excluded, the production of producers which are producing for merchant and captive market should be considered.
- r. The Authorized Officer has not given an examination on the submissions made by the association regarding standing of the domestic industry.
- s. Increase in price of coal cannot be termed as an unforeseen development since increase in price of exhaustible natural resource, which has limited availability is expected. Further, it is normal that the domestically available natural resource will experience lower rate of increase in prices.
- t. While the domestic industry itself opted to import higher price coal from Australia as compared to Russia, it has justified by stating that the freight rate was higher for importing from Russia. This implies that the non-availability of coal from Russia at low prices was due to high freight rates and the same cannot be termed as an unforeseen development.
- u. Even if increase in price of coking coal is considered as an unforeseen development, it cannot be the reason for increase in imports. The Authorized Officer in Bare Elastomeric Yarn, held that there is a difference between unforeseen development leading to serious injury and unforeseen development leading to increase in imports.
- v. The impact assessment by the Authorized Officer is not appropriate as it has considered only hot rolled coil steel as downstream product and not pig iron, billets and rounds. The Authorized Officer has assumed that the selling price of the domestic industry would be fixed at a particular rate after imposition of measures, such assumption is not economically viable and legally impermissible. While the Authorized Officer has considered that 304 kg of met coke is required for production of hot rolled coil steel, actually 400-500 kg of the same is required.
- w. The Authorized Officer has considered that the major demand will be fulfilled by captive consumers but has failed to consider that not all consumers of the product have captive met coke plants.
- x. Determination of quota based on volume of imports in last three years excluding the surge period is incorrect and the period of investigation cannot be bifurcated between the surge period and previous three years. There cannot be a consistent practice to fix quota since there have been only two safeguard (QR) investigations in India.
- y. While considering the last three representative years for fixation of quota, the current period representative of the actual demand-supply gap, that is, 2023-24, is already excluded. Exclusion of 2022-23 will result in entirely unrepresentative fixation of quota.
- z. The increase in imports in the surge period is offset by considering average imports in previous three years.
- aa. Surge period should not be excluded for determination of quota since the demand for steel has increased leading to increase in demand for met coke in India. The demand for steel is expected to increase further. In both safeguard (QR) investigations, that is, IPA and PVC, the Authorized Officer considered the growth of demand while fixing quota.
- bb. The disclosure did not consider and address the submission of Balta which demonstrated that exclusion of import from an individual country from the scope of safeguard measure is permissible. Accordingly, Poland should be excluded from the scope of the measures.
- cc. The petitioners do not hold major share of the total Indian production as it should be more than 51% of the total share of production in India.
- dd. It appears that there is no injury to the other 20 domestic producers constituting 67% of the total production in India and therefore, they are not before the Authorized Officer.
- ee. The petitioners have not provided the actual figures of some parameters as per Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September 2018 whereas the Authorized Officer has accepted the confidentiality claims in violation of the Trade Notice.
- ff. There is no increase in imports from Indonesia in such increased quantities in absolute terms or relative to domestic production so as to cause serious injury to the domestic industry.
- gg. As per the market intelligence, the domestic industry is importing the subject goods in reasonable quantities. Thus, increase in imports should be attributed to the imports made by the petitioners themselves which is causing injury to them.

- hh. The Authorized Officer should clearly provide the evidence of how Russia-Ukraine conflict, increased global freight rates and the alleged advantage of Chinese producers have specifically impacted the Indian market.
- ii. The petitioners are comparing the imports in POI with the imports in abnormal period i.e. 2020-21 and 2021-22 which is unreasonable and unjustifiable.
- jj. The Authorized Officer may opt for the previous years before COVID-19 pandemic to analyze the injury to the domestic industry.
- kk. The profitability of the domestic industry during 2022-23 have improved as compared to base year 2019-20, thus, it the performance of the domestic industry has improved showing that there is no injury to the domestic industry.
- ll. The Authorized Officer shall confirm in the final finding that the measures, will be for one year only and no further extension would be granted by way of mid-term or sunset review as no viable adjustment plan has been submitted.
- mm. The increase in imports is interim and is not being made with the intention to cause injury to the domestic industry. The petitioners themselves provide that the increase in imports is temporary.
- nn. The petitioners are at present not able to fulfill the demand of the Indian industry and the imposition of the safeguards measures would cut the source of regular supply and cause negative impact on the public interest of India.
- oo. Authorized Officer must reconsider its decision not to exclude met coke with size upto 40 mm from the scope of the product under consideration.
- pp. The Authorized Officer has not evaluated the contention of AMNS that met coke supplied by the domestic industry is of inferior quality.
- qq. Under Section 9A(4)(b) of the FTDR Act read with the Agreement on Safeguards, the domestic industry is defined as producers of “directly competitive goods” and not “directly competing goods”.
- rr. If only “directly competing” producers can be considered to be a part of the domestic producers, then EOUs should be excluded since they do not directly compete with imports. Yet in the solar safeguard investigation, the Authorized Officer included EOUs within the scope of the domestic industry even though the EOUs did not compete with the imported goods.
- ss. In US – Cotton Yarn, the Appellate Body explained the difference between competitive and competing. The Appellate Body held that even if the producers are not directly competing with another, the mere possibility to compete is sufficient to include the production quantity of those producers in the ‘total domestic production’. The captive producers are in a competitive relationship with the imported goods despite no sales in the merchant market.
- tt. Vertically integrated producers may also enter the merchant market as done by Neelachal Ispat Nigam Ltd. due to shutdown of its steel plant.
- uu. In Dominican Republic – safeguard measures, the Panel held that it is not permissible to define the domestic industry based on only a limited portion of the producers of the product.
- vv. The import volumes during the most recent period is 35,15,654 MT, whereas the import volumes during 2013-14 was 39,26,125 MT. The import volumes during the most recent period are less than the import volumes that existed a decade ago.
- ww. The domestic industry imports high priced coking coal from Australia, when cheaper alternatives are available. Due to the expensive raw materials sourced, the cost of production of met coke is higher than the import price of met coke. However, this is a circumstance that is unique to the domestic industry and is not a general unforeseen development.
- xx. Since India has not placed any sanctions against imports from Russia, it is not appropriate to conclude that only Chinese producers have benefitted from Russian coal.
- yy. The price of coking coal has declined between April 2022 to March 2023, thus, the submission that price of coking coal has increased should not be taken into account.
- zz. There is an abnormal increase in the cost of production of the domestic industry by 97% from the base year to the most recent period. The landed price of met coke increased by 79% during this period. The injury to the domestic industry is because of the increase in its raw material costs.

- aaa. The domestic industry increased its installed capacity during the most recent period, which may have led to an increase in cost of production.
- bbb. There is no factual basis of the impact of only Rs. 68/MT determined by the Authorized Officer on the prices of Hot Metal (Pig Iron). The Authorized Officer must disclose the evidence it has relied upon to arrive at such a number. The true impact on the downstream users is far higher.
- ccc. The Ministry of Steel targets 300 million MT of steel production by 2030-31, any measures imposed will set India back by a few years.
- ddd. The Authorized Officer is requested to extend the coverage of the exclusion to include low ash metallurgical coke with phosphorous content up to 0.030% with size of 30 mm. A tolerance of up to 5% for size in the definition of the scope of product exclusion.
- eee. There is no dedicated tariff item under which imports of Metallurgical Coke with ash content less than 18% can be specifically classified. It is not clear as to how the import data obtained from the DGCI&S can be relied upon for the purpose of the present investigation.
- fff. The domestic industry has limited its comments to the availability of met coke with size upto 40 mm, and has provided no comments regarding the quantities in which it is available. The limited availability of 'LAM Coke of upto 40 mm' will severely impact the operations of pig iron producers that use mini blast furnaces.
- ggg. The Authorized Officer has not substantiated upon the changes observed in the market conditions and the demand of the product under consideration post-Covid, and how fixing the quota based on the average imports in the three years prior to the surge period is justified.
- hhh. The domestic industry has consistently operated at less than half its capacity. Even when the anti-dumping duty was in effect on imports from China and Australia, the domestic industry was unable to increase its capacity utilization.
- iii. The respondents also apprehend that even if the domestic producers increase their production to meet the domestic demand, it may not be commensurate to the increase in demand for LAM Coke in India.
- jjj. Met coke is a major raw material for producing finished goods such as ferro alloys, steel, and pig iron. India is a major producer and exporter of these downstream products.
- kkk. There are significant differences in the data recorded in the disclosure statement and the data submitted by the domestic industry.
- lll. The Authorized Officer has claimed excessive confidentiality regarding the aggregate data of the domestic industry.
- mmm. Increase in prices of coking coal pre-dates the Russia-Ukraine war. The reports referenced by the domestic industry underscored this point.
- nnn. The domestic industry was well aware of tight supply of coking coal since mid-2021. The domestic industry was also aware since 2021 that the impact of limited supply and freight related challenges drove coking coal prices to record high levels between mid-2021 and February 2022. February 2022 was the month in which Russia invaded Ukraine whereby it is self-evident that the coking coal and freight related effects on prices were already an aged phenomenon by then.
- ooo. The cost of raw materials borne by the petitioners cannot be reasonably compared to the landed price of imports or be expected to move identically since India lacks natural reserves of coking coal and heavily relies on imports. The cost structure for domestic producers is inherently influenced by additional factors such as ocean freight costs and cannot be considered comparable to the cost of production of exporters.
- ppp. The grievances of the domestic industry are solely related to the cost of production and price of imports from China, and has no bearing on the legal standard for imposition of a safeguard measure.

M.2 Submissions by the domestic industry

155. The following submissions have been made by the domestic industry post issuance of the disclosure statement.
- a. Ultra-low phosphorous metallurgical coke with phosphorous content below 0.03% and size below 30 mm for use in ferroalloy applications only should be excluded. The importers must show bona fide use of the product in order to import the product without application of quota.
 - b. Coke fines and Ultra-Low Phos Coke have been excluded from the scope of the product under consideration but are included in the import data. It must be excluded for calculating the proposed quota.

- c. There is huge difference between the volume of imports as per the market intelligence of the petitioners and the volume of imports given in disclosure statement. The difference is due to the fact that the volume of imports given in the disclosure statement includes coke fines and ultra-low phos coke.
- d. The petitioners request the Authorized Officer to clarify that the price of coking coal did not increase for foreign producers which are situated in countries where coking coal is available domestically.
- e. The other interested parties agreed during the oral hearing that Ukraine-Russia conflict is an unforeseen development. Due to the said unforeseen development, the imports of product under consideration have increased in India and have caused serious injury to the domestic industry.
- f. Since coking coal accounts for 90% of the cost of production of met coke, the prices of met coke should move in tandem with the cost of coking coal. However, during the surge period, the landed price of met coke have not increased commensurate to the increase in coking coal prices causing serious injury to the domestic industry.
- g. While the Indian industry has also imported some quantities of Russian coking coal post Russia-Ukraine conflict, the quantities are very low and the price of such imports is higher than price of imports into China.
- h. Chinese producers have invested in Indonesia to take advantage of Australian coal. Since Australia is closer to Indonesia as compared to China, the cost of procurement of Australian coal is much lesser in Indonesia as compared to China.
- i. Due to disparity between the prices of global coking coal and domestically available coking coal, the Australian met coke industry was able to produce met coke at lower prices and export the same at low prices to India.
- j. Most of the domestic producers purchase coking coal based on published prices. Due to increase in imports of met coke into India, the domestic industry was not able to utilize the high price coking coal purchased as the domestic industry was forced to reduce production during the most recent period. Hence, even when the price of coking coal declined, the cost of production of the domestic industry remained high.
- k. In case imports had not surged, the domestic producers would have got orders and would have consumed coal, as planned. Surge in imports of met coke leading to non-availability of orders led to significant stock piling of coal.
- l. The imports have surged from multiple countries. Countries such as Japan and Poland have lost volumes and will benefit from the proposed measures.
- m. The petitioners account for major share in domestic production. Barring the applicants and supporters the other domestic producers include those which are interested in export market and trading along with manufacturing the product.
- n. One of the other domestic producer has captive coal mine and since low ash coking coal is not available in India, it is a producer of high ash met coke which is NPUC in the subject matter.
- o. The imports of the product under consideration have increased even post period of investigation.

M3. Examination by the Authorized Officer

- 156. The Authorized Officer has considered the submissions placed on record by all the interested parties including the Governments of various countries, domestic industry, exporters, importer, users and other interested parties. The Authorized Officer has already made detailed examination in this final finding. Only fresh submissions are being dealt with in this section of the final finding.
- 157. While the other interested parties have claimed that the injury to the domestic industry cannot be due to Ukraine-Russia conflict as Indian producers have not imported Russian coal, the Authorized Officer notes that the injury to the domestic industry is due to increase in imports of the product under consideration due to the unforeseen circumstances, that is, Russia-Ukraine conflict. The Russia-Ukraine conflict led to decline in supply of coking coal from Russia due to sanctions placed on such imports by a number of countries. As a collateral effect, the demand for coking coal from other countries increased leading to increase in prices of coking coal globally. Since met coke prices did not increase commensurate to increase in the price of coking coal the delta between met coke and coking coal declined leading to surge in imports of met coke.
- 158. Contrary to the argument that Indonesian producers also face impact of high freight cost due to similarity in distance from Russia and Australia, it is noted that Indonesia accounted for a major supplier of coking coal to India in 2019-20. Although Indonesia was exporting huge quantities of coking coal to India, exports of coking coal from Indonesia to India have declined while exports of met coke from Indonesia to India have increased. Indonesia benefitted from the Russia-Ukraine conflict as coking coal prices increased globally, however, prices of met coke did not increase commensurately as the Indonesian producers had access to domestic coking coal

and the delta between coal and coke declined, the Indonesian producers started exporting met coke to India. Hence, it cannot be said that the Indonesian producers are dependent upon imported coking coal and bear high freight cost for the same similar to the Indian producers.

159. The Authorized Officer notes that because of the unforeseen development of Russia-Ukraine conflict, the price of coking coal increased globally. However, the price of coking coal did not increase commensurate to the price of global coking coal in countries where the same was available domestically. Since Australia has abundance of domestically available coking coal, the producers in Australia had comparative advantage over producers from other countries and especially India where the producers are largely dependent upon imports of Australian coal. The Australian producers were able to produce low-priced met coke and were able to export the same to India in such increased quantities and at low-prices to cause serious injury to the domestic industry.
160. The Authorized Officer takes cognizance of the fact that the injury to the domestic industry during 2019-20 was due to sale of met coke by NINL in the merchant market at low prices and such injury was not due to imports into India which is also stated by the domestic industry. However, the same is not the case in the surge period, that is, in 2022-23. The injury to the domestic industry during 2022-23 was due to increase in imports into India due to unforeseen development.
161. It is also noted that though domestic producers in India might have imported coking coal from Russia at some favorable prices but Russian coking coal constitutes an insignificant share of total imports of coking coal into India. The contention of other interested parties that Jindal Coke Limited may have purchased coking coal from its related entity, the Authorized Officer notes that Jindal Coke Limited has not purchased coking coal from Jindal Steel and Power Limited which is claimed by the domestic industry and verified by the Authorized Officer.
162. The Authorized Officer notes that the Indian producers have purchased coking coal at high prices but were not able to utilize the same for production of met coke due to increase in volume of imports of met coke into India. When the coking coal prices declined, the cost of production of the domestic industry remained high as it had inventories of coking coal purchased at higher prices. In case, the imports had not surged in India, the domestic industry would have been able to consume the coking coal purchased and sell met coke in the market during the same period. Thus, the economies of the domestic industry have been adversely impacted due to surge in imports of met coke.
163. With regard to the submission on impact assessment, the Authorized Officer notes that since the present investigation is regarding imposition of measures in form of quantitative restrictions and not for imposition of duty, such restrictions will not adversely impact the downstream industry such as pig iron, steel etc. Further, since the product being used by ferroalloy industry has already been excluded from the scope of the measures, there will be no impact on such industry. Further, the measures are recommended only for a period of one year and there is no demand-supply gap in India which may lead to scarcity of the product or arbitrary pricing in India. Further, while quantitative restrictions will lead to lower volume of imports into India, the quota quantified by the Authorized Officer takes into account the demand-supply situation. There will be adequate supply of the product under consideration in India even after imposition of quantitative restrictions.
164. The contention of other interested parties regarding granting of country specific quota and exclusion of Poland from the safeguard (QR) measure is already addressed in the findings above. It is further reiterated that contrary to the contention, the notification no. 12/2021 – Customs (NT) dated 1st February 2021 clearly states that tariff rate quota may be global or country specific but the present investigation is not regarding tariff rate quota but is regarding quantitative quota. The present investigation has been initiated under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 and not under the Customs Tariff Act, 1975. Rule 11 of the Safeguard (Quantitative Restrictions) Rules, requires that the measures have to be applied on a non-discriminatory basis.
165. The contention of the other interested parties that the import of the product under consideration by the petitioners itself in reasonable quantities is responsible for the injury to the domestic producers is not tenable. Further, the other interested parties have not submitted any evidence regarding imports by the domestic industry. The Authorized Officer notes that the domestic industry has not imported the product under consideration during the period of investigation. In any case, imports by the domestic industry does not disqualify them from filing a petition for safeguard measures.
166. The contention of the other interested parties that the domestic industry suffered due to purchase of expensive Australian coking coal despite the availability of cheaper alternatives is merely a claim without any evidence. As noted in paragraph above while coking coal from Australia accounted for major share of the Indian imports of coking coal. Further the, domestic industry has stated that the grade or variety of coking coal is imported based on the technical requirements of the product under consideration's production. It cannot be substituted with the cheaper alternatives of lower grade or type.

167. The contention of the other interested parties regarding exclusion of ultra-low phos met coke is accepted. The product excluded from the scope of product under consideration is “low ash metallurgical coke with phosphorous content up to 0.030% with size of 30 mm with 5% size tolerance for use in ferroalloy manufacturing”. Further, the submissions with regard to import data and segregation methodology considered by the Authorized Officer, it is noted that DGCI&S data was procured at 4-digit level and was analyzed based on the description of the product under consideration. The transaction pertaining to only low ash metallurgical coke with ash content below 18% have been considered.
168. The Authorized Officer notes the submission made by the domestic industry that the imports of the product under consideration consists of the product excluded from the scope of product under consideration, that is, ultra-low phos metallurgical coke with phosphorous content upto to 0.030% with size of 30 mm and coke fines/breeze. The Authorized Officer notes that the imports already considered are excluding the imports ultra-low phos metallurgical coke with phosphorous content upto to 0.030% with size of 30 mm and coke fines/breeze.
169. With regard to the contention that met coke of 40 mm size used for blast furnaces should be excluded from the scope of the product under consideration, the Authorized Officer notes that the other interested parties have themselves submitted that such product is being manufactured and supplied by the domestic industry. With regard to quality of the product, the Authorized Officer notes that the landed price of imported met coke is below the selling price of the domestic industry. However, a premium quality product is normally sold at higher prices and not at lower prices as in the present situation. Thus, it cannot be said that the imported product is of a higher quality. Accordingly, no exclusion is required in this regard.
170. Regarding difference in data and the reasons for the same, it is noted that this difference was due to the revised submissions and verification of the data by the Authorized Officer.
171. Regarding the confidentiality in the disclosure statement for not providing aggregate data, it is stated that the major trends affecting the relevant economic parameters have been provided to all the interested parties. The interested parties were free to comment on the same. Therefore, there is no adverse impact of such confidentiality on any interested party.
172. With regard to the submissions of the other interested parties that the measures should not be extended after one year, the Authorized Officer notes that the present investigation is only for imposition of quantitative restriction and not extension of the same.
173. The other interested parties have submitted that vertically integrated producers may also enter the market. The Authorized Officer notes that Neelachal Ispat Nigam Limited entered the merchant market only due to closure of its steel plant. Further, the evidence on record shows that it was forced to sell met coke in the merchant market only to maintain its coke oven plants which has to be operated continuously. Further, there was an adverse impact on the merchant producers of the subject goods since Neelachal Ispat Nigam Limited sold the subject goods at very low cost. Further, the closure of steel plant and entrance of such producers into the merchant market is a speculative argument and the Indian industry whether merchant or captive has to be seen as it exists.
174. The Authorized Officer notes the submissions by the other interested parties regarding not considering the submissions with regard to standing. The Authorized Officer notes that the standing of the domestic industry is determined based on the most recent period and not over the complete injury period. This has been the past practice of the Authorized Officer and the same has been followed in the present investigation. Other issues regarding standing of the domestic industry has been dealt appropriately in the relevant sections.
175. The interested parties have raised an argument through comments on the disclosure statement with regard to interpretation of the term like or directly competitive under Article 4.1(c) wherein it has been submitted that the use of the word “or” under Article 4.1(c) should not be read as “and” which indicates that the goods produced should either be like or directly competitive and should not be both. It is noteworthy that the World Trade Organization (WTO) Panel in the case of United States – Safeguard Measure on Imports of Large Residential Washers had the occasion to address a comparable issue. In its deliberations, the Panel made the following observation:

“In making that determination, we do not need to exhaustively define what “like” under Article 4.1(c) could or could not mean, especially considering the drafters chose to not define the term in the Agreement on Safeguards. Instead, we need to determine whether Article 4.1(c) precluded the USITC from finding that imported and domestic parts were like products, given its finding that the two did not compete. Interpreting Article 4.1(c) in the context of Article 4 as a whole suggests to us that products that are not in any type of competitive relation with each other could not cause serious injury or threat thereof to one other. In particular, we note that Article 4.1(c) opens with the phrase “in determining injury or threat thereof”, which,

along with overall context provided by Article 4, specifically Articles 4.2(a) and 4.2(b), suggests that the domestic industry must be defined in a manner that allows the investigating authority to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to that industry. To the extent an investigating authority finds that two products are not in any competitive relation, we do not see how a domestic industry that is defined in a manner that excludes the possibility of subsequently determining that increased imports have caused or threatened to cause serious injury to that domestic industry (defined on the basis of producers of the like product, which here is covered parts) would be consistent with Article 4.1(c)."

176. The interpretation provided by the WTO panel in the dispute underscores the importance of considering competition within the safeguard investigation process. This aspect is crucial in defining both the product under consideration and, consequently, the domestic industry. The definition of domestic industry within the Safeguards Agreement commences with the phrase "in determining injury or threat thereof," empowering the Authorized Officer to assess the competitiveness of the product in question. This assessment is integral to determining whether injury has occurred.
177. In view of the above and to maintain coherence in interpretation, it is affirmed that captive production, not being in competition with imports, does not contribute to injury faced by the domestic producers engaged in direct competition with imported goods. Hence, in determining total domestic production within the present context, only producers vending 'like' goods which are 'directly competitive' and are subject to the injurious effects of surge in imports envisioned under the law are factored. Therefore, a major proportion of the 'like' or 'directly competitive' goods constituting the domestic industry in the facts of the present case is proposed to be assessed based on the production of the industry in the merchant market excluding the captive production.
178. With respect to the disclosure surrounding the concepts of competitiveness and competition, and the reliance placed upon the Appellate Body Report in the case of United States – Transitional Safeguard Measure on Combed Cotton Yarn from Pakistan, it is important to acknowledge that the aforementioned case pertained to measures imposed under the Agreement on Textiles and Clothing. However, it is important to note that the Agreement on Textiles and Clothing was terminated in 2005 and is no longer in effect. Secondly, the interpretation provided by the Appellate Body was in a different context and also the text of the Agreement on Textiles and Clothing is different than the text of the Agreement of Safeguards.
179. Conversely, the present investigation concerns a safeguard measure under the Safeguards Agreement. Notably, the World Trade Organization (WTO) Panel in the case of United States – Safeguard Measure on Imports of Large Residential Washers addressed a similar issue under Article 4.1(c) of the Safeguards Agreement. Given that the current investigation also involves a safeguard measure, the aforementioned WTO decision holds greater relevance and significance compared to the defunct Agreement on Textiles and Clothing.
180. Therefore, it is more appropriate to place reliance and consideration on the WTO decision pertaining to safeguard measures, as it directly aligns with the context and nature of the current investigation, whereas the Agreement on Textiles and Clothing is no longer applicable.
181. The other interested parties have submitted that if low priced imports are found to be impacting the domestic industry, appropriate remedies should be anti-dumping measures or anti-subsidy measures. The Authorized Officer notes that the injury to the domestic industry is due to sudden, sharp, significant and recent surge in imports due to unforeseen developments.

N. CONCLUSION

182. Based on the analysis of the application, it is seen that:
 - a. There has been a sudden, sharp, significant and recent increase in imports of the product under consideration into India.
 - b. There has been significant increase in imports in absolute and relative terms is due to unforeseen developments.
 - c. The imports of the product under consideration were undercutting the prices of the domestic industry and caused a strain on the selling price of the domestic industry in the domestic market.
 - d. The market share of imports of the product under consideration has increased in India.
 - e. The domestic industry started suffering serious injury in the most recent period on various parameters like financial profits, cash profits, negative return on capital employed.
 - f. The serious injury to the domestic industry is due to increase in imports of product under consideration into India.
 - g. Imposition of safeguard measures, in the form of quantitative restrictions, would be in public interest. It will prevent serious injury to the domestic industry while having a bearable impact on the downstream

industry as the demand of the subject goods would continue to be met by way of imports as well as sufficient capacities with the Indian industry.

O. RECOMMENDATION

183. In view of the aforementioned analysis, it is concluded that:

- a. The product under consideration, that is, low ash metallurgical coke has been imported into India in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry manufacturing the like article.
- b. The domestic industry has started suffering serious injury in the most recent period.
- c. The existing circumstances justify imposition of quantitative restrictions in order to prevent the domestic industry from further serious injury.

184. Accordingly, the Authorized Officer recommends the following measures:

- (i) The imports of the product under consideration are regulated and permitted not beyond the levels as mentioned in the table below. This quantum has been derived in terms of Rule 9(1) of the Safeguard Measures (Quantitative Restriction) Rules, based on an average of imports in the three representative years during the period of investigation, that is, 2019-20, 2020-21 and 2021-22 without considering the surge period, that is, 2022-23. However, the quota has been adjusted and increased in line with the increase in demand and highest capacity utilization of the domestic industry during the period prior to the surge period recommended in the table below are after keeping in view the demand-supply, demand growth and the capacity utilization of the domestic industry.
- (ii) The product under consideration, if produced in other developing countries (barring that mentioned in table below), shall not be subject to the measures recommended since the same are below the threshold prescribed under the Rules.
- (iii) The Directorate General of Foreign Trade (DGFT) had issued a Notification bearing file no. 01/92/180/106/AM-11/PC-VI/PRA dated 31st January 2013 wherein it had notified a list of developing countries under Section 9A(4)(a) of the FTDR Act, 1992. This notification was based on the Notification issued by the Department of Revenue. However, the Authorized Officer has noted that the list of developing countries has been subsequently revised by the Department of Revenue vide Notification No. 19/2016-Customs (N.T.), dated 5th February 2016. In case of imports from the developing countries listed under the said Notification No. 19/2016-Customs (N.T.), do not exceed 3% individually and 9% collectively, such imports will not attract quantitative restrictions in terms of Section 9A(1) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992.
- (iv) The Authorized Officer recommends imposition of Quantitative Restriction on imports of Low Ash Metallurgical Coke.
- (v) The imports would be permitted through the EDI ports only to facilitate electronic / real-time monitoring of the allocated quota. The quota would be monitored on quarterly basis. The total imports allowed in any quarter shall not exceed the total of that quarter and the next quarter. Any unutilized quota for a quarter shall be added to the next quarter. This would ensure that the exporters and the associated importers would be able to regulate the volumes smoothly. Thus, allocation of quota in such a manner would ensure that users, importers and exporters do not suffer any undue hardship. If necessary, further modalities for governing such Quantitative Restrictions may be notified, in accordance with relevant legal provisions.
- (vi) Accordingly, the Authorized Officer, in accordance with Section 9A(1) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, recommends imposition of quantitative restrictions on the imports of the following product for a period of one year from the date of the notification under the FTDR Act.

“Low Ash Metallurgical Coke, that is, Metallurgical Coke having ash content below 18% falling under the HS Code 2704 excluding coke fines / coke breeze and ultra-low phosphorous metallurgical coke with phosphorous content up to 0.030% with size of 30 mm with 5% size tolerance for use in ferroalloy manufacturing”

Figures in MT

Country	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
Australia	25,638	25,638	25,638	25,638	1,02,553

China PR	39,323	39,323	39,323	39,323	1,57,292
Colombia	1,24,886	1,24,886	1,24,886	1,24,886	4,99,542
Indonesia	33,182	33,182	33,182	33,182	1,32,729
Japan	1,04,990	1,04,990	1,04,990	1,04,990	4,19,960
Poland	2,53,168	2,53,168	2,53,168	2,53,168	10,12,672
Qatar	810	810	810	810	3,239
Russia	44,591	44,591	44,591	44,591	1,78,365
Singapore	23,239	23,239	23,239	23,239	92,955
Switzerland	40,887	40,887	40,887	40,887	1,63,549
UK	38	38	38	38	152
Others	22,831	22,831	22,831	22,831	91,325
Total	7,13,583	7,13,583	7,13,583	7,13,583	28,54,334

List of developing countries.

1. Afghanistan
2. Albania
3. Algeria
4. Angola
5. Armenia
6. Azerbaijan
7. Bangladesh
8. Belarus
9. Belize
10. Benin
11. Bhutan
12. Bolivia (Plurinational State of)
13. Bosnia and Herzegovina
14. Botswana
15. Brazil
16. Bulgaria
17. Burkina Faso
18. Burundi
19. Cabo Verde
20. Cambodia
21. Cameroon
22. Central African Republic
23. Chad
24. Comoros
25. Congo
26. Costa Rica
27. Côte D'Ivoire

28. Cuba
29. Democratic Peoples Republic of Korea
30. Democratic Republic of the Congo
31. Djibouti
32. Dominica
33. Dominican Republic
34. Ecuador
35. Egypt
36. El Salvador
37. Eritrea
38. Ethiopia
39. Fiji
40. Gabon
41. Gambia
42. Georgia
43. Ghana
44. Grenada
45. Guatemala
46. Guinea
47. Guinea Bissau
48. Guyana
49. Haiti
50. Honduras
51. Iran (Islamic Republic of)
52. Iraq
53. Jamaica
54. Jordan
55. Kazakhstan
56. Kenya
57. Kiribati
58. Kyrgyzstan
59. Lao Peoples Democratic Republic
60. Lebanon
61. Lesotho
62. Liberia
63. Libya
64. Madagascar
65. Malawi
66. Malaysia
67. Maldives
68. Mali

-
69. Marshall Islands
 70. Mauritania
 71. Mauritius
 72. Mexico
 73. Micronesia (Federal State of)
 74. Mongolia
 75. Montenegro
 76. Morocco
 77. Mozambique
 78. Myanmar
 79. Namibia
 80. Nepal
 81. Nicaragua
 82. Niger
 83. Nigeria
 84. Pakistan
 85. Palau
 86. Palestine
 87. Panama
 88. Papua New Guinea
 89. Paraguay
 90. Peru
 91. Philippines
 92. Republic of Moldova
 93. Romania
 94. Rwanda
 95. Saint Lucia
 96. Saint Vincent and the Grenadines
 97. Samoa
 98. Sao Tome and Principe
 99. Senegal
 100. Serbia
 101. Sierra Leone
 102. Solomon Islands
 103. Somalia
 104. South Africa
 105. South Sudan
 106. Sri Lanka

107. Sudan
108. Suriname
109. Swaziland
110. Syrian Arab Republic
111. Tajikistan
112. Thailand
113. The former Yugoslav Republic of Macedonia
114. Timor-Leste
115. Togo
116. Tonga
117. Tunisia
118. Turkey
119. Turkmenistan
120. Tuvalu
121. UAE
122. Uganda
123. Ukraine
124. United Republic of Tanzania
125. Uzbekistan
126. Vanuatu
127. Viet Nam
128. Yemen
129. Zambia
130. Zimbabwe

ANANT SWARUP, Authorized Officer